

*In Pursuit of Truth*

पाक्षिक

चर्चा: 21 | अंक: 07  
 01 से 15 जनवरी 2023  
 पृष्ठ: 48  
 मूल्य: 25 रु.

# आक्षय



## 2023 का आगाज नया साल **चुनौतियाँ अपार**

नववर्ष में आर्थिक मोर्चे के शिखर  
 पर भी होगा नया भारत

2023 में भारत अपने हिसाब से तय  
 करेगा कूटनीतिक दिशा



हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं  
इसलिए  
कौयला निकालते हैं



सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अनुषंगी कम्पनी

(भारत सरकार का एक उपक्रम)



CCLRanchi



CentralCoalfieldsLtd



centralcoalfieldsltd



Central Coalfields Limited



cclranchi

## ● इस अंक में

### वर्ल्डभगाथा

#### 9 | विकसित भारत का बनेगा रोडमैप

आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही केंद्री सरकार विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने जा रही है। इस रोडमैप को तैयार करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों की एक कॉन्फ्रेंस नए साल में आयोजित किया जाएगा।

### राजपथ

#### 10-11 | औपचारिकता बनकर रह...

विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को धेरने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का दाव खेला था, वह उसे उल्टा पड़ गया है।

अविश्वास प्रस्ताव भाजपा...

### लालफीताशाही

#### 18 | भ्रष्टों पर कौन मेहरबान ?

मप्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 1500 से अधिक शिकायतों में प्राथमिकी का...

### बिजली

#### 20 | गैर जरूरी करार का भार

मप्र के बिजली उपभोक्ता बिजली कंपनी के गलत निर्णय का बोझ उठाने को मजबूर हैं। जरूरत से ज्यादा बिजली के करार करने की वजह से हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले तीन साल में अकेले बिजली कंपनी ने 1773 करोड़ रुपए का भुगतान उन पावर...

**आकरण कथा 24, 25, 26, 27, 28**



### राजनीति

#### 30-31 | भाजपा के सामने...

2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा और एमसीडी में हार के बाद 2023 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के सामने कड़ी चुनौती रहने वाली है। 2023 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं।

### महाराष्ट्र

#### 35 | रश्मि ठाकरे मोर्चे पर...

महाराष्ट्र की राजनीति में शह-मात का खेल तेज होने लगा है। ये बीएमसी चुनावों की नजदीक आ रही तारीख की वजह से भी हो सकता है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा विपक्ष के निशाने पर हैं। ये सिलसिला तो शिवसेना में बगावत और...

### विहार

#### 38 | हंगामा क्यों बरपा है... ?

एक ओर जहां आए दिन संसद या विधानसभाओं में हंगामे की खबरें आती रहती हैं, वहाँ विहार विधानसभा में एक ऐसी बात पर हंगामे की खबर आई जो किसी मुद्रदे से नहीं बल्कि भाषाई संस्कार से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश...



### 6 - 7 अंदर की बात

- 40 पड़ोस
- 41 विदेश
- 43 कहानी
- 44 खेल
- 45 फिल्म
- 46 त्यंग

# कुछ हिररा सुधरा, बहुत सारा बाकी...

कि

स्त्री शायर ने लिखा है...

को दूटी स्तंडक मेरे गांव की अकस्मा लोया करती है  
दृश्य वर्ष बीत जाने पर स्पलों को सजोया करती है

ऐसा ही कुछ हाल देश के हृदय प्रदेश मप्र की राजधानी की स्तंडकों का हाल कैसा है, यह बकौल मुज्जमंत्री शिवराज सिंह चौहान...मैं कल अचानक भोपाल की स्तंडकों पर निकला। हमीदिया रोड से शाहजहांबाद होते हुए गुजरा। मुझे कल्पना नहीं थी कि स्तंडकों की हालत इतनी ज्यादा घ्राव होगी। ये रोड किसके पास हैं। पीडल्यूडी और आप लोग यह बताएं कि स्तंडकों की जब राजधानी में इतनी दुर्गति है, तो बाकी जगह क्या हालत होगी। अखबार गड़ों की छबरों से भरे पड़े हैं। क्या मैं रोज गड़ों की छबरें ही पढ़ता रहूँ ऐसा थोड़ी चलेगा। हम अकर्मण्य क्यों हैं, समय पर काम शुरू क्यों नहीं करते। कुछ दिक्कत है तो मुझसे कहो। यह मुझे ठीक नहीं लगा। 15 दिन बाद उन्हीं स्तंडकों पर फिर निकलूंगा। ये तल्ज शब्द थे मुज्जमंत्री शिवराज सिंह के, दिन था 26 अक्टूबर का। राजधानी समेत प्रदेशभर की स्तंडकों की छबर हालत को लेकर मुज्जमंत्री ने अधिकारियों की कलास ली थी। इसके बाद अफस्र हरकत में आए। ताबड़तोड़ जर्जर स्तंडकों का निरीक्षण होने लगा। भोपाल में अगले ही पीडल्यूडी और नगर निगम के अफस्र एक जाजन पर बैठे और मीटिंग में मंथन किया। दावा किया गया कि अगले ही दिन स्तंडकों की तस्वीर बदल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुज्जमंत्री के निर्देश के बाद भी अभी तक राजधानी की स्तंडकों की स्थिति बदल से बदल है। जिन स्तंडकों से ढोकर वीवीआईपी मंत्रालय और अपने आवास जाते हैं, वे स्तंडकें निश्चित रूप से चकाचक हैं। लेकिन शहर की अन्य स्तंडकों की स्थिति अभी भी जब की तस्वीर है। शहर में करीब 5 हजार किलोमीटर स्तंडकों का जाल बिछा दुआ है। नगर निगम की सबसे ज्यादा 3800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी स्तंडकें हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग के पास हमीदिया और कोलार रोड समेत 26 स्तंडकें हैं, जिनकी लंबाई 531 किलोमीटर। इस साल बांद हो चुके स्तीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) की भी 132 किमी स्तंडकों की देवष्ट्रेच्चर लोक निर्माण विभाग ही कर रहा है। इस बाद मानसून की बारिश के चलते 50 प्रतिशत स्तंडकें उच्छ्रेत गई हैं। लेकिन आज तक इन स्तंडकों को सुधारा नहीं गया है। शहर की मुज्जय स्तंडकों पर गड़े तो हैं ही इन पर बाहनों की रेलमपेल से धूल का गुबार भी उठ रहा है। जिससे लोगों का स्वास्थ्य घ्राव हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब प्रदेश चुनाव के मुहाले पर आ गया है। इसके बाद भी स्तंडकों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब राजधानी की स्तंडकों का यह हाल है तो सहज अंदर्जा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की स्तंडकों का क्या हाल होगा। हालांकि स्वकार ने विधायकों से स्तंडकों के निर्माण का प्रस्ताव मंगाया है। माना जा रहा है कि चुनावी साल में स्तंडकों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल राजधानी के लोग ही जर्जर स्तंडकों के शिकाय हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने के पहले स्वकार विधायकों द्वारा स्तंडकों के लिए दिए गए प्रस्तावों पर घोर्जाना घोलने जा रही है। उद्धृत स्तंडकों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपोप लगाया है कि जितनी भी स्तंडकें मंजूर हो रही हैं वे भजपा विधायकों के क्षेत्रों में हैं। जबकि कई भजपा विधायकों ने स्तंडकें नहीं होने पर अपनी ही स्वकार को घोरा है। प्रदेश के अधिकांश विधायकों की चिंता अपने क्षेत्र में सालों से पेंडिंग पड़ी स्तंडकों को लेकर है।

- श्रीनेह आगाम

# आक्षस

वर्ष 21, 3ंक 7, पृष्ठ-48, 1 से 15 जनवरी, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाम

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नंबर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,  
एफ-03, 04, पथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल - 462011 (म.प्र.)

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेस्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MPBPL/642/2021-23

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

## ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला, मार्केंगडे तिवारी, जयपुर:- आर.के. बिनानी, लखनऊ:- मधु आलोक निगम।

## प्रदेश संचालनाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (गंगावारीदा) ज्योत्सना अनूप यादव

089823 27267, (रत्नाम) सुभाष सोयानी

075666 71111, (विदिशा) मंहित बंसल

## क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईर्षे 294 माया इंकलेव मायापुरी  
फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शातिपथ, श्याम नार (राजस्थान)

मोदीपुर : 09829 010331

रायपुर : एपआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नार,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरु भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,

भिलाई, मोदीपुर 094241 08015

इंदौर : नवीन रुचेंगी, रुचेंगी कॉलोनी, इंदौर,

फोन : 9827227000

देवास : जय रिहं, देवास

फोन : -700026104, 9907353976

सावारिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाम सारा आगाम प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रधम तल,

एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित



## मन्त्रियों पर नज़र

2018 से स्वरूप लेते हुए इस बार सत्ता और भाजपा संगठन पूरी तरह स्वयंचत है। इसलिए इस बार हर गतिविधि पर नज़र रखनी जा रही है। मंत्री अपने प्रभाव वाले जिनमें फैसले के दौरान क्या-क्या कहेंगे, उसकी पूरी विपरीत संगठन तैयार करेगा। अब पार्टी मन्त्रियों के दौरान की पूरी निगरानी करेगी।

● छेंट कवच, शुजगढ़ (म.प्र.)



## लोकसभा चुनाव की तैयारी

हाल ही में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से सफ हो चला है कि अभी भी कांग्रेस जिंदा है। लेकिन कांग्रेस कब तक विपक्ष में बदली रहेगी, यह कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अश्विंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ओवरटक करने में लगी हुई है। गुजरात चुनावों में इसकी झलक देखने को मिली भी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई दूसरा लोकप्रिय चेहरा नहीं है और यह भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हर कहीं मोदी को प्रचारक बनाकर पेश किया जाता रहा है। कहीं कांग्रेस ने भी अभी दार नहीं मारी है, भावत जोड़ो यात्रा इसका उदाहरण है।

● पत्न घोषी, शाजापुर (म.प्र.)

## मतदाता को जागने की ज़िक्र

यह सही है कि चुनाव लोकतंत्र के लिए एक उत्सव की तरह होते हैं, लेकिन जब कोई उत्सव बार-बार मनाया जाने लगे तो वह एक बोझ की तरह लगने लगता है। जब चुनाव आते हैं तो शुजनीतिक दलों के साथ शास्त्र-प्रशास्त्र की भी प्रथमिकता बदल जाती है। जिन शुजों में सत्ता बदलने के आसान होते हैं, वहाँ तो प्रशास्त्र पंगु स्था पड़ जाता है। शिश्ता मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के प्रति उदासीनता है या फिर लोग निश्चिंत हैं? आने वाले चुनावों में मतदाताओं को अधिक स्तरीयता में आकर अपने हित में फैसले लेने होंगे।

● अफताब कुरैशी, शयब्देन (म.प्र.)

## राहुल की यात्रा

कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गंधी भावत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा को निश्चित रूप से सफलता मिल रही है लेकिन इस यात्रा से जो शुजनीतिक संदेश और एजेंटों सेट किया जाना चाहिए उस दृष्टि से यात्रा को ज्ञात्वा सफलता नहीं मिल पा रही है।

● शुजेश वर्मा, इंदौर (म.प्र.)



## भ्रष्टों पर लगे लगाम

मप्र में प्रशास्त्रीय अधिकारी-कर्मचारी आए दिन घूस लेते पड़े जा रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। मप्र की शिवराज सरकार को ऐसा कानून बनाने की ज़िक्र है, जिससे अफसरों के दिमाग में भ्रष्टाचार करने का ज्यात भी न पनप सके। कई विभागों में अभी भी अबूले आम शिवराज का झेल झेला जा रहा है। जिससे आम जनता को प्रश्नानी का सामना करना पड़ रहा है।

● अश्वी दुबे, श्रीहोर (म.प्र.)

## पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें।

## अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,  
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



## आसान हुई पायलट की उड़ान!

राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा हंगामा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी सचिन पायलट को न देने के चक्रमें पार्टी आलाकमान से भी सांकेतिक तौर पर एक बार बगावत कर चुके हैं। इस कुर्सी के चक्रमें ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष तक के पद में रुचि नहीं दिखाई थी। इन सबके बावजूद अशोक गहलोत के एक बयान ने यह संकेत दिया है कि वे राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति की क्लासेज लेंगे। गहलोत के इस बयान के बाद यह कथास लगाए जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत ने हार मान ली है? दरअसल, 'भारत जोड़ो यात्रा' इस समय राजस्थान में है। इस दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट कई बार राहुल गांधी के साथ एक ही फ्रेम में दिखे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के दो सीनियर नेताओं के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। दो बड़े नेताओं के मध्य सुलह के प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। राजस्थान सरकार के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, 'राजनीति से संन्यास लेने के बाद वह टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, जहां वे राजनीति की क्लास देना शुरू करेंगे।'

## राजभर के बदले सुर

हाल ही में हुए उप उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिल गई है, शिवपाल यादव की सपा में वापसी हो चुकी है। वर्हां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर लगातार पार्टी के बदलते रहते हैं। जहां उन्होंने विधानसभा चुनावों के बाद सपा का साथ छोड़ दिया था। अब निकाय चुनावों से पहले और मैनपुरी में आए उपचुनावों के नतीजे के बाद ओमप्रकाश राजभर के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं। दरअसल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान में कहा है कि अगर शिवपाल यादव बीच में आए और बात करें तो मैं अखिलेश यादव से बात करने के लिए तैयार हूँ। बात करने में कोई बुराई नहीं है। नेताओं की बात आपस में होती रहती है। ऐसे में अगर शिवपाल यादव मध्यस्थिता करते हैं तो मैं अखिलेश यादव से आगे की बात करने के लिए तैयार हूँ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजभर ने एक बार फिर से सपा को मैसेज दे दिया है कि शिवपाल यादव गठबंधन के लिए पहल करें।



## मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होंगे दिग्गज

भाजपा के संगठन में बदलाव होने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। हालांकि अगर जेपी नड़ा की जगह नया अध्यक्ष नहीं बनता है और उनको ही लोकसभा चुनाव तक कार्यकाल का विस्तार मिलता है या दूसरा कार्यकाल मिलता है तब संगठन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके बावजूद चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी सरकार में फेरबदल कर सकते हैं। उन्होंने दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहली फेरबदल करीब ढाई साल के बाद की थी। अब एक साल बाद फिर फेरबदल की चर्चा है तो उसका कारण गुजरात चुनाव का प्रयोग है। दरअसल, गुजरात में चुनाव से एक-सवा साल पहले मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रियों को बदल दिया गया था। सारे पुराने और बड़े नेता सरकार से हटा दिए गए थे और बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया गया था। उसी तरह का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार में भी कर सकते हैं। कथास लगाए जा रहे हैं कि मोदी की पहली सरकार से यानी मई 2014 से जो लोग मंत्री पद पर हैं उनमें से ज्यादातर को हटाया जा सकता है। सात या आठ साल से जितने लोग मंत्री हैं वे आशंकित हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर को बदले जाने की चर्चा है। उनकी जगह नए चेहरे लाए जा सकते हैं। हर राज्य में ऐसे नए चेहरों की पहचान हुई है। काफी नए और युवा लोगों को मंत्रिमंडल में लिए जाने की चर्चा है।

## कुनबे की कलह

कर्नाटक में भाजपा का अंदरूनी घमासान ठंडा पड़ने के बजाय और तेज हो गया है। दो पूर्व मंत्रियों के एस ईश्वरपा और रमेश जरकीहोली ने 19 दिसंबर से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बहिष्कार बाकायदा ऐलान करके किया। मंत्रिमंडल में अपनी वापसी नहीं होने से दोनों नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोर्माई सरकार बेशक चला रहे हैं पर नेताओं पर उनका वैसा काबू नहीं दिखता जैसा भाजपा शासित गुजरात और उप जैसे राज्यों में दिखता है। बसवराज बोर्माई मूल रूप से भाजपाई हैं भी कहां। असली भाजपाई तो पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरपा माने जाते हैं। अगले साल फरवरी में 80 बरस के हो जाएं। पार्टी ने दबाव बनाकर चार बार के मुख्यमंत्री येदियुरपा को मुख्यमंत्री पद से भले हटा दिया हो पर वे खुद को हाशिए पर मानने को कर्तई तैयार नहीं। उनकी चिंता वंशवाद का विरोध करने वाली पार्टी में अपने बेटों की सियासी पारी को धार देने की है। पिछले दिनों बयान भी दिया था कि वे न तो किसी की दवा के मोहताज हैं और न कोई उन्हें हाशिए पर पहुंचा सकता है।

## आज का अर्जुन

मैं अर्जुन हूँ... यह तो सभी जानते हैं कि केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री का नाम अर्जुन मुंडा है। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान बनाने वाले मुंडा राजनीति में अपने सहज और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने नाम को इस तरह लिया और यह महाभारत के संदर्भ से जुड़ा तो सदन में हँसी का माहौल बन गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालय के संदर्भ में पूरक सवाल पूछा था। मनोज झा का कहना था कि एकलब्ध शब्द प्रताड़ना और बहिष्कार का प्रतीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विद्यालय का नाम बिरसा, फूले या पेरियार के नाम पर होता तो बेहतर होता। इस पर अर्जुन मुंडा ने कहा-जो हमारी ऐतिहासिक पृथग्भूमि है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसके अनुसार ही एकलब्ध आदर्श आवासीय विद्यालय का नामकरण किया गया है।

## अर्ज सुनो हमारी

प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में इन दिनों दो नेताओं की जुगलबंदी काफी चर्चा में है। एक माननीय सरकार में मंत्री हैं और दूसरे उनके हम प्याला दोस्त। जिन मंत्रीजी की यहां बात हो रही है, वे ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले से आते हैं। मंत्रीजी के पास प्रदेश सरकार के बड़े विभागों में से एक विभाग है। बताया जाता है कि मंत्रीजी के जिस दोस्त की बात हो रही है, वे विध्य क्षेत्र के एक जिले के नेता हैं। सूत्रों का कहना है कि जबसे मंत्रीजी ने पाला बदला है, तब से उनकी और विध्य वाले नेता की दोस्ती इस कदर गहरा गई है कि वह हम निवाला और हम प्याला वाली हो गई है। यानी दोनों खाते और पीते एकसाथ हैं। बताया जाता है कि मंत्रीजी की कमाई को देखते हुए उनके दोस्त के मुंह में भी लार टपकने लगी है और वे आए दिन मंत्रीजी पर काम का दबाव डालते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नेताजी के मनमाने काम कर करके मंत्रीजी भी आजीज आ चुके हैं। बताया जाता है कि कई बार मंत्रीजी ने अपने दोस्त के मनमाने कामों को करने से आनाकानी भी की है। एक बार ऐसे ही एक बड़े काम को करने से मंत्रीजी ने आना किया कि उनके दोस्त नेताजी ने उनसे साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि हमारी अर्ज सुन लो वरना किसी दिन तुम्हारी सारी पौल खोलकर रख देंगे। बताया जाता है कि अपने दोस्त की धमकी वाली अर्ज सुनकर मंत्रीजी के भी होश उड़े हुए हैं।

## हर जगह मजा-मजा

नए साल में देश के हृदय प्रदेश में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। खेलो इंडिया के नाम से होने वाले इस इवेंट को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार अभी से जुट गई है। इस इवेंट को कराने के लिए बड़े स्तर पर निर्माण कार्य भी किए जाने हैं। इसको देखते हुए देश के कई बिल्डरों के मुंह में पानी आने लगा है। सब अपनी-अपनी पहुंच के माध्यम से काम चालू कर दिया। इसमें होने वाले इवेंट का कार्य करने वाली कंपनियां अपनी-अपनी कोशिशों में जुट गई हैं। लेकिन सबकी राह में बड़ी बाधा संघ के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार की एक कंपनी बनी हुई है। बताया जाता है कि इस कंपनी ने पूर्व में भी कई इवेंट जुगाड़ से ही आयोजित किए हैं। इसलिए इस बार भी इस कंपनी को टेंडर तो मिल गया है, परंतु टेंडर में कई शर्तें ऐसी हैं, जिन्हें विभाग मानने से दाएं-बाएं हो रहा है। उसी में संघ के नेताजी ने अपना रिश्तेदार बताकर सरकार पर दबाव बना दिया है। अब देखते हैं कि सारी मर्यादाओं को लांघकर विभाग इस कंपनी को कार्य देता है या नहीं।



## गजब का मैनेजमेंट

निमाड़ क्षेत्र के एक जिले के कलेक्टर साहब इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा की वजह यह है कि साहब जबसे जिले के कलेक्टर बने हैं, तब से उनकी सक्रियता, सूझबूझ ने सरकार के खजाने का राजस्व बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि 2012 बैच के ये साहब प्रमोटी आईएस अधिकारी हैं। जिले की कमान संभालते ही साहब ने सबसे पहले यह सूची तैयार की कि कहां से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। बताया जाता है कि उसके बाद साहब के मार्गदर्शन में लगातार राजस्व कमाया जा रहा है। सबसे अधिक राजस्व नर्मदा नदी में वैध और अवैध रेत खनन से हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में रेत खनन के लिए 5 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने पेनाल्टी के रूप में 2.5 करोड़ रुपए चार माह में ही जमा करा लिए। यही नहीं जिले में मुर्म सहित अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग आदि पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने करीब 9 करोड़ रुपए वसूले हैं। जिले में एकत्रित हो रहे राजस्व से सरकार भी खुश है। जिले से लेकर राजधानी की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में कलेक्टर साहब के मैनेजमेंट को खूब सराहा जा रहा है। यही नहीं साहब जबसे जिले में पदस्थ हुए हैं, तबसे यहां के माफिया भी निष्क्रिय हो गए हैं।

## माई की कृपा बनी रहे...

प्रदेश के ब्लूरोक्रेट्स अच्छी पदस्थापना पाने के लिए कई तरह के तिकड़म करते रहते हैं। नए साल के शुरू होने से पहले ऐसा ही एक तिकड़म बुंदेलखण्ड क्षेत्र के एक जिले के कलेक्टर साहब ने किया है। दरअसल, साहब प्रमोटी आईएस अधिकारी हैं। साहब को अपनी कलेक्टरी बचाए रखने और किसी बड़े जिले में पदस्थापना की चिंता सता रही है। इसके लिए साहब ने अपने जिले के ख्यातनाम धार्मिक स्थल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन्होंने अपने कुछ सिपहसालार बाबुओं को काम पर लगा दिया है। उन्होंने उन्हें एक झोला देकर राजधानी भेजा है। जात तौर पर तो इस झोले में प्रसाद, और कैलेंडर है, लेकिन अज्ञात तौर पर बहुत कुछ होने की बात कही जा रही है। साहब के सिपहसालार राजधानी की प्रशासनिक और राजनीतिक वीथिका में उस झोले को बांटने के काम में जुट गए हैं। साहब को उम्मीद है कि उनके ऐसा कराने से माई की कृपा उन पर बनी रहेगी। ऐसे बता दें कि प्रदेश के एक कदावर मंत्री की कृपा से उन्हें यह कलेक्टरी मिली है। अब देखना यह है साहब की कलेक्टरी रहती है या जाती है।

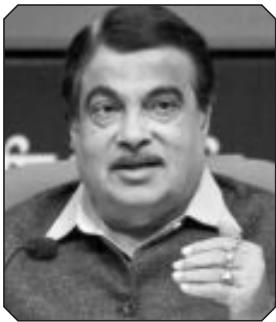
## दो अफसरों में ठनी

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो आईपीएस अफसरों यानी आईजी और डीआईजी के बीच बढ़ रही दरार चर्चा का विषय बनी हुई है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि इस महिला के कारण दोनों अफसरों में ठन गई है। पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि महिला कोई ऐसी-वैसी नहीं बल्कि वह भी एक पुलिस अधिकारी है। बताया जाता है कि पहले यह महिला डीआईजी साहब की दोस्त थीं। साहब और इनकी नजदीकियां काफी चर्चा में भी रही हैं। लेकिन अब उक्त महिला की पदस्थापना आईजी के क्षेत्र में हो गई है। इसलिए इन दिनों आईजी और उक्त महिला अधिकारी की नजदीकियां बढ़ गई हैं। बताया जाता है कि डीआईजी साहब जब भी उक्त महिला अधिकारी को आईजी के साथ देखते हैं तो उनका पुराना प्यार जाग उठता है और वे जल-भून जाते हैं। कई अवसरों पर उनके हाव-भाव चेहरे पर दिख जाते हैं। लेकिन वे करों भी तो क्या करें। अब देखना यह है कि दोनों की यह लड़ाई किस अंजाम पर पहुंचती है। वैसे यहां बता दें दोनों साहब शौकीन मिजाज के हैं और कोई भी अवसर हाथ से निकलने नहीं देते।



मैं भाजपा की बफादार सिपाही हूं। मैं आप लोगों के पास वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आपको भाजपा को वोट देना है या नहीं, यह आप लोग अपनी स्थिति देखकर तय करना। प्रदेश में लोधी समाज बड़ा वोट बैंक है, इसलिए मेरा फोटो दिखाकर वोट मांगा जाता है।

● उमा भारती



साल 2024 के अंत तक भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का साइज दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। इससे भारत इस सेक्टर में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो जाएगा। मंत्रालय अगले साल 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए सरकार से और बाकी पूंजी कैपिटल मार्केट से जुटाई जाएगी।

● नितिन गडकरी



जीवा एकदम अपने पिता की तरह है। जैसा पिता, वैसी बेटी। उसे जबसे फुटबाल के लीजेंड लियोनल मेसी के हस्ताक्षर वाली जर्सी मिली है, वह उसे हमेशा पहनने की कोशिश करती रहती है। उसे खेल का अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन खेल के प्रति उसका जुनून देखने लायक है। आगे वह जो चाहेगी, हम लोग वही करवाएंगे।

● साक्षी धोनी



यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नाटो विलेन बना हुआ है। उसके सहयोग से यूक्रेन ने युद्ध को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे खिलाफ हो रही हर साजिश का हम जवाब देंगे। चाहे हमारे सामने पूरी नाटो की सेना ही क्यों न आ जाए।

● व्लादिमिर पुतिन



जब हमारे अंदर कुछ देखने और दिखाने का होता तभी लोग हमें फॉलो करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब पैपराजी किसी महिला सेलिब्रिटी का फोटो लेने की कोशिश करते हैं तो वे उससे दूर भागने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूं। हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारी फोटो भले ही अपने प्रोफेशन के लिए लेते हैं, लेकिन उससे हमारा ही प्रचार-प्रसार होता है। अगर हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो फिर पैपराजी से डरने की क्या बात। मेरे आगे-पीछे तो रोज पैपराजी घूमते हैं और मैं उन्हें उनकी डिमांड के अनुसार पोज देकर फोटो खिंचवाती हूं।

● मलाइका अरोड़ा

## वाक्युद्ध



पिछले कुछ सालों के दौरान जांच एजेंसियों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस कारण अकारण ही लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अनिल देशमुख और संजय राउत की गिरफतारी है। हमारे सहकर्मियों ने बहुत कुछ झेला है।

● शरद पवार



कोई भी जांच एजेंसी बेवजह किसी को क्यों परेशान करेगी। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए ब्रह्माचार किया है, उन पर ही एजेंसियों ने हाथ डाला है। एजेंसियों को बदनाम करने की जगह लोगों को अपने नेताओं की करतूतों पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी किसी बेकसूर को कोई भी जांच एजेंसी परेशान नहीं करती है।

● देवेंद्र फडणवीस



**आ** तमनिर्भर भारत अभियान के साथ ही केंद्री सरकार विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने जा रही है। इस रोडमैप को तैयार करने के

लिए राज्यों के मुख्य सचिवों की एक कॉन्फ्रेंस नए साल में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में कुछ अनुभवी अफसर भी शामिल होंगे।

मप्र से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के साथ ही आईएएस संजय दुबे, नीरज मंडलोई और संजय शुक्ला भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 5, 6 और 7 फरवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अफसरों का ग्रुप डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन से विकसित भारत का रोडमैप बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ये कॉन्फ्रेंस जहां आयोजित होगी, वहाँ सभी भी 3 दिनों तक रहना होगा। इस दौरान खाना-पीना, योग, ध्यान सभी उसी जगह पर होगा। यही नहीं



## विकसित भारत का बनेगा रोडमैप



कौन अफसर किसके साथ ठहरेगा, यह भी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पता चलेगा।

### फरवरी में होगा अफसरों का रवेला

कोरोना संक्रमण के कारण पिछले करीब 3 साल से आईएएस अफसरों की खेलकूद प्रतियोगिता नहीं हो पाई है। गैरतरलब है कि राजधानी में आयोजित होने वाले इस आयोजन में प्रदेशभर के आईएएस अधिकारी सपरिवार शामिल होते हैं। इस बार इस आयोजन को फरवरी में कराए जाने की तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि इसमें शामिल होने के लिए अफसर तैयारी में जुट गए हैं। अगर इस बार कोरोना संक्रमण इसी तरह नियंत्रित रहता है तो इस बार तीन साल के अंतराल के बाद राजधानी में प्रदेशभर के आईएएस अफसरों का जमावड़ा देखने को मिलेगा।

## मार्च तक दुरुस्त होंगी 15 हजार किमी सड़कें

नए साल में प्रदेश की सड़कें चकाचक होंगी। प्रदेश के विधायकों से मिले प्रस्ताव के बाद सरकार ने मानसून में खराब हुई सड़कों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण का प्लान तैयार किया है। गैरतरलब है कि भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास को मुख्य मुददा बनाएंगी। इसलिए सरकार का फोकस विकास योजनाओं पर है। इसी के तहत सरकार प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 15 हजार किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के नाम पर तीन हजार करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। इस राशि से लगभग दो हजार सड़कें बनाई जाएंगी। यही नहीं इसमें राजधानी की परफॉर्मेंस गारंटी में 83 किमी सड़कें चिह्नित की गई हैं। इन सड़कों के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। उधर, सीपीए के समापन के बाद राजधानी के 24 पार्कों के संधारण का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इन पार्कों को नगर निगम को लेना है। लेकिन अभी तक मामला केवल फाइलों में ही चल रहा है। दरअसल, इन पार्कों के लिए ठेकेदारों को 41 करोड़ रुपए देना है। वहाँ हर साल इनके मैट्नेंस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, इसलिए नगर निगम भी इन पार्कों को लेने में कठता रहा है। दरअसल, नगर निगम की भी स्थिति अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नगर निगम की कोशिश है कि पार्कों के संधारण का काम उसे न मिले।

## कमिशनर एवं क्लेक्टर कॉन्फ्रेंस 16 एवं 17 जनवरी को

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 16 एवं 17 जनवरी 2023 को कमिशनर, क्लेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से वन-टू-वन करेंगे। मप्र सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने बताया कि 16 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा और प्रजेटेशन होगा। साथ ही जिलों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रस्तुतीकरण और विभागों की समीक्षा की जाएगी। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। पैसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन राजस्व विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के क्रियान्वयन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य योनिकीय विभाग, सीएम राइज स्कूलों के संचालन का क्रियान्वयन, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, शिशु, नवजात शिशु और मातृ मृत्युदर को कम करने के लिए किए जा रहे कार्य, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का क्रियान्वयन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न उपकरण प्रदाय संबंधी योजना में सेच्युरेशन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, संबल 2 योजना के क्रियान्वयन, श्रम विभाग और चिन्हित जिलों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रस्तुतीकरण और विभागों की समीक्षा की जाएगी।

## रवेला हो गया...

सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो मीडिया सलाहकार नियुक्त किए हैं। इनमें से एक हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आईसीपी केसरी और दूसरे हैं अजय कुमार पांडेय। आईसीपी केसरी को नई दिल्ली का तो अजय कुमार पांडेय को मुंबई का काम सौंपा गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें बड़ा खेला हुआ है। दरअसल, बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आईसीपी केसरी को किसी संवैधानिक पद पर बिठाना चाह रहे थे, लेकिन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने इसमें ऐसी चाल चली कि उन्होंने एक तीर से दो शिकायत किए। एक तो उन्होंने आईसीपी केसरी को दिल्ली में ही पद देकर इंगेज कर दिया और अपने लिए एक जगह सुरक्षित कर ली। बताया जाता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद बैंस की नजर किसी बड़े संवैधानिक पद पर गड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्रीजी के चहेते अफसर को भी दरकिनार कर दिया है। साथ ही उन्होंने नीरज वशिष्ठ को भी सुरक्षित किया, जिससे उनकी मप्र में उद्योगपतियों के साथ पूछ-परख बनी रहे। इसी चाल को चलते हुए अजय कुमार पांडेय की नियुक्ति मीडिया एडवाइजर मुंबई तक ही सीमित कर दी है, ताकि यहाँ आने वाले उद्योगपतियों को नीरज वशिष्ठ ठीक तरीके से देख सकें।

● कुमार राजेन्द्र

मप्र में विधानसभा  
चुनाव होने वाले  
हैं। इसको देखते  
हुए कांग्रेस प्रदेश  
की सचारुद्धि  
भाजपा को धेरने  
के लिए  
विधानसभा के  
शीतकालीन सत्र  
में अविश्वास  
प्रस्ताव लाई थी।  
लेकिन अविश्वास  
प्रस्ताव मात्र  
औपचारिकता  
बनकर रह गया,  
क्योंकि न कांग्रेस  
ने इसमें रुचि  
दिखाई और न ही  
भाजपा ने। आलम  
यह रहा कि  
कांग्रेस प्रदेश  
अध्यक्ष कमलनाथ  
तो अविश्वास  
प्रस्ताव पर चर्चा के  
दौरान दो दिनों  
तक सदन में पहुंचे  
ही नहीं। उधर,  
भाजपा ने कांग्रेस  
के सवालों का  
जवाब देने की  
बजाय उसके 15  
माह के  
शासनकाल पर  
जमकर हमला  
बोला।



## औपचारिकता बनकर रह गया अविश्वास प्रस्ताव

**वि**धानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को धेरने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का दाव खेला था, वह उसे उल्टा पड़ गया है। अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ था, लेकिन सदन में कांग्रेस में ही अविश्वास दिखा। नेता आपस में बटे दिखे। वहाँ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 51 सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ के 15 माह की सरकार के ग्रष्णचार की पोल खोलकर रख दी।

मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दो दिन चला हंगामा बहुत शांति से थम गया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में लंबी और ऐतिहासिक चर्चा के बाद गिर गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार ढाई घंटे बोलकर कांग्रेस के आरोपों पर न केवल जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस सासनकाल में हुए घपले-घोटालों की पोल खोल डाली। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन दलालों का अड़दा बन गया था, यह अँन रिकॉर्ड कह रहा हूं। वहाँ बैठकर कौन-कौन पैसे गिनते थे। कितने पैसे बाद में इनकम टैक्स के छापे में बरामद हुए। एक्स सीएम का बीड़ियो वायरल हुआ। हमारी सरकार किसी की मेहरबानी पर

नहीं बनी। मप्र का विकास मेरे जीवन का संकल्प है, हम जिएंगे मप्र के लिए, मरेंगे तो मप्र के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सदन में इस बार जैसी आक्रामकता दिखी, वैसी शायद ही पहले कभी दिखी थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को धेरने का जो खेल

खेला था, वह खुद अपने बुने जाल में फंस गई है।

गौरतलब है कि विधानसभा में 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। प्रस्ताव पर कांग्रेस के 31, भाजपा के 8 विधायक और 8 मंत्रियों ने पक्ष रखा। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ 2011 के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा भी हुई, लेकिन चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस के बीच अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। लेकिन कांग्रेस जिस उद्देश्य के साथ इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, उसमें वह पूरी तरह फेल हो गई। यानी वह भाजपा को धेर नहीं पाई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सदन में बताया था कि कांग्रेस ने 300 पॉइंट्स जुटाए हैं और चर्चा के लिए 51

### कमलनाथ के लिए अविश्वास प्रस्ताव से जरूरी क्या था

अविश्वास प्रस्ताव पर 16 घंटे बहस हुई। 21 दिसंबर को दिनभर और रात एक बजे तक। उस दिन कमलनाथ भोपाल से करीब 120 किमी दूर सिरोंज में कांग्रेस की सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा- 'मैंने पहले से कहा था, सिरोंज आऊंगा। मैं वर्चन का पक्का हूं इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर आपके बीच सिरोंज आया हूं।' अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अविश्वास प्रस्ताव के आरोपों का जवाब दे रहे थे, तब भी कमलनाथ सदन में नहीं थे। न ही नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह थे। कमांडर ही मौजूद नहीं थे, इसलिए सरकार विपक्ष पर हावी हो गई। कांग्रेस की पूरी टीम बंटी हुई दिखाई पड़ रही थी। कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट भी प्रभावशाली नहीं दिखाई दिया। भाजपा ने माइंड गेम से इस मुकाबले को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम कांग्रेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि सरकार पर लगाए गए आरोप गंभीर नहीं थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से उठाया नहीं गया। मुख्यमंत्री ने कहा, आप कह रहे थे कि आर्थिक हालत खराब है। हमने कभी पैसों का रोना नहीं रोया। इस पर कांग्रेस विधायक राकेश मारवाड़ ने कागज दिखाते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने जवाब में लिखा है कि खजाना खाली है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा- हमने कर्ज लिया, लेकिन सीमा से ऊपर नहीं लिया।



बिंदुओं का चयन किया गया था। लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोनों ही उपस्थित नहीं रहे, जिसे भाजपा ने मुद्रा बनाया।

शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस बंटी-बंटी नजर आई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पहले दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गायब रहे और दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह अनुपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'कांग्रेस हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक-दूसरे पर ही अविश्वास है, कांग्रेस का आरोप रहता है कि सरकार हमने गिराई थी, बता दूं सरकार हमने नहीं गिराई थी, बल्कि यह सरकार अपने अहंकार के कारण गिरी थी। अपने नेता सिंधिया को कहा था सड़क पर उतर जाओ, फिर आपके साथी हमारे साथ आ गए और चुनाव लड़कर जीत कर आए। हमारे साथ आए सभी कांग्रेस विधायकों ने भारी मतों से जीत हासिल की। इसलिए यह सरकार हमने नहीं गिराई थी, यह सरकार तो अपने खुद के अहंकार की वजह से गिरी थी।' बता दें कि कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया था। विपक्षी दल कांग्रेस के लगातार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बिंदुओं पर अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री के ढाई घंटे के संबोधन के दौरान उन्होंने लगभग सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल के दौरान की गतिविधियों को लेकर विपक्ष को लगातार घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस 15 साल बाद सरकार में आई, तो जनता से किए अपने सभी वायदे पूरा करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रतिपक्ष से ही कहा कि वे सोचें कि उनकी सरकार आखिर गिर क्यों गई। आज सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैरमौजूदी को भी उन्होंने रेखांकित किया।

किसान कर्जामाफी पर मुख्यमंत्री ने कहा- राहुल गांधी ने अंगुलियों पर गिनकर कहा था कि

किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने कर्जामाफी का कचरा कर दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा- सचिन भाई इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं। अरुण यादव ने ट्रॉट कर इस सरकार के बारे में क्या लिखा था, याद है या नहीं? अगर ये सरकार ईमानदारी से कर्जा माफ करती तो 53 लाख के कर्जे माफ होते। आपने 7 हजार करोड़ कर्जा माफी का दिया है। इस पर तरुण भनोट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा- आपने पांच महान काम किए। इस पर विधायक लक्षण सिंह ने मुख्यमंत्री को टोकते हुए कहा कि अविश्वास के विषय पर जवाब दें। मुख्यमंत्री ने फिर कहा- कभी कलेक्टर-एसपी की पोस्टिंग में पहले पैसे नहीं लिए गए। लेकिन, कमलनाथ जी की सरकार में पैसे लेकर कई अधिकारी बदले गए। तीन-तीन कलेक्टर बदले। बात ये होती थी कि कौन कितने ज्यादा देने वाला है। मप्र के इतिहास में पदों की बंदरबांट की गई। अभी इसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर खरगोन की कसरावद सीट से विधायक सचिन यादव ने कहा कि इनके पास प्रमाण हैं क्या? मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा- मामला लोकायुक्त में चल रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा- हर बार ये कहा जाता है कि हमने सरकार गिराई। 11 दिसंबर को रात में कांग्रेस 110-112 सीटों पर आगे थी। रात में ये निश्चय करके सोया था कि सुबह इस्तीफा दे दूंगा। कई मित्रों का कहना था कि बहुमत तो उनका नहीं है। मैं सीएम हाउस में था। भृपेंद्र जी आए। मुझे जोर देकर कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन मैंने कहा कि मेरा जमीर अनुमति नहीं देता। कांग्रेस की संख्या ज्यादा है। मैं सीधे घर से निकला और मीडिया से कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं।

● सुनील सिंह

## सरकार पर ये लगाए आरोप

- पूरक पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी।
- अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा।
- नर्सिंग कालेजों में फर्जीवाड़ा, विकित्सा महाविद्यालयों में खरीदी के नाम पर अनियमितता।
- खरोजगार योजनाएं बेरोजगारों के साथ छलावा, बेरोजगारी दूर करने का कोई ठास समाधान नहीं।
- प्रदेश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आगजनी की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल।
- जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बढ़ीं, शराब बिक्री को बढ़ावा देने संबंधी निर्णयों से महिलाओं में आक्रोश।
- महाकाल महालोक के निर्माण में भ्रष्टाचार, राम बन गमन पथ का निर्माण न होना।
- ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा न मिलना।
- भिंड में कोटवार और भृत्य की फर्जी नियुक्ति दिखाकर लाखों रुपए का आहरण।
- कारम बांध के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता।
- राशन टुकानों से गरीबों को निम्न गुणवत्ता का चावल वितरित करना।
- प्रदेश में बिजली कटौती कर दूसरे राज्यों को बेचना, सौलर पंप योजना में राज्यांश कम करने से किसानों पर पड़ा भार।
- 280 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देकर उन्हें बचाने का प्रयास करना।
- अनुबंध नियुक्ति में विवाहित बेटी को नौकरी न देना, अविवाहित बेटियों और विधवाओं को पारिवारिक पेंशन का लाभ न देना।
- सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के मामलों की धीमी जांच, पुलिसकर्मियों को सासाहिक अवकाश न देना।
- प्रधानमंत्री आवास और सामूहिक विवाह योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला।
- स्कूल के बच्चों के गणवेश खरीदी में अनियमितता, आदिवासी हितों की अनदेखी।
- प्रोफेसर भर्ती में घोटाला, हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक की नियम विरुद्ध नियुक्ति।
- किसानों की ऋण माफी रोकना, खाद की कमी, राज्य पर ऋण का अत्यधिक बोझ, कानून व्यवस्था की बदतर रिष्टि, प्रदेश में अवैध उत्थनन व रेत माफिया का आतंक।

**म** प्र में एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आलम यह है कि प्रदेश में भ्रष्ट अफसर दमदार बने हुए हैं। ऐसे ही दो अफसर हैं जनपद पंचायत नटेरन के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएल कुरेले एवं पूर्व सहायक यंत्री एनपी मेहर। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ 15वें वित्त आयोग की राशि गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने की शिकायत है। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 मई को विदिशा जिले के कागांपुर भ्रमण के दौरान दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण एवं जांच करने के निर्देश दिए थे। लेकिन स्थानांतरण के अलावा इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संचालक, सह आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के निर्देश पर 8 जून को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा की अध्यक्षता में रूपेंद्र मरावी लेखाधिकारी, सुरेश वर्मा परियोजना अधिकारी, डॉ. ऋचा जैन परियोजना अधिकारी एवं अरके दुबे सहायक यंत्री जनपद पंचायत लटेरी की जांच समिति गठित की गई। इस समिति द्वारा जांच के बाद जो जांच प्रतिवेदन दिया गया, उसमें बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की राशि का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन के दौरान पाया गया कि मप्र शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र क्रमांक/पं.रा./सीएफसी/2020/11325 दिनांक 01.10.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत भी जनपद पंचायत नटेरन द्वारा तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं करने से राशि का उपयोग शासन द्वारा नियत समयावधि में नहीं किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना शासन निर्देशानुसार 60 एवं 40 के अनुपात में तैयार न की जाकर शासन नियमों के विपरीत 50 एवं 50 के अनुपात में तैयार की गई। उक्त तैयार की गई कार्ययोजना का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से नहीं कराया गया। राशि का उपयोग भी जनपद पंचायत नटेरन के द्वारा नहीं किया गया।

26 अप्रैल 2022 को जनपद पंचायत नटेरन की बैठक आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2020-21 (कुल 11 कार्य), 2021-22 (कुल 15 कार्य) एवं 2022-23 (कुल 13 कार्य) कुल योग 39 कार्यों की समेकित कार्ययोजना तैयार की गई। जिसमें जनपद पंचायत नटेरन के सदस्यों से 15वें वित्त योजनांतर्गत कार्यवाही विवरण अनुसार कुल 38 कार्य अंकित हैं। जिनमें अन्य किसी ग्राम पंचायत या अन्य जनप्रतिनिधि के लिखित प्रस्ताव सम्मिलित नहीं हैं। निर्माण कार्यों के लिखित में

# भ्रष्टों को किसका संरक्षण... ?



## ...तो फोर्स रिटायरमेंट दे देना चाहिए मेहर को

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 मई को एसएस कुरेले और सहायक यंत्री एनपी मेहर के खिलाफ गंभीर शिकायत मिलने के बाद अलीराजपुर स्थानांतरण कर दिया था, लेकिन दोनों अधिकारी वहां नहीं गए। कुरेले ने तो अपनी नई पदस्थापना करा ली है, लेकिन मेहर उस दिन के बाद से अवकाश पर चले गए। करीब 7 माह से वे बीमारी के नाम पर अवकाश पर हैं। इस संदर्भ में जब कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यात्रिकी सेवा अलीराजपुर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहली बार यह नाम सुना है। और न ही इस संदर्भ में मेरे पास कोई आदेश भेजा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन्हें फोर्स रिटायरमेंट देगी। दरअसल, भ्रष्टाचार में लिप होने के कारण मेहर ने अलीराजपुर जाना उचित नहीं समझा है और बीमारी का बहाना बनाकर अभी तक अवकाश पर है। यह एक तरह से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाकर कार्ययोजना शासन के पोर्टल पर प्रविष्ट की गई। जिसका जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त बिना ही 18 निर्माण कार्यों की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर राशि शासन नियमों के विपरीत निर्माण एजेंसियों को जारी करने की कार्यवाही की गई।

उक्त कार्ययोजना में ग्राम पंचायत सतपाठाहांट में पानी रोकने हेतु दिवाल, ग्राम पंचायत नटेरन में स्वच्छता के लिए गंदे पानी की निकासी हेतु खेराई नाले पर करटेनवाल, ग्राम पंचायत सेऊ में जिन बाबा चबूतरे के सामने सीसी रोड निर्माण कार्य शासन नियमों के विपरीत स्वीकृत किए जाकर राशि संबंधित एजेंसी को प्रथम किस्त विमुक्त की गई है। जनपद पंचायत नटेरन के सहायक लेखाधिकारी महेंद्र रघुवंशी को जिला पंचायत द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3317 दिनांक 03.06.2019

द्वारा लेखा संबंधी कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण लेखा संबंधी कार्य नहीं कराने के निर्देशों के उपरांत भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नटेरन द्वारा विरष्ट कार्यालय के जारी निर्देशों के विपरीत रघुवंशी, सहायक लेखाधिकारी को 15वें वित्त योजना का कार्य कराया जा रहा था। 12 मई 2022 को परियोजना अधिकारी सुरेश वर्मा द्वारा जनपद पंचायत नटेरन में मनरेगा में सामग्री भुगतान के संबंध में जांच हेतु निरीक्षण किया गया जिसमें सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत नटेरन द्वारा ग्राम पंचायतों को सामग्री भुगतान किए गए जिसके बिल बाउचर की रेंडमली आधार पर चेक किए गए। जिसमें पाया कि कुछ ग्राम पंचायतों में कार्यों का प्राथमिकता क्रम में भुगतान नहीं हुआ है, जिसके संबंध में सहायक लेखाधिकारी द्वारा स्पष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए।

उपरोक्त तथ्यों, दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि संचालक पंचायतीराज द्वारा प्राप्त शिकायत जनपद पंचायत नटेरन जिला विदिशा में 15वें वित्त आयोग की राशि के गलत तरीके से भुगतान प्रथम दृष्टा सही पाई गई। उपरोक्त जांच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक लेखाधिकारी एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत नटेरन प्रथम दृष्टा दोषी पाए जाते हैं। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए गए दस्तावेजों, नस्तियों एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, परंतु जनपद पंचायत नटेरन के विरुद्ध 15वें वित्त अंतर्गत गंभीर वित्तीय अनियमितता की विस्तृत जांच किया जाना उचित होगा।

उसके बाद कार्यालय जिला पंचायत विदिशा ने सहायक सहायक पंचायतराज संचालनालय भोपाल को 8 अगस्त को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन में दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्टा दोषी पाए जाने और विस्तृत जांच किए जाने की अनुशंसा भी की गई थी। लेकिन उसके बाद भी पंचायतराज संचालनालय में दोनों की फाइलें दबा दी गईं। इस संदर्भ में गत दिनों शब्दीर सेफी नामक व्यक्ति ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र द्विंद्र सिंह सिसोदिया से शिकायत की थी। मंत्री ने भी मामले को संज्ञान में लिया और जांच के निर्देश दिए थे। लेकिन आज तक दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उधर, इस मामले में जब कुरेले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरा काम नियमानुसार किया है। तबादला तो एक सामान्य प्रक्रिया है।

● लोकेंद्र शर्मा

**ए** क तरफ सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहते, जिससे उनका पेट भरे और सरकार का खजाना खाली रहे। ताजा मामला अरबों रुपए के घाटे में मूँग बेचने का है। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने प्रदेश के किसानों से 7,20,000 किवंटल मूँग खरीदा था। सरकार ने इसके लिए 7275 प्रति किवंटल का भाव किसानों को दिया था। यानी किसानों को कुल 5,23,80,00,000 रुपए भुगतान किए गए। अब सरकार ने किसानों से खरीदी किए गए मूँग को खरीदने के लिए टेंडर निकाला। इस मूँग को खरीदने के लिए कई व्यापारी तैयार थे। इसके लिए प्रति किवंटल 6000 से लेकर 6100 प्रति किवंटल के भाव दिए जा रहे थे।

लेकिन मार्केफेड के अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और सरकारी मूँग का टेंडर 5400 रुपए प्रति किवंटल की बोली पर मंजूर कर दिया। इससे सरकार को प्रति किवंटल 1875 रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। यानी 7,20,000 किवंटल मूँग के बड़े लॉट को बेचने में सरकार को 135 करोड़ रुपए की चपत लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि किसानों से अधिक मूल्य पर मूँग खरीदकर कम कीमत पर बेचा गया है।

इस मूँग को अधिक कीमत पर खरीदने को तैयार व्यापारियों को कहना है कि इस टेंडर में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में जांच कराई जानी चाहिए। अगर सरकार खुले बाजार में भी इसे बेचती तो कम से कम 6000 रुपए किवंटल के भाव से यह मूँग बिक जाता। लेकिन अधिकारियों ने अपना हित साथने के लिए ऐसा किया है। व्यापारियों का आरोप है कि जिसने कम कीमत पर यह मूँग का टेंडर लिया है, वह उसे 5600 रुपए प्रति किवंटल के भाव से बेच भी रहा है। ऐसे में आखिर क्या वजह थी कि 1875 रुपए के घाटे में मूँग को बेचना पड़ा। बताया जाता है कि गाड़रवाड़ा की मेसर्स पुष्पा इंटरप्राइजेज ने मार्केफेड के प्रबंध संचालक को पत्र लिखकर सूचित किया था कि वे नर्मदा संभाग की मूँग को 6000-6100 प्रति किवंटल तक लेने को तैयार हैं। लेकिन सरकार ने किसी भी व्यापारी की नहीं सुनी और बड़े लॉट की बोली में मूँग को घाटे में बेच दिया।

गौरतलब है कि मप्र राज्य सहकारी विषयन संघ (मार्केफेड) ने सरकारी गोदामों में से मूँग की नीलामी की प्रक्रिया जब शुरू की थी, तभी यह विवादों में फंस गई थी। व्यापारियों ने निविदा की शर्तों और प्रक्रिया पर विरोध जताया था। दरअसल प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों के गोदामों से मार्केफेड कुल 1 लाख 11 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा साबुत मूँग की नीलामी कर रहा था। नीलामी में बेची जा रही मूँग समर्थन मूल्य पर



## मूँग के टेंडर में बड़ा धालमेल

### इस बार विरोध के बाद हुई खरीदी

इस बार सरकार ने काफी विरोध के बाद मूँग की खरीदी की है। 2022 में प्रदेश के 30 जिलों में 5-6 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूँग की फसल साढ़े तीन से चार लाख किसानों ने लगाई थी, जिससे 15-17 लाख मेट्रिक टन मूँग का उत्पादन हुआ है। प्रदेश में मूँग का बम्पर उत्पादन होने के बाद भी सरकार ने जब मूँग की खरीदी शुरू नहीं की तो किसान अपनी मूँग की फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हुए। भारत सरकार ने मूँग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने के लिये मूँग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7755 रुपये घोषित किया था। जब प्रदेश में चारों तरफ मूँग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग तेज होने लगी तो सरकार ने मूँग खरीदना शुरू किया। बताया जाता है कि बजट की कमी के कारण सरकार मूँग की खरीदी में देरी कर रही थी।

रबी सीजन 2021-22 में ही उपार्जित की गई थी। मार्केफेड की नीलामी प्रक्रिया शर्तों को लेकर प्रदेशभर के व्यापारियों और मंडी में असंतोष फैल गया। दरअसल नीलामी के साथ शर्त रखी गई है कि एक बार में एक ही लाट में गोदाम की पूरी मूँग का विक्रय होगा। जिन जिलों के गोदामों से मूँग का विक्रय हुआ वहां सबसे छोटा लाट भी 128 मीट्रिक टन का था। जबकि सीहोर, हरदा, होशगांवाद जैसे प्रमुख मूँग उत्पाद क्षेत्रों के गोदामों में लाट 2200 से लेकर 71 हजार मीट्रिक टन के थे। व्यापारियों के अनुसार एक बार में

इतनी मात्रा बेचे जाने की शर्त का सीधा लाभ बड़ी कंपनियों को मिलेगा। छोटे और मध्यम मिलर्स और कारोबारी सरकारी विक्रय की प्रक्रिया से खुद-ब-खुद बाहर हो जाएंगे। क्योंकि छोटे मध्यम मिलर्स के लिए इतना मूँग एक साथ उठाना संभव नहीं है। इसका असर हुआ कि बड़ी कंपनियों ने लाभ उठाते हुए कम दामों पर मूँग खरीदी। आगे भी बड़ी कंपनियों को ही सर्वे माल का लाभ मिलेगा। छोटे-मध्यम कारोबारियों ने मांग रखी थी कि सरकार मूँग विक्रय की शर्तों में बदलाव कर लाट में विक्रय करे। ताकि मध्यम-छोटे मिलर्स प्रक्रिया में शामिल हो सके। साथ ही शर्त भी रखी जाए कि कंपनियां सरकार से खरीदी गई मूँग को प्रदेश की मंडियों में न बेचे। स्थानीय कारोबारियों को डर है कि कंपनियां सरकारी गोदामों से खरीदा मूँग मंडियों और बाजार में उतारकर अचानक गिरावट का माहौल बना सकती है। हालांकि निविदा और नीलामी की शर्तों में मार्केफेड ने यह शर्त तो जोड़ी है कि आगे समर्थन मूल्य पर मप्र में होने वाली मूँग खरीदी के दौरान यह मूँग विक्रय के लिए नहीं आना चाहिए। हालांकि प्रतिबंध सिर्फ समर्थन मूल्य में बेचे जाने पर है। साफ है कि आगे मूँग के बाजार में उतरने वाला यह स्टॉक और फिर एमएसपी पर होने वाली खरीदी दोनों बाजार को बुरी तरह प्रभावित करेंगे। एक ओर सरकारी खरीदी के कारण किसान अब कम दाम पर मूँग नहीं बेचेंगे। दूसरी ओर बड़ी कंपनियों द्वारा अपने स्टॉक के दम पर कभी भी बाजार में गिरावट लाने का खतरा बरकरार रहेगा।

● प्रवीण सक्सेना

20

23 में होने वाले मप्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकते हैं। इसे लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन में जरूरी बदलाव पर चर्चा हुई। प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक अध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर बात हुई। ऐसे में संभावना है कि भोपाल, ग्वालियर समेत कई बड़े जिलों में जिलाध्यक्ष जल्दी बदले जा सकते हैं।

चंबल अंचल के सीनियर कांग्रेस लीडर ने बताया कि अगले साल चुनाव होने हैं। पार्टी के सामने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल होने वाले 22 विधायकों में से 19 विधायक इसी क्षेत्र से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। लिहाजा, इन क्षेत्रों में कांग्रेस को चुनावी नजरिए से मजबूत करने के लिए फेरबदल किए जाएंगे। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, निवाड़ी, मुरैना, अशोकनगर, श्योपुर समेत करीब 16 जिलों के अध्यक्षों को बदलने पर चर्चा हुई है। सूत्रों की मानें तो जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट पर भी अगले हफ्ते तक जारी हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दो महीने का वक्त हो चुका है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच गई है। राहुल के दिल्ली पहुंचने पर खड़गे की नई टीम को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है।

अगले साल 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों के सभी पार्टियों के लिए चुनाव अहम होंगे, क्योंकि इन राज्यों में पार्टियों की जीत या हार से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड़ का पता चलेगा। इन चुनावों से पार्टियों को राज्यों में मजबूती का पता चलेगा। इसके आधार पर पार्टियां लोकसभा के लिए रणनीति तैयार करेंगी। मप्र, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। मप्र और कर्नाटक में जहां भाजपा की सरकार है, वहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में कांग्रेस का बिज है। इन राज्यों में अभी से चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है। मप्र में कांग्रेस की हालत कई इलाकों में खराब है। सबसे ज्यादा विव्यु और बुंदेलखण्ड में कांग्रेस कमज़ोर है। प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं, जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। इनमें टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच और मंदसौर जिलों में किसी भी सीट पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं हैं। इन जिलों में 42 विधानसभा की सीटें हैं। इन



## कांग्रेस में बड़ी सर्जी जल्द!

इन प्रमुख तारीखों पर आयोजित होगी गांधी चौपाल

नए साल में आयोजित होने वाली गांधी चौपालों में 1 जनवरी को कांग्रेस संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी गुरु गोविंदसिंह प्रकाश पर्व, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी लालबहादुर शास्त्री पुण्यतिथि, 12 जनवरी विवेकानंद जयंती युवा दिवस, 14 जनवरी मकर संक्रान्ति, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 21 जनवरी नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी, 27 जनवरी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय जयंती और 30 जनवरी महात्मा गांधी की शहादत की 75वीं पुण्यतिथि पर गांधी चौपाले लगाई जाएंगी। नए साल में आयोजित होने वाली गांधी चौपालों के आयोजनों की संपूर्ण वीडियोग्राफी करवाना अनिवार्य किया गया है, जिसे बाद में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भी भेजना होगा, साथ ही आयोजन संबंधित प्रकाशित होने वाले समाचारों की कटिंग भी अनिवार्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ई-मेल या वाट्सएप नंबरों पर प्रेषित करना होगा। इसी के साथ गांधी चौपालों में भाग लेने वाले सभी लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबरों को एक रजिस्टर में अकित कर उसके फोटो भी कार्यालय तक पहुंचाना होगा, जिससे उनका लगातार पार्टी से संपर्क बना रहा।

जिलों को लेकर भी कांग्रेस खासा जोर दे रही है। एआईसीसी में करीब दो घंटे चली बैठक में इन जिलों को लेकर भी चर्चा हुई है। लंबे समय से जिन सीटों पर कांग्रेस हार रही है, उनमें अगले एक साल तक ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर कमेटियों

से लेकर बूथ की टीम तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। अब कांग्रेस लगातार हार रहे विधानसभा क्षेत्रों में बूथ पर दो टाइप की टीमें तैयार करेगा। इनमें कांग्रेस की ओर से बूथ कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, यूथ कांग्रेस भी डिजिटल बूथ बनाकर युवाओं की टीम तैयार कर रहा है।

उधर भोपाल में पिछले दिनों आयोजित हुई बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गांधी चौपालों के आयोजनों में आई शिथिलता को नई दिशा देते हुए गांधी चौपालों को पुनः गति और विस्तार देने के निर्देश जारी किए हैं। वैसे तो गांधी चौपालों का आयोजन पूरे प्रदेश में विगत कई दिनों से चल ही रहा है, मगर 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस से लेकर पूरे जनवरी माह में 16 अलग-अलग दिनों में हर मंडल एवं सेक्टर स्तर पर गांधी चौपालों का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने गांधी चौपालों के जरिए आगामी चुनावों के लिए जनता का विश्वास जीतने और मौजूदा सरकार की खामियां गिनाई।

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारे महान नेताओं का आजादी के आंदोलन में बलिदानी इतिहास है। हजारों नौजवानों ने इस आजादी के लिए कुर्बानी दी है एवं लाखों कार्यकर्ताओं ने जेल की यातनाएं सही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हर मंडल एवं सेक्टर स्तर तक गांधी चौपाल आयोजित कर पार्टी के आजादी के इतिहास पर चर्चा की गई। हर मंडल सेक्टर पर स्वतंत्रता सेनानी, उनके पुत्र-प्रपौत्र, वरिष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी महिलाओं तथा मेधावी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। जनवरी माह में आने वाले त्योहार, पुण्यतिथि, जयंती, राष्ट्रीय पर्व और योग दिवस सहित करीब 16 अलग-अलग दिन इन गांधी चौपालों का आयोजन एक मंडलम और सेक्टर स्तर पर किया जाएगा। वर्तमान में सभी समन्वयकों के प्रयास और परिश्रम से 12952 गांधी चौपालों आयोजित हो चुकी हैं। प्रत्येक विधानसभा पर 100 गांधी चौपालों का आयोजन विधायकों के लिए ए महाजनसंपर्क अभियान सिद्ध होगा, जो पार्टी की जीत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

● अरविंद नारद



**गु** जरात में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत करने की मांग उठ रही है। लेकिन मप्र भाजपा सूत्रों का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश में अपना एक अलग मॉडल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत संगठन की ही तरह चुनावी मार्च पर युवाओं को लड़ाया जाएगा। वर्हीं उम्प्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जाएगा। ये नेता पार्टी की रणनीति बनाने से लेकर सत्ता और संगठन को सुझाव भी देंगे।

गौरतलब है कि मप्र शुरू से ही संघ, जनसंघ और भाजपा की प्रयोगशाला रहा है। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा मिशन 2023 के लिए एक प्रयोग करने जा रहे हैं। जिस तरह वीडी शर्मा ने संगठन में युवाओं को महत्वपूर्ण पद देकर मप्र भाजपा संगठन को देश का सबसे युवा और सक्रिय संगठन बनाया है, उसी तरह मिशन 2023 के चुनावी मैदान में युवा नेताओं को टिकट देने का प्लान बनाया है। इस प्लान के लिए 70 प्लस का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी 70 साल पार वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के लागू होने से मप्र विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, 2 कैबिनेट मंत्री और पार्टी के लगभग 13 विधायकों को अगले साल होने वाले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने टिकट देने के लिए एक फॉर्मूला तय कर रखा है। इसके तहत 70 साल से अधिक की उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने का मापदंड फिक्स है। ऐसे में लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बिसाहूलाल सिंह भी टिकट के हकदार नहीं हैं। ये दोनों शिवराज सरकार की कैबिनेट में उम्प्रदराज मंत्री हैं। हालांकि ये आगामी चुनाव में उत्तरने के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 में जो विधायक 70 पार के होंगे उनमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री बिसाहूलाल साहू, अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, सीतासरण शर्मा, गोपीलाल जाटव, नागेंद्र सिंह नागोद, श्यामलाल द्विवेदी, नागेंद्र सिंह गुढ़, रामलल्लू वैश्य, जयसिंह मरावी, प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, महेंद्र सिंह हार्डिंया, पारस जैन, देवीलाल धाकड़, के अलावा प्रभात ज्ञा, अनूप मिश्रा, गौरीशंकर शेजवार, जयंत मलैया, उमाशंकर गुसा, रघुनंदन शर्मा, हिम्मत कोठारी, कैलाश चावला, बिंजेंद्र सिसोदिया, अचना चिट्ठनिस, सुमित्रा महाजन, सुधा मलैया आदि।

## 70 पार वालों को टिकट नहीं उम्प्रदराजों के परिजन हो जाएंगे बेरोजगार

मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 200 पार का नारा दिया है। कटनी में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अबकी बार 200 पार के लक्ष्य के साथ 200 से अधिक सीटें जीतने का सकल्प लिया। भाजपा 200 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव में नए और युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। मप्र भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नैजवानों को अवसर देने का काम भाजपा करती है। मप्र में भी 2023 के चुनाव में भी नए लोगों को अवसर मिलेंगे। अबकी बार 200 पार के नारे के साथ इस दिशा में भाजपा रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेगी। इसके लिए भाजपा ने उम्प्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रखने की रणनीति बनाई है। लेकिन उम्प्रदराज नेताओं को इस बात का डर सत्ता रहा है कि अगर वे मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए तो उनके परिजन बेरोजगार हो जाएंगे। गौरतलब है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात ज्ञा के बेटे तुष्मुल ज्ञा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन, जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदर महाजन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ख्य. नंदकुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार भी टिकट के दावेदार हैं। इन युवा दावेदारों के अभिभावकों को यह डर सत्ता रहा है कि उनका सक्रिय राजनीति से अलग होते ही उनके परिजनों को भी दरकिनार कर दिया जाएगा।

हार्डिंया, पारस जैन, देवीलाल धाकड़ आदि शामिल हैं।

गौरतलब है कि 2018 में भाजपा ने कई 70 पार वाले विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो पिछले चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगले चुनाव के लिहाज से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन नेताओं में उमाशंकर गुसा, रामकृष्ण कुसमारिया, हिम्मत कोठारी और रुस्तम सिंह भी टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव तक इन सभी की आयु 70 के पार हो जाएगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी इस फॉर्मूले का गहरा असर पड़ा है। ऐसे में अब मप्र के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान से बाहर होने का डर सत्ताने लगा है। हालांकि भाजपा का 70 प्लस का फॉर्मूला पिछले चुनाव में भी था। इसके बाद भी भाजपा-कांग्रेस ने 70 या इससे अधिक उम्र वाले 9 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 4 को जीत मिली थी। सबसे अधिक उम्र वाले भाजपा के मोती कश्यप (78) और कांग्रेस के सरताज सिंह (78) चुनाव हार गए। भाजपा के तीन प्रत्याशी गुढ़ से नागेंद्र सिंह (76), नागौद से नागेंद्र सिंह (76) और रेणांव से जुगल किंगोर बागरी (75) चुनाव जीतने में सफल रहे। ऐसे में वीडी शर्मा ने मिशन 2023 के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके अनुसार 70 पार वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सकता है।

वीडी शर्मा के फॉर्मूले पर गौर करें तो मप्र भाजपा का जो नया मार्गदर्शक मंडल होगा, उसमें ये नेता शामिल हो सकते हैं—विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री बिसाहूलाल सिंह, अजय विश्नोई, गौरीशंकर बिसेन, सीतासरण शर्मा, गोपीलाल जाटव, नागेंद्र सिंह नागोद, श्यामलाल द्विवेदी, नागेंद्र सिंह गुढ़, रामलल्लू वैश्य, जयसिंह मरावी, प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, महेंद्र सिंह हार्डिंया, पारस जैन, देवीलाल धाकड़, के अलावा प्रभात ज्ञा, अनूप मिश्रा, गौरीशंकर शेजवार, जयंत मलैया, उमाशंकर गुसा, रघुनंदन शर्मा, हिम्मत कोठारी, कैलाश चावला, बिंजेंद्र सिसोदिया, अचना चिट्ठनिस, सुमित्रा महाजन, सुधा मलैया आदि।

● विकास दुबे

मिशन 2023 के मुकाबले में उत्तरने से पहले भाजपा की कोशिश है कि उसके सभी वर्तमान विधायकों की परफॉर्मेंस ऐसी रहे कि पार्टी को न टिकट बदलना पड़े और न ही हार का ड्रा रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी लगातार मंत्रियों और विधायकों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों के साथ बैठक करके इमेज सुधारने का आरिवरी मौका दिया है।

**म** प्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के काम में फेरबदल, बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वहीं सत्राओं और संगठन चुनावी मोड में आ गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेशभर के ताबड़तोड़ दौरे

और ब्लॉक एवं जिला स्तर से मिले फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों से बैठक करनी शुरू कर दी है। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को क्षेत्र में अपनी छवि सुधारने की सख्त हिदायत दी जा रही है।

इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में इनके कामकाज की समीक्षा करने के साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होना है, इसलिए भाजपा दफ्तर में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री की विधायकों और बाद में मंत्रियों संग हुई बैठक को पार्टी की अगली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में विधायकों उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत भी कराया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की स्थिति, विधायकों का लोगों से संवाद, लोगों के बीच उपलब्धता आदि पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों से कहा है कि वे क्षेत्र में निकलें और लोगों के बीच रहें। जिनकी स्थिति खराब है, वे संभल जाएं। यदि जनता में अपनी इमेज सही नहीं बना पाते हैं तो फिर अगले चुनाव में टिकट के लिए दावा अभी से छोड़ दें। मंत्रियों को विकास योजनाओं में जिले के समस्त भूमिपूजन कार्यक्रम करने और योजनाओं से आम लोगों को अवगत करने जैसे विषय की तैयारी करवाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संगठन ने इस बात पर नाराजगी जताई कि प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर नहीं जाते हैं। बार-बार कहने के बाद भी गांवों में रात्रि

## माननीयों को इमेज सुधारने का आरिवरी मौका



## अब सबको साधने का जातन

तीनों सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पार्टी पूरी तरह एकश्न मोड में नजर आ रही है। लोकेन सभी सर्वे रिपोर्ट में एक बात कॉमन है कि गवालियर-चंबल संभाग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वहीं प्रदेश के बुदेलखण्ड और विध्य में भी भाजपा को ज्यादा मेहनत की जरूरत बताई गई है। बुदेलखण्ड वही क्षेत्र हैं जहां से 4 कद्दावर मंत्री सरकार में शामिल हैं। भाजपा नेताओं को एक सूत्र में पिराने एक सतत समीक्षा की नसीहत दी गई है। पिछले दिनों प्रक्रिया है। सर्वे को लेकर मंत्री प्रदेश भाजपा रजनीश अग्रवाल का कहना है कि हमारी पार्टी के आंकलन की अपनी व्यवस्था है। कार्यकर्ताओं के हर स्तर पर समीक्षा की जाती है। और यह चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं कि भाजपा कहीं कमजोर नहीं है। हम हर मोर्चे पर डटे हैं, बेहतर परिणाम आएंगे। गौरतलब है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है, इसलिए पार्टी के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा काफी सोच-समझकर आगे बढ़ रही है।

विश्राम अधिकतर मंत्रियों ने नहीं किया। पार्टी नेताओं ने मंत्रियों द्वारा विभागीय कामकाज में अरुचि पर भी सवाल किए गए। प्रभार के जिलों में कार्यकर्ताओं से संवाद और जिला कोर ग्रुप की बैठक नहीं करने जैसे विषयों पर भी नेताओं की नाराजगी मंत्रियों को झेलनी पड़ी। इस कवायद को मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले माह में शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें कामकाज में कमजोर मंत्रियों की छुट्टी की जाएगी और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव ने मंत्रियों को स्पष्ट कहा कि जब भी वे प्रभार के जिलों में जाएं तो गरीब बस्तियों और अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों में भी औचक निरीक्षण कर वहां के छात्र-छात्राओं से संवाद करें। उन्होंने कहा कि लोगों से बैठक करें। इसके बाद विधायकों को एकांत में संवाद करें। इस समय कोई अधिकारी मौजूद नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम चार संभागों में संपन्न हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 83 लाख लोगों को अधिकार पत्र सौंपे गए हैं। शेष संभागों में भी जल्द कार्यक्रम आयोजित होंगे।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में मंत्रियों ने उनके प्रभार के जिलों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्रदेश प्रभारी

मुरलीधर राव को दी गई। राव ने विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी मंत्रियों को नई सरकार बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ प्रभार के जिलों और क्षेत्रों में काम करने की बात कही। साथ ही मिश्रा ने बताया कि सप्ताह में एक दिन प्रदेश कार्यालय में तीन मंत्री बैठेंगे, जो प्रदेश और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। डॉ. मिश्रा ने बताया कि बैठक में मंत्रिगणों को कहा गया है कि जब भी वे प्रभार के जिलों में जाएं तो गरीब बस्तियों और अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों में भी औचक निरीक्षण कर वहां के छात्र-छात्राओं से संवाद करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम 4 संभागों में संपन्न हो चुके हैं। शेष संभागों में भी जल्द कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भूअधिकार आवास योजना का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। 1 से 15 फरवरी के बीच विकास यात्राएं निकलेंगी। इस दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा के दौरान 1 फरवरी से निकाली जाने वाली विकास यात्रा पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए विधायकों के क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्य की अपडेट रिपोर्ट लेने के साथ उनसे आगामी विकास कार्यों के प्रस्ताव भी ले रहे हैं। इसके अलावा विधायकों के क्षेत्र के क्षेत्रीय व जातीय समीकरण पर भी चर्चा कर समाज के लोगों को साधने की नसीहत भी दी जा रही है। इस दौरान विधायकों को उनकी क्षेत्रीय सर्वे रिपोर्ट से अवगत कराने के साथ उनकी कमजोरियां भी बताई जा रही हैं। कई विधायकों का कार्यकर्ताओं से संवाद और नाराजगी की रिपोर्ट मिलने पर उन्हें इसकी जानकारी देकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और उनकी समस्याओं का प्रशासन व विभागीय अफसरों के माध्यम से निराकरण कराने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों जबलपुर, भोपाल व नर्मदापुरम संभाग के कई विधायकों के साथ वन-टू-वन की। पूर्व मंत्री व विधायक अजय विश्नोई मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। नर्मदापुरम जिले के एक विधायक के अनुसार चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों की पूर्णता, जनता



और कार्यकर्ता से संवाद और क्षेत्र में अधिकतम सक्रियता पर चर्चा कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक मुख्यमंत्री एक विधायक को 10 मिनट का समय दे रहे हैं, उनसे मिलने के दौरान चलो-चलो नहीं कहते, इससे हौसला बढ़ता है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री बैठेंगे। मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही मंत्रियों को प्रभार वाले जिले में जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभार वाले जिलों में मंत्री एससी-एसटी छात्रावासों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अधिकारी साथ नहीं रहेंगे।

2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा की परेशानी तीन सर्वे रिपोर्ट्स ने बढ़ा दी है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखण्ड और विंध्य क्षेत्र के जिलों में पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। ऐसे में पार्टी ने अपना अधिक ध्यान इन क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर कर दिया है। इन क्षेत्रों को नेताओं को एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दे दिया गया है। वैसे तो भाजपा हर समय चुनावी मोड पर रहने वाला राजनीतिक संगठन माना जाता है, लेकिन हाल ही में तीन तरह की सर्वे की रिपोर्टें ने प्रदेश के नेताओं को कड़ी मशक्कत कराने के लिए मैदान में ढूंढ़े रहने की हिदायत दे दी है।

वैसे तो भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने के बाद से ही चुनावी मोड में नजर आ रही है। लेकिन

जब से सर्वे रिपोर्ट आई है, जिला और संभाग स्तर पर नेताओं को एक्स्ट्रा एक्टिव मोड पर लाने के निर्देश राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों ने दे दिए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो प्रदेश में पिछले चुनाव में भाजपा ने जिन सीटों पर कमजोर परफॉर्मेंस किया था वहां रिस्ति में सुधार हुआ है लेकिन जो विंध्य पार्टी की ताकत बना था वहां रिस्तियां बदली दिख रही हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग में 2018 के चुनाव की तरह हालात बने हुए हैं। इस क्षेत्र में न केवल विरोधी पार्टी बल्कि पार्टी की आंतरिक गुटबाजी भी असर दिखा सकती है।

पार्टी सूत्रों की मानें तो अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट में अलग-अलग जानकारी आई है। किसी में 40 सीट तो किसी में 70 सीटों को डेंजर जोन में माना गया है। यूं तो चुनाव से पहले भाजपा ही नहीं अन्य राजनीतिक दल भी सर्वे कराते हैं लेकिन पार्टी के सूत्र बताते हैं ये मोदी-शाह फॉर्मूला है। जनता के बीच सरकार की क्या छाव है यह जानना बहुत जरूरी है। सूत्रों की मानें तो पार्टी ने एक आंतरिक सर्वे कराया है। एक सर्वे वनवासी कल्याण परिषद की ओर से किया गया तो एक संघ के माध्यम से। बीते दिनों सर्वे रिपोर्ट को लेकर सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामबाल, प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य नेताओं ने लंबी बैठकें कीं।

● कुमार विनोद

## कांग्रेस भी करवा रही सर्वे

प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपनी स्थिति का आंकलन करने के लिए कांग्रेस भी सर्वे करा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समय-समय पर अपने स्तर पर सर्वे करवाते रहे हैं। गोपनीय सर्वे के आधार पर वे अपने पार्टी नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय रहने की नसीहत देते रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़े यात्रा के पहले मप्र में कांग्रेस की मालवा के वरिष्ठ विधायक को भी एक सर्वे का हवाला देते हुए सक्रिय रहने को कहा गया था। भारत जोड़े यात्रा में निर्दलीय विधायक तो छोड़िए प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भाजपा कमजोर नहीं हो। प्रदेश की जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। आप वाले साल में सरकार बनेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सर्वे करते हैं, लेकिन वे सभी सर्वे गोपनीय होते हैं। जिससे संबंधित जो फीडबैक रहता है वैसा निर्देश दे दिया जाता है।

**म** प्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 1500 से अधिक शिकायतों में प्राथमिकी का इंतजार है। जबकि इस वर्ष शिकायतों पर जांच के बाद 100 से ज्यादा मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि मप्र में भ्रष्ट अफसरों पर कौन मेहरबान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी नहीं मिल रही है।

जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू में इस वर्ष शिकायतों पर जांच के बाद 100 से ज्यादा मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद भी अभी 1500 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। इनमें सबसे पुराने प्रकरण 2008 के हैं, यानी 13 साल बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। इसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। जांच में देरी की बड़ी वजह यह है कि जांच एजेंसी के पास स्वीकृत हमले में से 60 प्रतिशत की कमी है। दूसरी बात यह है कि कोरोना संक्रमणकाल में लॉकडाउन की वजह से भी कार्य प्रभावित हुआ है। ईओडब्ल्यू में अब तक 100 से ज्यादा मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जो जांच एजेंसी के गठन से लेकर अब तक में सर्वाधिक है।

शिकायतों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है। पिछले वर्षों में प्राथमिकी का आंकड़ा औसतन 50 से 60 के बीच रहता था। 2021 में 91 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस वर्ष यह संख्या 110 तक पहुंचने की उम्मीद है। जांच एजेंसी के पास हर वर्ष पांच से सात हजार शिकायतें पहुंचती हैं। शिकायतों का परीक्षण (स्क्रूटनी) किया जाता है। इनमें अधिकतम 10 प्रतिशत पर ही जांच शुरू हो पाती है। साथ्य के अभाव में या फिर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित नहीं होने से बाकी शिकायतों पर ईओडब्ल्यू जांच करने की जगह संबंधित विभाग को भेज देता है। इस वर्ष 400 शिकायतों पर जांच शुरू हो चुकी है। 2021 में यह आंकड़ा 289 था। प्राथमिकी दर्ज होने में देरी की एक वजह यह भी होती है कि राज्य शासन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने में विलंब होता है। हर समय औसतन 100 से ज्यादा मामलों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित रहती है। इनमें बैंकों से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी-कर्मचारियों के भी ज्यादा मामले हैं। शासन से एक बार में 10 से 15 मामलों में ही अभियोजन की अनुमति मिल पाती है।

प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त तो है लेकिन लोकायुक्त को भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी नहीं दे



## भ्रष्टों पर कौन मेहरबान ?

### कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि मप्र में भाजपा भ्रष्टाचार तंत्र को संरक्षण दे रही है। ऊपर तक इनकी मिलीभगत है इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों का मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचारियों का संरक्षण और उनका बचाव कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति देने की एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए तमाम पैरामीटर होते हैं। भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समझौता नहीं करती है। कार्रवाई लगातार जारी है। किसी को बद्धा नहीं जाएगा।

रही है। ऐसे करीब 280 अफसर हैं जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली है। लेकिन शासन की मंजूरी न मिलने के कारण इनके खिलाफ चार्जर्शीट ही पेश नहीं हो पा रही। कई बार प्रताचार के बावजूद संबंधित विभाग अभियोजन की स्वीकृति में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ विभाग तो लोकायुक्त की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे रहे। लोकायुक्त संगठन को ऐसे 280 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का इंतजार है। इजाजत नहीं मिलने की वजह से भ्रष्टाचार के 15 केस 9 साल से लंबित हैं। सबसे ज्यादा नगरीय आवास और विकास विभाग के लगभग 31 मामले लंबित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग और पंचायत

एवं ग्रामीण विकास विभाग के 29-29 मामले लंबित हैं। वहीं राजस्व विभाग के 25 और स्वास्थ विभाग के 17 मामले लंबित हैं। अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के कारण चार्जर्शीट पेश करने में देर हो रही है। वैसे नियम के अनुसार अधिकतम 4 महीने में अभियोजन की स्वीकृति मिलनी चाहिए।

आईएएस पवन जैन के खिलाफ केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सलाह के बाद शासन ईओडब्ल्यू को केस चलाने की मंजूरी देगा। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र लिखकर डीओपीटी से इस मामले में सलाह लेगी। ईओडब्ल्यू ने इंदौर से जुड़े 7 साल पुराने मामले में चालान पेश करने के लिए शासन से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। डीओपीटी से अभियोजन की स्वीकृति के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। तत्कालीन एसडीओ राजस्व पवन जैन पर रियल स्टेट के लोगों से सांठगांठ कर पर्यवेक्षण शुल्क जमा करने का आरोप है।

इस बीच सिंचाई परियोजनाओं में 800 एकड़ के घोटाले का मामला भी चर्चा में आ गया है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दखल हुआ है। ईडी ने ईओडब्ल्यू से एफआईआर की कॉपी मांगी है। ईओडब्ल्यू ने इसी साल बिना काम 800 करोड़ एडवास भुगतान के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर की कॉपी मांगी है। एफआईआर की कॉपी के आधार पर ब्लैक मनी के एंगल पर जांच होगी।

● डॉ. जय सिंह संधव

**म** प्र में मिशन 2023 के मद्देनजर भाजपा ने हर वर्ग को साथने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश में चुनावी आहट के बीच भाजपा के अलावा अब संघ ने भी आदिवासियों को फोकस कर मैदानी कसावट शुरू कर दी है। हिंदुओं को एक जुट करने में आदिवासी अहम कड़ी हैं, जिन्हें संघ फोकस करता रहा है। बोटबैंक के नजरिए से भी भाजपा के लिए यह अहम है। इस कारण आदिवासियों को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। भाजपा और संघ की कोशिश है कि आदिवासियों को अपना बनाया जाए।

गौरतलब है कि मिशन 2023 के तहत भाजपा ने अपना पूरा फोकस अनुसूचित जनजाति पर कर रखा है। इस वर्ग को साधने के लिए पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। अब संघ भी इस दिशा में सक्रिय होने जा रहा है। बनवासी राम की थीमलाइन से लेकर धर्मार्तरण रोकने और अधिकारों के संरक्षण तक पर संघ की विशेष टीमें इनके बीच जाएंगी। खास बात ये कि इसमें भारत जोड़े यात्रा वाले आदिवासी इलाके भी शामिल रहेंगे। भाजपा भी इस रूट के इलाकों को फोकस करके काम कर रही है। संघ भी इस बेल्ट में परंपरागत तरीके से काम करेगा। इससे पूर्व 2003 में शिवगंगा अभियान के जरिए संघ के अनुषांगिक संगठन बनवासी कल्याण परिषद ने बड़ी संख्या में आदिवासियों को जोड़ा था। स्वयंसेवक आदिवासी जागरूकता के लिए काम करेंगे। आदिवासियों को उनके अधिकार समझाने के साथ विचारधारा को इस वर्ग में मजबूत किया जाएगा। भाजपा पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा कर रही है। सियासी सरगर्मी के बीच बनवासी राम को लेकर संघ का काम भाजपा को मजबूत करेगा। बनवासी कल्याण परिषद के तहत इस पर काम हो रहा है। राज्य स्तरीय दफ्तर भी तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के भोपाल दौरे के समय किया गया। संघ का मानना है कि मिशनरी संस्थाएं आदिवासियों का धर्म बदलने का काम करती हैं। इस कारण बनवासी राम से जोड़कर आदिवासियों को हिंदू बनाए रखा जाए। भाजपा और संघ के लिए राष्ट्रीय स्तर से भी 2018 के बाद से ही मप्र अहम केंद्र बना हुआ है। संघ के कई बड़े बौद्धिक आयोजन इस दौरान हो चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उप्र के मप्र से सटे जिलों में भी संघ ने कार्यक्रम किए हैं। संघ का सहयोगी संगठन विद्याभारती मप्र के आदिवासी इलाकों में धर्म जागरण, सामाजिक समरसता और शैक्षणिक गतिविधियों की जमीनी हकीकत पर अंतर्कित परिपोर्ट तैयार करा रहा है। ताकि आदिवासियों के धर्मात्मण को रोकने और उनमें आध्यात्मिक जागरण का रोडमैप तैयार किया जा सके। हाल ही में विद्याभारती की सहयोगी संस्था जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा के माध्यम से संस्कार केंद्र कार्य अवलोकन अभियान



## चुनावी मोर्चे पर संघ

### अब संघ के रोजगार सृजन केंद्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब रोजगार के मुद्दे पर भी ध्यान दे रहा है। गत दिनों 4 दिन के प्रवास पर भोपाल आए संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भोपाल सहित 16 जिलों में रोजगार सृजन केंद्रों का शुभारंभ किया। भोपाल में यह केंद्र सी-13, शिवाजी नगर में खुला है। होसबाले ने यहाँ से अन्य जिलों में ऑनलाइन शुभारंभ किया। स्वदेशी जागरण मंच के साथ 23 संगठनों का समूह इस पूरी योजना का संचालन कर रहा है। इसे खालीलंबी भारत अभियान नाम दिया गया है। देश में अब तक 55 रोजगार सृजन केंद्र शुरू हो चुके हैं। इनमें 2 भोपाल में हैं। अगस्त में भोपाल आए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सतीश कुमार ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र शुरू किया था। पिछले महीने शारदा विहार में भी एक केंद्र शुरू हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री केशव दुर्गोलिया ने बताया कि 12वीं पास युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए स्टार्टअप, मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएंगी। विषय विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली जाएंगी। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में ये रोजगार सृजन केंद्र शुरू किए गए।

चलाया गया। इस अभियान से संघ के बड़े पदाधिकारी खुद आदिवासी आबादी के बीच इन संस्कार केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे और दो दिन उसी गांव में ठहरे। मध्यभारत प्रांत के जिलों में यह कार्यक्रम 15 से 30 नवंबर के बीच किया गया। कुछ जिलों में यह अभियान अभी चल ही रहा है।

संघ आदिवासियों के विकास और रोजगार पर फोकस करेगा। मप्र में बेरोजगार के रूप में 32.57 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि सरकारी और निजी सेक्टर मिलाकर 1 लाख से

कुछ अधिक पद रिक्त हैं। संघ पदाधिकारियों के अनुसार दिल्ली के बिट्टू टिक्की वाले और फिलपकार्ट शुरू करने वाले सचिन और बिनी बंसल युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद बन सकते हैं। बिट्टू ने सड़क किनारे दुकान शुरू कर 500 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। आदिवासी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग और औद्योगिक ट्रेनिंग दिलाने के लिए एमपी नगर में बनवासी कल्याण परिषद के कौशल विकास केंद्र का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है। 11 दिसंबर को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इसका लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत योगेश बापट भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अभियान में जनजातीय संस्कार केंद्र वालों गांवों में संघ पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के बारे में फीडबैक लिया। इनमें गांवों में सामाजिक समरसता, धर्मजागरण, हाल ही में हुए धर्मार्थण, हिंदू त्योहारों पर गांव के माहोल, स्वच्छता से जुड़े कामकाज का ब्यौरा पूछा गया। आदिवासी गांवों में 48 घंटे बिताकर लौटे संघ पदाधिकारियों ने गांववार अपना-अपना फीडबैक विद्याभारती को दिया है। इसी के आधार पर विस्तृत अंतरिक रिपोर्ट तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन यह रिपोर्ट आदिवासी अंचल में संघ और विद्याभारती की गतिविधियों के रोडमैप का आधार होगी। मप्र की तीनों प्रांत मालवा, महाकौशल और मध्यभारत में 1500 से अधिक जनजातीय संस्कार केंद्र चल रहे हैं। विद्याभारती के अंतर्गत जनजातीय शिक्षा के मध्यभारत प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख रूपसंहित लोहाने ने बताया कि मध्यभारत में के जिलों में 456 संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें सर्वाधिक रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिलों में हैं। इन सभी में केंद्र अवलोकन पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि इन संस्कार केंद्रों में सिर्फ एक ही शिक्षक होता है, जो प्राथमिक कक्षाओं के आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम संचालित करता है।

● राकेश ग्रेवर

**म** प्र के बिजली उपभोक्ता बिजली कंपनी के गलत निर्णय का बोझ उठाने को मजबूर हैं। जरूरत से ज्यादा बिजली के करार करने की वजह से हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले तीन साल में अकेले बिजली कंपनी ने 1773 करोड़ रुपए का भुगतान उन पावर प्लांट को किया, जिनसे एक भी यूनिट बिजली नहीं खरीदी गई। इन प्लांट को स्थाई लागत के रूप में राशि दी गई। इधर ये भार आम उपभोक्ता महंगी बिजली खरीदकर भर रहा है।

बता दें कि वर्तमान में बिजली कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंतर की भरपाई के लिए 3.02 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनी का मानना है कि उनके पास पर्याप्त बिजली की उपलब्धता है। फिलहाल कंपनी के पास करीब 21 हजार 615 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। जबकि 21 दिसंबर को बिजली कंपनी की सर्वोच्च मांग रबी सीजन में 16 हजार 514 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ये अभी तक का सबसे ज्यादा बिजली की मांग का रिकार्ड है। प्रदेश में इसी के आसपास बिजली की बिना सोचे विचार ही धड़ाधड़ कई साल पहले ही लंबे समय के करार पावर प्लांट से कर रही है। इस वजह से उन्हें शर्त के मुताबिक बिना बिजली लिए भी एक निर्धारित राशि भुगतान करनी पड़ रही है। विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा में इस संबंध में प्रश्न पूछा था। जिसके जवाब में विभाग ने जानकारी दी है। उनके अनुसार तीन साल में बिजली कंपनी ने साल 2019-20 में 494.25 करोड़, 2020-21 में 908.27 करोड़ तथा 2021-22 में 371.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इन तीन साल में कुल कंपनी ने 1773.71 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मप्र के जरूरत की करीब 84 प्रतिशत बिजली थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। इसमें 25.7 प्रतिशत एमपी जेनको, 36.6 प्रतिशत केंद्रीय एवं अन्य सेक्टर से मिलती है। 25 प्रतिशत बिजली निजी क्षेत्र तथा 8.3 प्रतिशत बिजली नवकरणीय ऊर्जा और अन्य तथा 4.4 प्रतिशत बिजली संयुक्त उपक्रम एवं अन्य जल विद्युत गृह से ली जाती है। गैर जरूरी बिजली करार पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि शर्तों के आधीन ही पावर प्लांट को राशि दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उनसे जब करार निरस्त करने की बात हुई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था।

राज्य सरकार बड़े घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देकर मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने की तैयारी में है। सरकार 301 से अधिक का स्लैब खत्म करने जा रही है। इस स्लैब वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 5 लाख है। अब ये 150 से 300 यूनिट की स्लैब

मप्र देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक राज्य है। इसके बाद भी प्रदेश के उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली मिलती है। इस महंगाई के दौर में बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। नए साल में गैर जरूरी करार का भार प्रदेश के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। अगर इसे लागू कर दिया गया तो उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा।



## गैर जरूरी करार का भार

### क्षम्, कहां होगी जनसुनवाई?

आयोग ने इस पर जनसुनवाई के लिए सूचना गत दिनों जारी कर दी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में 23 जनवरी, पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में 24 जनवरी और मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में 25 जनवरी को जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई के बाद मार्च में आयोग नए वित्तीय वर्ष के लिए नई दर निर्धारित करेगा। ये दरें एक अप्रैल से लागू होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार कंपनी 300 से अधिक यूनिट का स्लैब खत्म करने की तैयारी में है। इस स्लैब में लगभग पांच लाख से अधिक उपभोक्ता आते हैं। उक्त स्लैब के खत्म होते ही वे 150 से 300 यूनिट के स्लैब में आ जाएंगे। वहीं 150 से 300 यूनिट की खपत करने वाले करीब 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा। 1537 करोड़ की भरपाई आगामी वर्ष के लिए बिजली कंपनियों को सभी मदों से 49,530 करोड़ के राजस्व की जरूरत होगी, लेकिन उसे 47,992 करोड़ रुपए का राजस्व ही प्राप्त हो सकेगा। उसे प्रस्तावित हानि 1,537 करोड़ रुपए की होगी। इस हानि को पूरा करने के लिए बिजली दरों में औसत रूप से 3.20 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति आयोग से मांगी है। इसमें बिजली दर में औसत 3.20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।

प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां एक बार फिर उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी में हैं। बड़े घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देकर मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी करने की कवायद की जा रही है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से मप्र विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण की टैरिफ पिटीशन सौंपी है। कंपनियों ने बिजली दर में औसत 3.20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां एक बार फिर उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी में हैं। बड़े घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देकर मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी करने की कवायद की जा रही है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की तरफ से मप्र विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर निर्धारण की टैरिफ पिटीशन सौंपी है। जानकारी के अनुसार आगामी वर्ष के लिए बिजली कंपनियों को सभी मदों से 49,530 करोड़ के राजस्व की जरूरत होगी, लेकिन इस वर्ष कंपनियों को 47,992 करोड़ रुपए का राजस्व ही प्राप्त हो सकेगा। वहीं प्रस्तावित हानि 1,537 करोड़ रुपए की होगी। इस हानि को पूरा करने के लिए बिजली दरों में औसत रूप से 3.20 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति आयोग से मांगी है। इसमें बिजली दर में औसत 3.20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।

● जितेंद्र तिवारी

में आ जाएंगे। यानी उन्हें कम दरों पर बिजली मिल सकती है। वहीं, 151 से 300 यूनिट की

**म** प्र में स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने से स्कूलों की ग्रेडिंग लगातार गिरती जा रही है। दरअसल, प्रदेश में स्कूलों की ग्रेडिंग सुधारने के लिए भले ही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में शिक्षकों की लगातार सरकारी आयोजनों में इयूटी लगाई जा रही है। इस कारण वे स्कूलों से बाहर रहते हैं। जिसके कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में भोपाल के स्कूलों की ग्रेडिंग कैसे सुधरेगी?

गौरतलब है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले राज्यों में मप्र पांचवें स्थान पर है। इसे पहले स्थान पर लाने के लिए स्कूलों में कई तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, इनमें कुछ तैयारियां ऐसी भी हैं, जो प्रदेश व राजधानी को पहले पायदान पर आने से रोक रही हैं। ये तैयारियां राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षकों के शामिल होने, उन्हें सफल बनाने से जुड़ी हैं। इनका सामाजिक सरोकार तो है लेकिन पढ़ाई से संबंध नहीं है। यह वे कार्यक्रम हैं जो जिला मुख्यालयों पर आयोजित होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों को शामिल होना पड़ा है। और इन्हें शामिल कराने की जवाबदारी शिक्षकों की होती है।

प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले भोपाल में वर्षभर के भीतर 12 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें विद्यार्थी और बच्चों को शामिल होना पड़ा है। बाकी के अधिकतर शिक्षक बीएलओ इयूटी कर रहे हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बता दें कि भोपाल हाल ही में आई हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों की ग्रेडिंग के आधार पर तैयार रैंकिंग में 19वें पायदान पर रहा। इस जिले से अच्छा प्रदर्शन तो छोटे जिलों का रहा। जबकि प्राथमिक व हाई स्कूल की ग्रेडिंग के आधार पर तैयार होने वाली रैंकिंग में भी भोपाल को 29वीं रैंक मिली थी। यह हाल अकेले भोपाल का नहीं है, बल्कि अन्य प्रमुख जिलों का भी है, जो ग्रेडिंग में पिछड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों में मूल काम पढ़ाई पर जोर देना होगा और शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा। तभी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। प्राचार्यों का कहना है कि राजधानी में होने वाले कार्यक्रमों में शिक्षकों व विद्यार्थियों को भेजना अनिवार्य हो जाता है। वहीं, राजधानी के 450 शिक्षक दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्त और अटैचमेंट पर हैं।

प्रदेश के करीब 12 हजार शिक्षक पढ़ाना छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य में लगे हैं। कई शिक्षक विभागीय कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं। हालांकि, विभाग की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति व अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में लौटने का आदेश कई बार जारी किया गया है, लेकिन फिर भी पालन नहीं हो रहा है।

# कैसे सुधरेगी स्कूलों की ग्रेडिंग?



## सरकारी स्कूलों में छात्रों के भविष्य से रिवलवाइ

माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वह पढ़-लिखकर कुछ बन सके और देश का नाम रोशन कर सकें, लेकिन मप्र के सरकारी स्कूलों की हकीकत कुछ और है। प्रदेश के अलग-अलग सरकारी स्कूलों में बच्चों से काम करा जाने के मामले सामने आए हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उन विद्यार्थियों से स्कूलों में साफ-साफाई, बर्टन धुलाने और झाड़ू लगावाने जैसे काम कराए जा रहे हैं। हाल ही में छात्रों से काम करा जाने का मामला शहडोल जिले से सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शहडोल के बुद्धार विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से बालश्रम कराया जा रहा है। यहां शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कक्षा में जाने से पहले हर दिन पानी भरकर रखने का फरमान सुनाया है। स्कूली बच्चे अपने शिक्षकों की बातों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और हर दिन विद्यालय से कुछ दूरी पर रिश्त सरकारी हैंडपंप से भारी भरकम पानी की बाल्टी में पानी भरकर ला रहे हैं। बाल्टी का वजन छात्राओं के वजन से भी ज्यादा है, ऐसे में यदि पानी की बाल्टी गिर जाए तो बच्चियों को चोट भी लग सकती है, लेकिन बेपरवाह शिक्षकों को इससे फर्क नहीं पड़ता। बताया जा रहा है कि स्कूल में किसी भूत्य की नियुक्ति नहीं की गई है इसलिए छात्राओं से ही भूत्य के काम कराए जा रहे हैं। ये हाल मप्र के किसी एक सरकारी स्कूल के नहीं हैं बल्कि ग्रामीण अंचल के हर विद्यालय के हालात कुछ ऐसे ही हैं।

प्रदेश के 18 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आरिफ नगर के शासकीय हाईस्कूल में 18 शिक्षक हैं, लेकिन छह शिक्षकों की इयूटी बीएलओ कार्य में है। नवीबाग प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पदस्थ हैं और दोनों की इयूटी बीएलओ में लगाने के लिए कोई नहीं है। शासकीय प्राथमिक शाला द्वारका नगर में नौ में से सात शिक्षकों की इयूटी अन्य कार्यों में लगाई गई है। सीएम राइज करोंद में आठ शिक्षकों की इयूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है।

लैपटाप वितरण कार्यक्रम, मेडिकल में हिंदी की किताबों के लाच करने का कार्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, सात दिवसीय विश्वरंग कार्यक्रम, सीएम राइज भवनों का भूमिपूजन, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आयोजित समारोह, बिरसा मुंडा जयंती समारोह, अनुगृज 4 से 5 दिसंबर, बाल रंग 17 से 19 दिसंबर, नशा मुक्ति कार्यक्रम, उषा एप के

लॉन्चिंग कार्यक्रम, मूँग दाल वितरण कार्यक्रम, घर-घर तिरंगा अभियान आदि। शिक्षाविद सुनीता सक्सेना कहती है कि देखने में आ रहा है कि स्थानीय कार्यक्रमों में शिक्षकों व विद्यार्थियों को शामिल किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए स्कूलों में 15-15 दिन पूर्व से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह भी ग्रेडिंग में पिछड़ने का एक बड़ा कारण है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि भोपाल जिले की रैंकिंग इसलिए पिछड़ रही है, क्योंकि यहां अधिकांश समय शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों या शासन के बड़े-बड़े कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

**म** प्र का पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों के लिए असुरक्षित होता दिख रहा है। वर्ष 2009 में यहां एक भी बाघ नहीं बचा था। कई प्रयासों के बाद उन्हें फिर से बसाया गया। इसकी देश-दुनिया में प्रशंसा भी हुई, लेकिन अब हालात वैसे ही हैं। पिछले तीन साल में यहां पांच बाघ और एक तेंदुआ का शिकार हो चुका है। पार्क की सीमा से सटे पन्ना उत्तर बनमंडल के विक्रमपुर गांव में गत दिनों पहले देर शाम नर बाघ का शव क्लच तार के फंदे पर झूलता मिला है। छह माह पहले एक बाधिन और उसके दो शावकों के शव मिल चुके हैं।

वर्ष 2020 में शिकारियों ने एक बाघ का गला काटकर शव केन नदी के पानी में डुबो दिया था। जिस उत्तर बनमंडल में हाल में बाघ का शिकार हुआ है, वहां इसी साल जुलाई से बनमंडल अधिकारी का पद खाली है। दक्षिण बनमंडल के अधिकारी उसका प्रभार संभाल रहे हैं। 12 साल की मेहनत का परिणाम है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में आज करीब 70 बाघ हैं, लेकिन सुरक्षा के जैसे इंतजाम और अनदेखी है, उससे लगता है कि यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहेगी।

सूत्र बताते हैं कि पार्क के कुछ हिस्से और आसपास के क्षेत्र में नियमित गश्त नहीं हो रही है। जिस क्षेत्र में हाल ही में बाघ का शिकार हुआ है, वहां पिछले साढ़े पांच महीने से अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। पार्क के पूर्व संचालक ने बाघों को कालर आईडी से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा था, हालांकि इसे बन्यप्राणी मुख्यालय ने नहीं माना पर कालर लगे बाघों की मॉनीटरिंग बंद कर दी गई थी। जानकार बताते हैं कि इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ती गई। पन्ना के बाघों की गर्दन में सैटेलाइट कालर लगाया गया था। तीन सदस्यीय दल बाघ या बाधिन से 100 मीटर की दूरी पर एंटीना लेकर चलता था, उसका मूवमेंट देखता रहता था। एक स्थान पर बाघ 10 मिनट रुका और उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो जांच दल हाथियों की मदद से बाघ तक पहुंच जाता था।

कभी हीरों की नगरी पन्ना के जंगलों पर उसका राज चलता था, वह मांद से निकलता था तो पूरा जंगल सहम जाता था, उसकी एक दहाड़ से जंगल का जर्ज-जर्ज थर्रा उठता था! भारी-भरकम ढीलढोल वाले खूंखार बाघ को यहां बाघों का जनक कहा जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में देश-विदेश से आने वाले पर्यटक उसकी एक झलक पाने ललायित रहते थे। बाघ विहीन पन्ना को एक से एक नायाब नगीने उसी ने दिए, लेकिन अब वह उपेक्षित है, गुमनाम जीवन जी रहा है। उसी से पैदा हुए वंशजों ने उसकी टेरिटरी पर कब्जा जमाकर उसे खदेढ़ दिया। यहां बात हो रही है पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर नंबर-1 बाघ टी-3 की, जिसने पन्ना को



## बाघों के लिए सोफ नहीं पन्ना टाइगर रिजर्व

### डैकैत ठोकिया ने किए थे शिकार

वर्ष 2000 के आसपास पन्ना टाइगर रिजर्व और नजदीकी क्षेत्र में सक्रिय डैकैत ठोकिया ने सबसे अधिक बाघों का शिकार किया। वह बाघ के अंगों की तस्करी करता था। पार्क में उसका इतना आतंक था कि कई क्षेत्रों में निरानी बंद हो गई थी। वर्ष 2007 में शोध करने पन्ना आए शोधार्थी चंद्रघुन ने वन अधिकारियों को बताया कि पार्क में बाघ हैं ही नहीं। हालांकि जांच में तत्कालीन वन अधिकारियों ने इसे झूठला दिया। जब भारतीय बन्यप्राणी प्रबंधन संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों ने जांच की, तो साफ हो गया कि पार्क में एक भी बाघ नहीं है। आखिर बाघ पुनर्स्थापना योजना बनी और कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ, पेंच से बाधिन पन्ना भेजे गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी एक जोड़ा भेजा गया। इन्हीं से कुनबा बढ़कर 70 पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005-06 तक पार्क में 30 से 35 बाघ थे।

बाघों से आबाद किया था।

मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में पन्ना के बाघ टी-3 ने अहम भूमिका निभाई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में उसने दो से 80 बाघों तक का सफर पूरा कराया। महज 14 साल में उसने अकेले तीन दर्जन से अधिक बाघ सदस्यों को जन्म दिया था। अब वह बूढ़ा हो चुका है। उसके इलाकों पर उसके बेटे, नारी-पोतों ने कब्जा जमा लिया है। उसकी साथी बाधिन, उसके बेटों और उनसे जन्मे बाघों ने उसकी टेरिटरी पर ही कब्जा जमाकर उसे खदेढ़ दिया है।

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के बाद आए पहले बाघ टी-3 ने जंगलों की खाक

छानकर यहां स्थित तालगांव पठार को अपना पहला इलाका बनाया था। इस इलाके में वह साथी बाधिन टी-1 और टी-2 के साथ इसी इलाके को टेरिटरी बनाकर रखा था। यह वह इलाका था जहां से पन्ना में बाघों की वंश बढ़ना शुरू हुआ था। बाघ टी-3 की पहली संतान पी-111 पन्ना टाइगर रिजर्व का हीरा कहलाता था, जो पिछले दिनों खत्म हो गया। यह वही टाइगर था, जो बिलकुल अपने पिता के जैसे ही दबंग, तेज, खूंखार था। जवानी में कदम रखते ही उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाका तालगांव पठार पर कब्जा जमाया था। उसके कारण ही पिता बाघ टी-3 को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था।

बाघ टी-3 के बूढ़े होने और जंगल में दहशत व रूतबा खत्म होने के बाद उसके वंशजों, साथी बाधिनों ने साथ छोड़ा तो ठीक पन्ना टाइगर रिजर्व ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। प्रबंधन ने उसके गले में पहनाया गया रेडियो कालर आईडी उतार लिया है। अब यह बाघ जंगल में कहां किस लोकेशन पर है, इसकी जानकारी प्रबंधन को भी नहीं रहती। महीने-15 दिन में उसकी मैन्युअल लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। अपले ने भी उसे उपेक्षित कर खुद के हाल पर छोड़ दिया है। साल 2008 के पहले बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके लिए बांधवगढ़ से बाधिन टी-1 और पेंच टाइगर रिजर्व से पर बाघ टी-3 व कान्हा से एक अन्य बाधिन टी-2 को लाया गया था। दो बाधिनों के साथ टाइगर ने अपना वंश बढ़ाना शुरू किया तो यह सिलसिला लगातार आज तक जारी है।

● श्याम सिंह सिक्करवार

वि

धानसभा चुनाव का संग्राम शुरू होने के साथ ही बुदेलखंड राज्य निर्माण का मुद्दा गमने लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर मायावती तक ने बुदेलखंड राज्य के नाम पर सियासत चमकाई है। मप्र विधानसभा चुनाव में फिर एक बार बुदेलखंड राज्य की चर्चा है। बुदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जिसे उप्र और मप्र दोनों राज्यों में आधा-आधा बांटा गया है, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था। यह राज्य आजादी की लड़ाई जीतने के साथ ही अलग अस्तित्व वाला राज्य रहा है। यहां अलग मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में इसका विभाजन हो गया। तभी से भाषाई आधार पर बुदेलखंड को पृथक राज्य बनाने को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। चुनावों में ये मुद्दा गरम रहता है और उसके बाद इसकी धार धीमी हो जाती है।

बुदेलखंड में 14 जिले आते हैं। इसके पहले इस का और भी व्यापक रूप रहा है जो भिंड से लेकर रीवा, सतना विदिशा समेत मप्र के कई जिलों तक फैला रहा। वर्तमान में बुदेलखंड के इलाके में जो जिले माने जाते हैं उनमें उप्र के ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट शामिल हैं। मप्र के हिस्से में टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह व दतिया का नाम शामिल है। इसे वापस अलग राज्य को लेकर कई दशकों से आंदोलन चल रहे हैं। उमा भारती ने 2014 में झांसी से लोकसभा चुनाव के दौरान 3 साल में अलग बुदेलखंड राज्य का बादा किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। बुदेलखंड निर्माण मोर्चा समेत कई और संगठन अब बुदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

बुदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय कहते हैं कि 1956 के पहले तक बुदेलखंड अलग राज्य के अस्तित्व में रहा है। जब देश आजाद हुआ छोटे राज्यों को भारत में विलय करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल की तरफ से किया गया। उस समय बुदेलखंड की 35 स्थानीय रियासतों ने लिखित संधि की थी, जिसमें भाषा और बोली के आधार पर राज्य निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। 12 मार्च 1948 को बुदेलखंड राज्य इकाई का गठन किया गया। इसकी राजधानी नैंगांव बनाई गई। बुदेलखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। वह चरखारी के रहने वाले थे। बुदेलखंड राज्य को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो शिफारिश दी उसके आधार पर 1956 में बुदेलखंड को दो भागों में बांट दिया गया। इसका एक हिस्सा उप्र और दूसरा मप्र में समायोजित कर दिया गया। तभी से इसकी मांग शुरू हो गई। 1970 के दशक में झांसी में वैद्यनाथ आयुर्वेद के मालिक पं.



## पृथक बुदेलखंड की मांग तेज

### जनवरी से लगेगा अभियान

पृथक बुदेलखंड राज्य की मांग करने वाली बिखरी ताकतों को एकजुट करने और सभी को एक मंच पर लाने के लिए बुदेली सेना जनवरी से अभियान चलाएगी। बुदेली सेना के जिलाध्यक्ष अंजीत सिंह ने बताया कि पृथक बुदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए उप्र-मप्र बुदेलखंड के 14 जिलों में दो दर्जन से अधिक संगठन संघर्षत है। बांदा, महोबा, झांसी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, दमोह, पन्ना, सागर आदि जिलों में पृथक बुदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले दो दर्जन से अधिक संगठन हैं। सभी संगठनों का उद्देश्य है कि बुदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। अब जनवरी महीने से इन सभी दो दर्जन संगठनों को एक मंच पर लाने की मुहिम छेड़ी जाएगी। जब सभी ताकतें एक मंच पर आ जाएंगी तो आंदोलन भी सशक्त होगा। बुदेलखंड विकास बोर्ड उपाध्यक्ष और सिने स्टार रहे राजा बुदेला ने कहा कि बुदेलखंड राज्य की कवायद शुरू हो चुकी है। 2024 के पहले इसे बनाया जाएगा। राज्यसभा में इसके पास न होने से विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि बुदेलखंड में अब पलायन रुकेगा। कृषि विवि परिसर में स्पॉटर्स कॉम्प्लेक्स और फिल्मी सेंटर बनेगा। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं।

विश्वनाथ शर्मा ने बुदेलखंड राज्य निर्माण की मांग उठाना शुरू की। उन्होंने बुदेलखंड एकीकरण समिति का गठन किया। इसमें हजारों सदस्य जोड़े गए। 1989 में बुदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन शंकरलाल मेहरोत्रा ने किया और अलग राज्य की लड़ाई को उन्होंने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया। कई बार गिरफ्तारी भी हुई।

बुदेलखंड अलग राज्य की मांग के लिए कई नेता और राजधाने भी आंदोलन में शिरकत करते रहे हैं। मप्र से तत्कालीन टीकमगढ़ संसद

लक्ष्मीनारायण नायक ने बुदेलखंड की आवाज उठाई। उनके साथ उमा भारती ने अलग बुदेलखंड राज्य की पैरवी की और वह जंतर-मंतर पर कई बार आंदोलन में शिरकत करने भी पहुंची। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बिटठल भाई पटेल, पना महाराज, औरछा महाराज, पूर्व विधायक मुना राजा बसारी, बेबीराजा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, मदन मानव आंदोलन का हिस्सा रहे। उप्र के इलाके से जो नेता बुदेलखंड राज्य के लिए लड़ते रहे उनमें पूर्व सांसद स्व. विश्वनाथ शर्मा, गंगाचरण राजपूत, बादशाह सिंह, प्रदीप जैन आदित्य, राजा रंजीत सिंह जूदेव, हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, तिंदवारी ब्रजेश प्रजापति, झांसी विधायक रवि शर्मा, पूर्व सांसद भैरो प्रसाद मिश्रा, राजेंद्र अग्रिहोत्री, हरगोविंद कुशवाहा, रविंद्र शुक्ला, विनोद चतुर्वेदी, विवेक सिंह बांदा समेत कई बड़े नेताओं ने बुदेलखंड राज्य की मांग उठाई।

बुदेलखंड राज्य की मांग चुनाव में ज्यादा जोर पकड़ती आई है। राजा बुदेला ने भी इस मांग को उठाया। राजा बुदेला कांग्रेस के टिकट पर 2002 में झांसी लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद राजा बुदेला ने राजनीतिक दल बुदेलखंड कांग्रेस बनाकर 2012 में झांसी सदर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस चुनाव में सिर्फ 1984 वोट हीं हासिल हुए। मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुदेलखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाई तो यह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। राहुल गांधी 2007 और 2008 में दलितों के घर पर सो रहे थे तो मीडिया ने बुदेलखंड की बदहाली को उभारा था। उसके बाद 7466 करोड़ का बुदेलखंड पैकेज जारी किया गया। यह इलाका सियासी चर्चा में आ गया। राहुल गांधी की बुदेलखंड में सक्रियता के चलते तत्कालीन उप्र की मायावती सरकार ने बुदेलखंड को लेकर बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने उप्र को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जिसमें अलग बुदेलखंड भी था। 2012 में चुनाव के पूर्व उप्र को चार भागों में बांटने के इस प्रस्ताव को केंद्र ने अपूर्ण बताकर अस्वीकार कर दिया। तभी से ये मांग लगातार सुलगती रही है।

● सिद्धार्थ पांडे



# 2023 का आगाज नया साल चुनौतियां अपार

नववर्ष में आर्थिक मोर्चे के शिखर  
पर भी होगा नया भारत

2023 में भारत अपने हिसाब से तय  
करेगा कूटनीतिक दिशा

**कोरोना महामारी, गिरती अर्थव्यवस्था, रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध और ग्लोबल रसर पर उगपटक के बीच भारत ने वर्ष 2022 में विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराया है। इसलिए नया वर्ष 2023 भी चुनौतियों भरा रहने वाला है। क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सामरिक ताकत वाला देश बनता जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2023 में भारत अपने हिसाब से कूटनीतिक दिशा तय करेगा। साथ ही आर्थिक मोर्चे के शिखर पर भारत का अपना वजूद होगा।**

## ● राजेंद्र आगाल

वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है। नए साल में कई नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। कोरोना महामारी, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता से जहां आम आदमी को दो-दो हाथ करने की चुनौती है, वहीं सरकार को गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत

करना और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की चुनौती है। इस वर्ष 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए यह साल राजनीतिक पार्टियों के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। इसलिए वर्ष 2023 चुनौतियों के लिए अपार संभावनाओं को जनम देगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के लिए भारत जिस तरह मजबूत देश बनकर

उभरा है, उसे और मजबूत करने की चुनौती सरकार पर होगी। वहीं यह वर्ष आत्मनिर्भर मप्र के लक्ष्य को पूरा करने का भी है। इसके लिए वर्ष 2023 में हर तरफ हलचल देखने को मिलेगी। भारत के सामने एक बार फिर से विश्व गुरु बनने का मौका है। इसके लिए कूटनीतिक रणनीति कारगर होनी चाहिए।

पिछले दो साल कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर उठापटक का असर भारत की कूटनीतिक स्थिति पर भी पड़ा। हालांकि, भारत ने अब तक अपनी जरूरतों और हितों के हिसाब से इस मोर्चे पर अपना स्टैंड बनाए रखने में सफलता पाई है। इस लिहाज से 2022 भारत के लिए कूटनीतिक सफलता वाला साल रहा। क्या 2023 में भी भारत अपने हिसाब से कूटनीतिक दिशा और दशा को तय करेगा? क्या नई चुनौतियों से गुजरना होगा भारत को? कितना अहम होगा कूटनीतिक मोर्चा भारत के लिए? यह तमाम सवाल उभर रहे हैं नए साल के आगाज पर...।

### महंगाई और मंदी का भंवर

60 साल पहले एक सोचियत नेता को एक शतरंजी चाल सूझी थी। उसने सोचा कि परमाणु बमों से लैस दो मिसाइलों को गुपचुप क्यूबा ले जाकर अमेरिका की नाक के नीचे तैनात कर उसे शह दी जाए, पर वह इसका हिसाब नहीं लगा पाया कि अमेरिका की चाल क्या होगी और क्या उसकी काट उसके पास है? 60 साल बाद रूस के नेता को उससे भी दुस्साहसी चाल सूझी। उसने अमेरिका और नाटो देशों से दोस्ती बढ़ा रहे अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोलकर अमेरिका और नाटो को शह दी, पर उनकी चाल क्या होगी, यह उसने इस बार भी नहीं सोचा।

निकिता खुश्चेव की तरह फँसने के साथ-साथ पुतिन ने अपनी चाल से वैश्विक क्रम और संतुलन से जुड़े कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। दूसरे विश्वयुद्ध और शीतयुद्ध के बाद से यह माना जाने लगा था कि परमाणु अस्त्रों के पारस्परिक संहार के खतरे ने परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया है, लेकिन यूक्रेन पर जीत हासिल न कर पाने से बौखलाए पुतिन की आखिरी दांव के रूप में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने की धमकी ने उस मान्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका और नाटो के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पुतिन बड़े संहारक परमाणु अस्त्रों की जगह सीमित दायरे वाले परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उनका क्या जवाब होगा? पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अक्सर इसी तरह की धमकियां देते रहते हैं। परमाणु शक्तिसंपन्न देशों के बेलगाम और विस्तारवादी शासक अब समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट खड़े कर रहे हैं। इनके बारे में दुनिया को गंभीरता से सोचना होगा।

अभी तक राजनयिकों का सोचना था कि यूरोपीय संघ और रूस तथा अमेरिका और चीन व्यापार के लिए एक-दूसरे पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि अब इनके बीच युद्ध होने के आसार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान के मामले पर चीन के कड़े होते तेवरों ने इस धारणा



### नए साल में 10 राज्यों में असंबंधी इलेक्शन

साल 2023 में भारत के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्षीय राज्यों में होने वाले असंबंधी इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी 8 याचिकाओं का फैसला आना भी अभी बाकी है। जिसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ने वाला है। केंद्र सरकार के लिए इन सभी चुनाव में सबसे जरूरी है जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, वर्योकि यहां से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि 2023 के गर्मी में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहमियत रखते हैं मगर केंद्र सरकार को अगर साल 2024 में होने वाली लोकसभा सीटों में बहुमत से सरकार बनानी है तो विधानसभा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। इन राज्यों में 93 लोकसभा सीटें हैं जो पूरे देश की 17 प्रतिशत लोकसभा सीटें होती हैं। राजस्थान में 25, मप्र में 29, छत्तीसगढ़ में 11, कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, जम्मू-कश्मीर में 6, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, नागालैंड में 1 और मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। इन सभी को मिलकर कुल 93 लोकसभा सीटें होती हैं। अगर भाजपा इनमें से ज्यादातर सीटों में विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो लोकसभा सीटों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल कांग्रेस भारत जोड़े यात्रा में व्यस्त है जबकि भाजपा ने अभी से मिशन 2024 शुरू कर दिया है।

को ध्वस्त करते हुए सिद्ध किया कि हकीकत इसके उलट है। पुतिन ने यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को उसकी कमजोरी मानकर यूक्रेन पर हमला बोला। उन्हें लगता था कि अब्दल तो यूरोप के देश रूस के सामने खड़े होंगे नहीं और हुए तो ऊर्जा के संकट से भाग खड़े होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। व्यापाको लेकर अमेरिका और चीन की आपसी निर्भरता तो और भी ज्यादा है। इसलिए शायद चीनी नेता ताइवान को हथियाने के लिए रूस जैसा दुस्साहसी कदम न उठाएं, लेकिन यूक्रेन पर हमले ने साबित कर दिया कि सामरिक हितों के सामने आर्थिक हित गौण ही रहते हैं, भले ही वे कितने भी अहम क्यों न हों।

2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करने वाले और विश्व बैंक, आईएमएफ एवं फेडरल रिजर्व में काम कर चुके अर्थशास्त्री नूरिएल रुबीनी ने अपनी नई पुस्तक 'मैगारेट्स' या महासंकट में लिखा है कि दुनिया कर्ज, महंगाई और मंदी के ऐसे भंवर की तरफ बढ़ रही

है जो पिछली सदी के तीसरे दशक के आर्थिक संकट जितना गंभीर साबित हो सकता है। 1999 में पूरी दुनिया का निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर दुनिया की जीडीपी से लगभग दोगुना था। पिछले 20 वर्षों में वह दोगुने से बढ़कर साढ़े तीन गुना हो चुका है। चीन का निजी और सार्वजनिक कर्ज उसकी जीडीपी का 330 प्रतिशत हो चुका है और अमेरिका में 420 प्रतिशत। भारत के निजी कर्ज के विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं, फिर भी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर जीडीपी से लगभग डेढ़ गुना हो चुका है।

### चुनावी साल होगा 2023...

2023 सियासी सरगमियों और चुनावों के नाम होगा। इस वर्ष देश के करीब 10 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। 2024 के शुरू में ही लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिए 2023 को लोकसभा का

# साल 2023 में भी विदेशी निवेशकों को भाएगा भारत

अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति अपनाए जाने और रुस-यूक्रेन युद्ध जारी रहने से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत अपनी प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव योजना और काफी हद तक सेहतमंद इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना को देखते हुए वर्ष 2023 में विदेशी निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना रह सकता है। सरकार की तरफ से ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस और स्किल्ड मैनपावर को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, देश के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी नीतियों के उदार होने, विशाल घरेलू बाजार की मौजूदगी और ग्रोथ रेट अच्छी रहने की संभावनाओं से नए साल में भी भारत विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रह सकता है। हालांकि कॉर्टेपट के क्रियान्वयन में देरी, थकाऊ प्रक्रिया और ऊँची ब्याज दरें चिंता का विषय रह सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीडी की तरफ से जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, उद्योग जगत में नई परियोजनाओं के लिए होने वाले निवेश में सुधार की गति अब भी विकासशील देशों में कमज़ोर बनी हुई है। रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन संकट की वजह से पैदा हुई खाद्य, ईंधन व वित्त समरियाएं पहले से ही कोविड-19 महामारी के दुष्परिणामों का सामना कर रहे विकासशील देशों पर भारी पड़ रही हैं। इन परिस्थितियों में भी भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में वर्ष 2022 में अच्छी स्थिति में रहा है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने जनवरी-सितंबर 2022 की अवधि में 42.5 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हासिल किया है। इसके पहले वर्ष 2021 में भी भारत में 51.3 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया था। भारत को अब तक का सर्वाधिक एफडीआई वित्त वर्ष 2021-22 में मिला था जब विदेशी निवेशकों ने यहां कुल 84.84 अरब डॉलर लगाए थे। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत में आने वाला इकिवटी एफडीआई 14 प्रतिशत घटकर 26.9 अरब डॉलर पर आ गया। अप्रैल-सितंबर की इस अवधि में कुल एफडीआई निवेश (इकिवटी निवेश, दोबारा निवेश की गई राशि और अन्य पूँजी) भी घटकर 39 अरब डॉलर रह गया जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 42.86 अरब डॉलर रहा था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड में सचिव अनुराग जैन ने कहा कि भारत विदेशी निवेशकों के लिए प्रसंदित गंतव्य बना हुआ है।



## एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का विचार

जी-20 इन दिनों चर्चा में है। दिसंबर में ही भारत ने इस वैश्विक समूह की कमान संभाली है। अध्यक्षता संभालने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र का आह्वान किया। उन्होंने इसके पीछे की संकल्पना का भी उल्लेख किया, कोई विकसित दुनिया और कोई तीसरी दुनिया नहीं और एक विश्व कहने का यही आशय है कि समूची मानवता एक परिवार के रूप में साझा समुद्दिकरण करे और अशक्त पक्ष को एक भविष्य के लिए सहारा देकर सशक्त बनाया जाए। ये सभी बातें तो प्रशंसनीय हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए सवाल उनके फलदारी होने को लेकर जुड़ा है। भूराजनीतिक हलचल, दक्षिणपंथी राजनीति, उद्दंड तानाशाही और आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी दुर्दात चुनौतियां इस राह में कुछ बड़े अवरोध के रूप में दिखती हैं। साथ ही, रुस-यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी का काला साया, जलवायु आपदाएं और भूमंडलीकरण से प्रत्येक स्तर पर विचलन से उपजी बेलगाम महंगाई, ब्याज दरों में तेजी का सिलसिला और नियंत्रण बढ़ती आर्थिक दुश्वारियां स्थिति को और बिगड़ने वाली हैं। संप्रति विश्व समुदाय के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक विमर्श भी आर्थिक वृद्धि के प्रति उदासीनता को दर्शाने वाला है। पिछली सदी के नौवें दशक के मध्य से 2007 के बीच की अवधि को व्यापक सम्भाव का दौर माना जाता है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की ओर उन्मुख हो रही थीं, जिसमें करोड़ों लोगों को भयावह गरीबी और अभावग्रस्तता के दुष्क्रान्ति से बाहर निकाला गया। व्यापक भूराजनीतिक शांति, संयमित राजनीतिक नेतृत्व, कम मुद्रास्फीति, नियन्ती ब्याज दरें, भूमंडलीकरण की गहरी होती पैठ और पूँजी के मुक्त प्रवाह जैसे पहलुओं ने इसमें प्रभावी भूमिका निभाई।

चुनावी वर्ष भी मान सकते हैं। इसी साल लोकसभा चुनाव के रण की तैयारी भी होगी और विभिन्न सूबों में विधानसभा चुनावों का भी तांता लगा रहेगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़ा सूबे उप्र का निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण प्रकरण के बाद काफी अहम और चर्चित हो गया है। ये चुनाव भी 2023 में ही होना है। दिल्ली की कुर्सी समेत सबसे अधिक सूबों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सत्ता है इसलिए अपनी हुक्मतों को बचा पाने के लिए भाजपा के लिए आगामी वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण और सियासी व्यस्तता भरा होगा। कांग्रेस और भाजपा विरोधी तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए 2023 करो या मरो के संघर्ष से भरा होगा। भाजपा जैसे शक्तिशाली दल से लड़ने के लिए आगामी वर्ष में विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास किसी बड़ी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होंगे। विभिन्न

राज्यों के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव के नतीजों की आशंकाएं बताएंगे। मप्र, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में भी 2023 में चुनाव होंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार वापसी का संघर्ष करेगी और मप्र में भाजपा को ये संघर्ष करना होगा। 2018 में मप्र में कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम कांग्रेसी विधायकों की बगावत ने भाजपा सरकार बनवा दी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा सुबा है जहां कांग्रेस ने मजबूती से जीत हासिल की थी और भाजपा की करारी हार हुई थी। 2018 के खंडित जनादेश के बाद कर्नाटक का सियासी नाटक सबको याद होगा। यहां किसी को बहुमत नहीं मिला था। पहले कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने।

फिर बाद में तमाम उठापटक के बाद भाजपा ने कर्नाटक में सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। ऐसे ही देश के कई राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों का कॉकटेल जनाधार विधानसभा चुनावों में ये भी तय करेगा कि किस क्षेत्रीय दल का किस राष्ट्रीय पार्टी से कैसा रिश्ता है! 2023 में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों की बेला में सरकारें जनकल्याणकारी योजनाओं की झड़ी से जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त चुनावी सियासत ध्वनीकरण के प्रयास और भावनात्मक कार्ड खेलने का माहौल भी पैदा कर सकती है। 2023 में ही अयोध्या में निर्माणाधीन राममंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाने की पूरी संभावना है। और 23-24 में बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित राम मंदिर में दर्शन के लिए रामभक्तों का प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त संभावना है कि समान नागरिक कानून पास करवाकर भाजपा चुनावों में लाभ लेने का प्रयास करे। हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दों और ध्वनीकरण की बिसात की काट के बीच पिछड़ा वर्ग, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों का शोर भी 2023 में सुनाई देगा।

### सॉफ्ट पावर दिखाने का बड़ा मौका

2023 में सबसे बड़ा मौका देश में होने वाला जी-20 का आयोजन होगा। अगले साल 9-10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के प्रमुख जुटेंगे। इससे पहले सम्मेलन से जुड़े 200 अलग-अलग आयोजन देश के 50 शहरों में होंगे। भारत के लिए यह मौका पूरे विश्व को अपनी सॉफ्ट पावर से रुक़ू कराने का है। साथ ही, कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत के लिए यह विश्व को अपना स्टैंड दिखाने का मौका है। भारत में जी-20 का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब देश आजादी का 75वां साल मना रहा है। ऐसे में इसका महत्व और बढ़ गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने कौल्ड वॉर के नए सिरे से शुरू होने का संकेत दिया। लेकिन भारत ने पूरे युद्ध के दौरान अपनी तटस्थता बनाए रखी और दोनों पक्षों से युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील भी की। भारत ने सभी मंचों पर स्पष्ट किया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अपने राष्ट्रीय हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। किसी दबाव में स्टैंड नहीं लेगा। शुरू में ऐसी खबरें भी आईं कि भारत के इस रुख को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका या यूरोपीय देशों ने भारत के रुख पर किसी तरह की नेगेटिव टिप्पणी नहीं की।

रूस से कच्चा तेल खरीदने के मसले पर भी भारत ने यूरोपीय देशों को साफ सदेश दिया था कि यह उसका हित है। कई विशेषज्ञों ने भारत के इस रुख पर सवाल भी उठाए, लेकिन अब तक भारत इसमें संतुलन बनाने में सफल रहा है।



### मंदी और महंगाई बड़ी चुनौती

पिछली सदी के आठवें दशक में आप आर्थिक संकट के समय निजी और सार्वजनिक कर्ज आज की तुलना में बहुत कम था। इसलिए सरकारों ने मंदी से उबरने के लिए कर्ज उठाकर खर्च किया। 2008 के वित्तीय संकट के समय महंगाई नहीं थी। इसलिए केंद्रीय बैंकों ने व्याज दरों को शून्य तक लाकर और सरकारी कर्ज यानी बांड खरीदकर पैसे की तंगी दूर की थी, परंतु आज महंगाई पर काबू पाने के लिए बैंकों को व्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं और सरकारें कर्ज के बोझ से इतनी दबी हुई हैं कि और कर्ज लेकर खर्च नहीं कर सकती। यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो लोग सरकारी ऋणपत्र या बांड बेचन लगेंगे। केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए बांड बेच रहे हैं। दोनों तरफ की बांड बिकवाली से व्याज दरें और भी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे महंगाई में उछल आएगा और मंदी का संकट गहराता जाएगा। शेयर बाजारों की हालत भी अच्छी नहीं है। पिछली सदी के आठवें दशक की मंदी के समय कंपनियों के शेयरों के दाम उनकी आमदनी के औसतन आठ गुना थे। आज उनके दाम आमदनी के बीस गुना के पास हैं। इसका खतरा यह है कि महंगाई और मंदी की आहट सुनते ही शेयर बाजारों में हड़कंप मच सकता है और दाम आधे तक हो सकते हैं। रुबीनी की पुस्तक में इसी आर्थिक महासंकट की चेतावनी दी गई है। चीन की अर्थव्यवस्था पर मंदी के साथ-साथ कोविड की लहर ने हमला बोल दिया है। यदि चीन को फिर से बंद हो सकती है। चीन और भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के सप्लाई इंजन हैं और अमेरिका तथा यूरोप मांग के इंजन। यूरोप में मंदी आ चुकी है और अमेरिका में आने के आसार हैं और यदि चीन भी कोविड से ठप हो गया तो भारत कब तक बच पाएगा?

अगले साल इस मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर भारत ऐसा संतुलन बनाए रखने में सफल रहा तो इसके लिए बड़ी कूटनीतिक जीत होगी।

### भारत-चीन संबंधों की दिशा

हाल के वर्षों में भारत-चीन के बीच संबंध उत्तर-चाहूव भरे रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो चीन से संबंध मजबूत करने के कई पहल किए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कम समय में आठ मीटिंग हुईं। लेकिन अचानक पिछले कुछ सालों से चीन से संबंध बद से बदल रहे हैं। दशकों बाद सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी शुरू हुईं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2023 दोनों देशों के बीच संबंधों के आगे का रोडमैप तय करने के लिए सबसे अहम होगा। भारत चीन को

डिप्लोमेसी के स्तर पर अलग-अलग करने की रणनीति पर अधिक भरोसा करता है। जाहिर है यहां से हमारी कूटनीति की बड़ी परख होने वाली है। उधर, चीन सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि इस स्तर पर भी जांचेगा कि भारत को ग्लोबल स्तर पर कितना सोपेर्ट मिलता है। दरअसल, चीन इलाके का महाशक्ति बनना चाहता है। साउथ एशिया में उसने पहले ही अपना रुख दिखा दिया था। उसकी राह-मंशा में भारत सबसे बड़ी बाधा है। जाहिर है ऐसे उलझे हालात में भारत का कूटनीतिक संतुलन भी देखा जा सकता है।

### पड़ोसी देशों से संबंध

कुछ सालों से भारत के पाकिस्तान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों, खासकर नेपाल और बांग्लादेश के साथ उत्तर-चाहूव भरे रिश्ते रहे हैं। पाकिस्तान की तल्खी तो पिछले कई सालों की



कहानी रही है। भारत ने वैसे नेपाल और बांग्लादेश से अपने संबंधों को पहले की तरह बेहतर करने की दिशा में पहल की है। नए साल में पड़ोसी देशों के रिश्ते किस तरह आगे बढ़ते हैं और यह देश के हित में बना रहता है, इस मोर्चे पर भी चुनौती बनी रहेगी। दोनों देशों की अद्वृन्ती राजनीति भी पिछले कुछ समय से उठापटक भरी है। वहां एक बार स्थिति साफ होने के बाद संभवतः अगले साल इस मोर्चे पर स्पष्टता आएगी। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के अनुरूप स्टैंड नहीं लिया। साथ ही, भारत ने व्यापार और दूसरे मोर्चे पर हाल में कुछ कड़े रुख अपनाए। इससे इन देशों से रिश्ते पर असर भी पड़ा। लेकिन यहां भी भारत ने मुद्रा दर मुद्रा कूटनीति को अपने पक्ष में किया। हालांकि, अभी भी दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ लगातार माइंड गेम बाला कूटनीतिक दांव सामने रख रहे हैं। इसकी कई मिसाल अगले साल देखी जा सकती हैं।

### वैश्विक अस्थिरता

वर्ष 2022 समाप्त हो गया है तो इस साल की पड़ताल और नववर्ष से उम्मीदों का आंकलन बहुत स्वाभाविक है। इस साल महामारी से लगभग मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वर्ष बीते-बीते चीन से कुछ खतरनाक संकेत सामने आने लगे हैं। फरवरी में यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के भी वर्षात तक शांत पड़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरण बिगाड़ दिए। वैसे तो वैश्विक घटनाक्रम से भारत का अछूता रह पाना भी असंभव है, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा। इसी साल भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और यह भी एक सुखद संयोग रहा कि इसी वर्ष एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जिसने वर्षों तक भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखा। इसी साल भारत को जी-20

समूह की अध्यक्षता मिली तो अगले साल पूरी दुनिया की निगाहें भी उस पर टिकी रहेंगी कि दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वह कैसे जी-20 समूह को सार्थक नेतृत्व प्रदान कर वैश्विक समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाएगा। इस पहलू का निर्धारण काफी हद तक भारत के अपने प्रदर्शन पर भी निर्भर होगा।

दिसंबर 2022 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। यह इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि बीते आठ वर्षों में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ सहित तमाम नीतियां फलदायी सिद्ध हुई हैं। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के स्तर पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना अनुकूल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। निवेशकों के लिए भारत आकर्षक स्थल बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ‘महामारी, गरीबी और असमानता भारत से मिले साक्ष्य’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सहायता से अत्यधिक गरीबी का स्तर घटकर 0.8 प्रतिशत पर आ गया है।’ यह आंकलन वर्ष 2004-05 से कोरानाकाल वाले 2020-21 के बीच का है। निसंदेह कोरानाकाल में गरीबी घटाने के सरकारी प्रयासों को झटका लगा, किंतु आईएमएफ की रिपोर्ट संकेत करती है कि तालिबांदी से रोजगार छिन जाने और वैस्थापित होकर गांव-देहत पहुंचे कामगार निराश्रित नहीं थे। सरकारी सहायता ने भी उन्हें बड़ा सहारा दिया। यह सहजता से कहा जा सकता है कि घरेलू स्तर पर अपनी नींव सुढ़ा करने के साथ ‘नया भारत’ नववर्ष में वैश्विक कूटनीति के शिखर पर भी होगा। सितंबर 2023 तक भू-राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा से संबंधित संगठन ‘शंघाई सहयोग संगठन’ और शक्तिशाली आर्थिक समूह ‘जी-20’ की नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्षता करेगा। यह हमारे देश की ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी ‘यह युद्ध का दौर नहीं’ वैश्विक विमर्श के केंद्र में रही।

### नया साल 2023 खुशियां लेकर आएगा या मुश्किलें बढ़ाएगा?

नया साल यानी 2023 आ चुका है। इस नए साल में ग्रहों की स्थितियां क्या रहेंगी। देश-विदेश, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा, राजनीति, आर्थिक स्थिति, संस्कृति और खेलकूद के क्षेत्र में कैसा बीतेगा समय। पंडित शरद त्रिपाठी के अनुसार, नए संवत्सर का नाम नल रहगा। इसका राजा बुध और मंत्री शुक्र होगा। राजा और मंत्री में मित्रता होने से सत्ता पक्ष और सरकार के काम आसानी से हो जाएंगे। कुंडली में लग्नेश बुध अष्टम भाव में राहु के साथ है। यह विश्व शाति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरे भाव पर राहु की दुष्टी भी है। इससे विश्व के कुछ देशों की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भारत के पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विश्व में हिंसा होने की आशंका है। कई देशों में सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। आंतकी घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व में व्यापारिक दृष्टि से मंदी तो रहेगी। आम लोगों को खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। भारत में विरोधी दलों का वर्चस्व बनेगा। भारत में कोई विशेष कानूनी व्यवस्था भी लागू हो सकती है। अंक शास्त्र के अनुसार, 2023 का कुल योग सात आता है, जो केतु का अंक है। केतु आधानिकता तो देता है, लेकिन यह वायरस का भी प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कोरोना दोबारा फैल सकता है या उसी तरह की कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। साल 2023 में अनेक बदलाव सभव है। सभी मुरुओं और जीव-जंतुओं को भी लाभ होगा। 2023 में घरेलू स्थितियां अच्छी बनेगी। सभी की सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थेड़ी बढ़ सकती हैं, जैसे- पेट संबंधी समस्या तथा हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। निजी जीवन को लेकर खासा उत्साहित रहेंगे। सुख-सुविधाओं को पूर्ण करने तथा भौतिक वस्तुओं का समावेश करेंगे। 2023 में भारत वर्ष संपूर्ण विश्व में अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके कारण भारत की परंपरा, रीति-रिवाज और संस्कृति को लेकर अनेक कार्य दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राचीन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। संपूर्ण विश्व में भारत का नेतृत्व सराहनीय रहेगा।

**गु**

जरात, उप्र और असम के बाद अब कर्नाटक भाजपा की हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन रही है। टीपू सुल्तान के महिमामंडन का विरोध तो कम से कम एक दशक से अपनी जगह कांग्रेस भाजपा में विवाद का मुद्दा बना ही हुआ है। पिछले दो सालों में भाजपा ने गौ हत्या प्रतिबंध और धर्मातरण पर रोक लगाने के दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। कर्नाटक के गौ हत्या प्रतिबंध कानून की खासियत यह है कि इसमें गाय, बछड़े के साथ-साथ बैल को भी शामिल किया गया है और 13 महीने से कम उम्र के भेंसे को भी शामिल किया गया है। यह इस लिहाज से बाकी राज्यों के कानून से अलग है।

अब विधानसभा चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड और हलाल मीट सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने के बिल पास करवाने की तैयारी चल रही है। धर्मातरण और गौरक्षा कानूनों की तरह ये दोनों बिल भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने और कांग्रेस की मुस्लिम, ईसाई तुष्टिकरण की नीति को चोट करने वाले हैं। कांग्रेस ने पहले पास किए गए दोनों बिलों का भी विरोध किया था और हलाल मीट पर प्रतिबंध का भी कड़ा विरोध कर रही है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर अभी मंथन भी शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा है कि उत्तराखण्ड और मप्र के बिलों का प्रारूप देखने के बाद इस पर काम शुरू होगा। इस बीच 19 दिसंबर को विधानसभा में वीर सावरकर का आदमकद चित्र लगाकर भाजपा ने कर्नाटक में हिंदुत्व की एक लंबी लाईन खींच दी है। जबसे राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई है, वीर सावरकर कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन गए हैं। हालांकि नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने तक वीर सावरकर से नफरत की राजनीति नहीं थी। लेकिन जबसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हुई, तब से हर हिंदूवादी नेता का विरोध शुरू हो गया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर का विरोध कर्नाटक से ही शुरू किया था, जो बाद में महाराष्ट्र पहुंचते-पहुंचते उग्र हो गया था। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को गददार तक कह दिया था। उसी लाईन पर चलते हुए गत दिनों कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ढीके शिव कुमार ने वीर सावरकर को गैर भारतीय तक कह डाला। उन्होंने कहा कि वह न तो कर्नाटक के हैं और न ही भारतीय। इस पर कांग्रेस और भाजपा में काफी तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी, जो कर्नाटक से ही आते हैं, ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा कांग्रेस का आजादी के आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है, यह डुप्लीकेट और नकली कांग्रेस है।

वैसे कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में सिर्फ वीर सावरकर का चित्र ही नहीं लगाया गया है, बल्कि



## हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला

### हलाल पर हर साल विवाद

हलाल मुद्दे पर कर्नाटक में इस साल मार्च में काफी विवाद खड़ा हुआ था। जब कुछ हिंदू संगठनों ने हिंदू त्योहारों के दौरान हलाल मीट का बहिष्कार करने का आव्वान किया था। रविकुमार ने इसे निजी विधेयक के रूप में पेश करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिखा था। हालांकि, अब भाजपा सरकार इसे एक सरकारी विधेयक के रूप में पेश करने की योजना बना रही है। भाजपा के एक अन्य विधायक अरविंद बेलड ने कहा है कि कांग्रेस जो चाही है कह सकती है, लेकिन देश के अधिकांश लोग हलाल में विश्वास नहीं करते हैं।

महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और कर्नाटक के समाज सुधारक बसवन्ना का चित्र भी लगाया गया है। विरोध करने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जगजीवन राम के फोटो लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया, जबकि विधानसभा के अंदर सरदार पटेल का भी चित्र लगाया गया है। वीर सावरकर कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन चुके हैं, तो भाजपा भी जानबूझकर वीर सावरकर को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हिंदुओं में इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे अनजान है, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए सावरकर का विरोध करना कांग्रेस की मजबूरी बन गया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ने भले ही हिंदूचल प्रदेश और गुजरात को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के रूट में शामिल नहीं किया था, लेकिन कर्नाटक को रूट में शामिल किया था। 23 अक्टूबर को राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा

कि भाजपा कर्नाटक को नफरत और कुशासन की प्रयोगशाला बना रही है।

हलाल मीट सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध कर्नाटक में भाजपा का नया आईडिया है। भाजपा के एमएलसी एन रविकुमार ने इस संबंध में फिलहाल प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का नोटिस दिया है, जैसे संसद में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण के प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए हैं, जबकि ये दोनों बिल भाजपा के आधिकारिक एजेंट पर हैं। भाजपा विवादास्पद बिलों को पहले प्राइवेट मेंबर बिलों के रूप में पेश करके बहस शुरू करवाती है, ताकि विपक्ष के तेल और तेल की धार देखी जा सके। एन रविकुमार ने राज्यपाल से जिस बिल को पेश करने की इजाजत मांगी है, उसमें कहा गया है कि हलाल सर्टिफिकेट को गैर कानूनी घोषित किया जाए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अलावा किसी अन्य संगठन की ओर से जारी खाद्य सर्टिफिकेट पर रोक लगाई जाए। हलाल सर्टिफिकेट निजी मुस्लिम संगठन की ओर से जारी किया जाता है। हलाल सामग्री बेचने वाले को इसकी फीस चुकानी होती है, जो वह हर हलाल सर्टिफिकेट के हिसाब से अदा करता है। सर्टिफिकेट देने वाले हलाल संगठन उस फीस का इस्तेमाल मुस्लिम धर्म प्रचार और धर्मातरण करवाने के लिए करते हैं। लेकिन हलाल मीट गैर मुस्लिमों को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। इस संबंध में इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। एक छात्र ने यह याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि देश की 85 फीसदी आबादी को उनकी इच्छा के खिलाफ हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सर्टिफिकेट निजी संस्थाएं जारी करती हैं इसलिए इस पर पांचदी लगनी चाहिए। याचिका दाखिल करते हुए वकील विधेय आनंद ने कहा था कि एक धर्म निरपेक्ष देश में किसी एक धर्म की मान्यताओं और विश्वास को, दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। यह गैर-मुस्लिमों के मूल अधिकारों का हनन है।

● राजेश बोरकर

प्र

धानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जीत को राष्ट्रीय जीत बता रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की हार को भूलकर गुजरात की जीत का जश्न मनाया। सबाल यह है कि क्या यह जश्न 2023 की चुनौतियों को छोटा करके आंकना नहीं है। 2023 की चुनौतियां 2022 से भी

ज्यादा गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजों ने भाजपा को चेतावनी दी है, लेकिन उस चेतावनी को सही अर्थों में पढ़ने की बजाय, भाजपा गुजरात के जश्न में डूब गई।

गुजरात ने 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने का संकल्प लिया है, लेकिन

यह संदेश राज्यों की सरकारों के लिए नहीं है।

भाजपा को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के संदेश को पढ़ने की जरूरत है। ये संदेश कुछ-कुछ 2018 जैसे ही संदेश हैं, तब राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने संदेश दिया था। 2019 में अगर मोदी सरकार पुलवामा के जवाब में पाकिस्तान के भीतर

घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती तो भाजपा को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले तक भाजपा को 200 के करीब सीटें मिलने का आंकलन आ रहा था। 26 फरवरी के सर्जिकल स्ट्राइक ने सारी स्थिति ही बदल दी थी।

हालांकि 2024 से पहले क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। 2018 वाले संकेत फिर मिलने शुरू हो गए हैं, हालांकि हमें 2023 का इंतजार करना होगा। जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मप्र, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के चुनाव होंगे। इस समय मप्र, कर्नाटक, त्रिपुरा में भाजपा सरकारें हैं। वैसे पूर्वोंतर के चारों ही राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने और हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस में नए जोश का संचार हुआ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में आज का राजनीतिक परिदृश्य लगभग हिमाचल जैसा ही है। कर्नाटक और मप्र की तरह कांग्रेस शासित इन दोनों राज्यों में भाजपा-कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी। यानी

## भाजपा के सामने 2023 की चुनौतियां गंभीर...

**2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा और एमसीडी में हार के बाद 2023 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के सामने कड़ी चुनौती रहने वाली है। 2023 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं।**



### राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा आगे

भाजपा को भले ही राज्यों के चुनाव में कुछ चुनौती मिल रही हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह प्रतिद्वंद्वी दलों से खासी आगे है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के साथ ही आप के रूप में उसके लिए एक नई चुनौती उभर रही है, जिससे भाजपा विरोधी मतों में बिखराव संभव है, जैसा गुजरात में हुआ। वहीं, हिमाचल के चुनावी रण से अतिम क्षणों में किनारा करके पलायन कर गई आप के बाद भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें बेहद करीबी संघर्ष में भाजपा जीतते-जीतते भी हार गई। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बहुत कुछ इस पर निर्भर करते हैं कि आप और कांग्रेस में राजनीतिक संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा या फिर उनमें संघर्ष विराम हो जाएगा। यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आप अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का रास्ता काटती है या नहीं। हालांकि, आप की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए लगता नहीं कि वह कांग्रेस के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की राह पर बढ़ेगी।

भाजपा और कांग्रेस शासित दो-दो राज्यों में कड़ी टक्कर होगी। हार या जीत कुछ भी हो सकता है। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती कर्नाटक, मप्र और त्रिपुरा सरकारों को बचाने की है। भाजपा ये तीनों राज्य बचाने के साथ अगर कांग्रेस से राजस्थान या छत्तीसगढ़ में से एक राज्य भी छीन लेती है, तो 2024 का उसका रास्ता साफ होगा।

तेलंगाना में दिल्ली और बंगाल जैसी राजनीतिक लड़ाई होगी, जहां अभी से शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। जिस तरह बंगाल विधानसभा चुनावों और दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले सीबीआई और ईडी ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर

शिकंजा कसना शुरू किया था, उसी तरह अब तेलंगाना में शुरू हो चुका है।

दिल्ली के शाराब घोटाले में मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और एमएलसी कविता का नाम आया है, सीबीआई और ईडी ने उन्हें तलब भी किया है। ईडी की रिमांड रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद कविता ने कहा कि चुनावों से पहले

तेलंगाना में भी वही हो रहा है, जो बंगाल और दिल्ली में हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ईडी आती है।

बंगाल और दिल्ली में सीबीआई और ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारियों का भाजपा को राजनीतिक फायदा नहीं हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ईडी के अधिकारियों के एक सम्मेलन में आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई की खुली छूट देते हुए कहा था कि जब राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, लेकिन उन्हें बिना उसकी परवाह किए अपना काम करते रहना है।

जब चुनाव वाले राज्य में सीबीआई और ईडी भाजपा विरोधी दलों के नेताओं पर कार्रवाई करती है, तो उसे राजनीतिक विद्रोष ही माना जाता है। इसलिए अच्छा हो कि सीबीआई और ईडी के लिए भी कोई मर्यादा तय हो। जैसे विधानसभा और लोकसभा की सीट खाली होने पर आखिरी छह महीनों में चुनाव नहीं होते, उसी तरह सीबीआई और ईडी को भी चुनाव वाले राज्य में आखिरी छह महीने पहले मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के खिलाफ अपना काम बंद



### भाजपा से जाट छिटके, अब जाटव पर अटके

उप विधानसभा चुनाव में पराजय से हताश-निराश सपा-रालोद गठबंधन को खत्तौली की जीत ने संजीवनी दे दी है। खासकर, जब जाट और दलित वोट भाजपा की बजाय रालोद प्रत्याशी को मिला है। सपा गठबंधन को लगने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह एक दशक से उपर में चले आ रहे भाजपा के विजय अभियान की लगाम थामकर उसे केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकता है। यह भरोसा अकारण नहीं है। दलित नेता चंद्रशेखर रावण के प्रभाव में जिस तरह पश्चिमी उप्र के दलितों के बड़े वर्गों ने सपा-रालोद गठबंधन को वोट किया है, वह ट्रेड लोकसभा चुनाव में आशिक भी बना रहा तो यह समीकरण पश्चिमी उप्र की एक दर्जन सीटों पर असरकारी प्रभाव डालेगा, जिसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। विशेषकर सहारनपुर और मेरठ मंडल की सीटों पर जहां चंद्रशेखर का खासा प्रभाव है। पश्चिमी उप्र में आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ मंडल में गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सिकरी सीट आती हैं। इस बेल्ट की सभी तरह सीटों पर दलित खासकर जाटव वोट निर्णयिक भूमिका अदा करता है। जाटव मतदाताओं की बदौलत ही बसपा पश्चिमी उप्र में लंबे समय तक मजबूत ताकत बनी रही।

कर देना चाहिए, ताकि उसके दुरुपयोग के आरोप न लगें।

तेलंगाना में हाल ही में हुए एक उपचुनाव में जिस तरह टीआरएस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप, छापेमारी, गिरफ्तारियों के नाटक हुए, वह एक संकेत है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा। क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया था, इसलिए वह राज्य को अपनी पारिवारिक संपत्ति समझते हैं। वह अपने सरकारी आवास से ही सरकार चलाते हैं, सचिवालय जाते ही नहीं। राजनीतिक विरोधियों के साथ उनका व्यवहार दुश्मनों जैसा होता है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने जा रही आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी की कार को हैदराबाद पुलिस की क्रेन घसीटकर थाने ले गई थी, जबकि वह खुद कार में बैठी थी। पुलिस ने कार में बैठी शर्मिला को कार समेत हिरासत में ले लिया। शर्मिला रेड्डी टीआरएस सरकार के खिलाफ प्रदेश में पदयात्रा कर रही हैं। वह

जहां भी जाती है, टीआरएस के कार्यकर्ता उनकी यात्रा में बाधा बनते हैं, अब पुलिस प्रशासन ने उन्हें पदयात्रा की इजाजत ही नहीं दी है। यह एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जो तेलंगाना में चल रही तानाशाही के सबूत देती हैं। इसलिए तेलंगाना की राजनीतिक लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है।

हिमाचल और दिल्ली से संदेश है कि भाजपा को भी अपने क्षत्रियों को मजबूत करना पड़ेगा, या मजबूत क्षत्रियों के हाथ में सत्ता और संगठन सौंपना पड़ेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का राज्य के साथ जुड़ाव, गुजराती अस्मिता, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का मुद्दा केंद्र में रहा। दूसरी ओर, हिमाचल में आप के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाना दर्शाता है कि देश के सभी हिस्सों में आप का दिल्ली या पंजाब वाला दांव इतनी आसानी से फलीभूत नहीं हो सकता। उसे इसके लिए जमीन पर लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। हालांकि, गुजरात में जिस प्रकार आप का खाता खुला है और उसने अपनी मौजूदगी दिखाई दी है, उससे वह एक राष्ट्रीय दल बनने की राह पर बढ़ गई है। इस तरह से भी इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में महत्व और बढ़ गया है।

● विपिन कंधारी

दायरा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल, जहां भाजपा को विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली में जहां भाजपा को नगर निगम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, इन दोनों राज्यों में 11 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में सभी 11 सीटें भाजपा जीती थी, लेकिन हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई थी। मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव का नतीजा भाजपा के लिए एक संकेत और संदेश था कि उसे मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले से ही विधायक थे।

हालिया चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों के लिए कुछ खट्टे-मीठे अनुभव वाले रहे। राजनीतिक दल अमूमन मीठे अनुभवों को तो बहुत सहजता से लेते हैं, लेकिन खट्टे अनुभव में छिपी सीख को अनदेखा करते हैं। चूंकि आगामी आम चुनाव में बमुश्किल 16 से 18 महीने का समय शेष है और उससे पहले कई राज्यों में नियमित अंतराल पर चुनाव होने हैं तो इस जनादेश के गहरे निहितार्थ हैं। अगले साल की पहली छमाही में कर्नाटक के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव होने हैं तो दूसरी छमाही में राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे। फिर 2024 में लोकसभा के साथ-साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को गुजरात-हिमाचल के नतीजों की थाह लेकर आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। जहां तक राज्यों की बात है तो उनका गणित अलग है। वहां पार्टीयों का राज्य स्तरीय नेतृत्व और सांगठनिक क्षमताओं जैसे अलग-अलग मुद्दे हावी रहेंगे, जिस कारण किसी एक दल का पूर्ण वर्चस्व मुश्किल दिखता है। हिमाचल इसका ताजा उदाहरण है, जहां भाजपा मामूली अंतर से चुनाव हार गई। वहां उसका डबल इंजन का दांव कारगर नहीं रहा, क्योंकि स्थानीय पहलू हावी रहे। वहीं गुजरात का चुनाव राज्य से अधिक राष्ट्रीय विमर्श के आधार पर लड़ा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य के साथ जुड़ाव, गुजराती अस्मिता, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का मुद्दा केंद्र में रहा। दूसरी ओर, हिमाचल में आप के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाना दर्शाता है कि देश के सभी हिस्सों में आप का दिल्ली या पंजाब वाला दांव इतनी आसानी से फलीभूत नहीं हो सकता। उसे इसके लिए जमीन पर लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। हालांकि, गुजरात में जिस प्रकार आप का खाता खुला है और उसने अपनी मौजूदगी दिखाई दी है, उससे वह एक राष्ट्रीय दल बनने की राह पर बढ़ गई है। इस तरह से भी इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में महत्व और बढ़ गया है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय उत्तर-चंद्राव के दौर से गुजर रही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जो कभी भी तनकर खड़ी हो सकती है। इसलिए नेहरू-गांधी परिवार हार मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेस को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने हिमाचल में सरकार बनाकर अपना लोहा मनवा दिया है।

**प्रि**

यंका गांधी ने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी और सक्रिय राजनीति की शुरुआत भी उप्र से की थी। प्रियंका गांधी वाड़ा वैसे तो बचपन से ही परिवार के साथ चुनावी कैंपेन के दौरान रायबरेली और अमेठी जाती रहीं, लेकिन कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद पहली बार पूर्वी उप्र की चुनाव प्रभारी बनाइ गई थीं और पहली बार में ही बहुत बड़ा झटका लगा। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की हार किसी सदमे से कम नहीं थी। और उप्र चुनाव 2022 के नतीजों ने तो जैसे किर से जख्म हरे कर दिए थे। महिला उम्मीदवारों को 40 फोसदी टिकट देने के बावजूद कांग्रेस को चुनावों में सिर्फ दो सीटें ही मिल सकीं। जैसे उप्र चुनाव में प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी को कांग्रेस के मंच से पहली बार अहमदाबाद की रैली में महासचिव के रूप में बोलने का मौका मिल पाया था, ठीक वैसे ही उप्र से बाहर ही पहली बार जीत का जायका महसूस करने का मौका हिमाचल प्रदेश जाकर मिला है। ये खुशी इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि शिमला के पास ही प्रियंका गांधी वाड़ा ने अपना घर भी बनवाया है।

हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी एक तरीके से प्रियंका गांधी के ही कंधों पर देखी गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तो उधर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई थी। गुजरात में तो एक दिन के लिए वो आदिवासी नेता अनंत पटेल के बुलावे पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए गए थीं। ऐसे भी समझा जा सकता है कि अमेठी में राहुल गांधी की हार का दर्द थोड़ा कम हुआ होगा। वैसे भी बड़े दिनों बाद कांग्रेस को अकेले भोगने वाली कोई खुशी मिली है। पीछे देखें तो 2021 में प्रियंका गांधी ने असम चुनाव में भी चुनाव कैंपेन का मौर्चा संभाला था, लेकिन मायूसी ही हाथ लागी थी। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश की जीत का श्रेय मिलेगा या भारत जोड़ो यात्रा का असर बताकर ये जीत भी राहुल गांधी को समर्पित कर दी जाएगी?

प्रियंका गांधी वाड़ा का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। वायरल तो राहुल गांधी के भी कई वीडियो हुए हैं। नेपाल वाले से लेकर तेलंगाना दौरे तक, जिसमें वो पूछते हैं— बोलना क्या है? राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहीं प्रियंका गांधी वाड़ा का वायरल वीडियो उनकी फिटनेस का सबूत है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को कई बार दौड़ते देखा गया है। और ये



## प्रियंका गांधी का बढ़ता दबदबा!

### पहले संकटमोचक, अब फाइनल अथॉरिटी

पहले तो प्रियंका गांधी की भूमिका सिर्फ संकटमोचक तक सिमटी रहती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद वो भी फाइनल अथॉरिटी की ही तरह नजर आने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंद सिंह सुखखू का मुख्यमंत्री बनना भी इसी बात की मिसाल है। अबल तो बतौर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे को ही तमाम फैसलों के लिए अथॉरिटी लेटर मिला हुआ है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही होते हैं। अब तो लगता है प्रियंका गांधी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। कांग्रेसी सुखविंद सिंह सुखखू के अपने दो प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ने की वजह प्रियंका गांधी के साथ उनका पुराना संबंध मानते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद प्रतिभा सिंह के अलावा मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, लेकिन सुखखू बाजी मार ले गए।

बाकी कांग्रेस नेताओं को मुश्किल में डाल देता है। करेल विधानसभा चुनाव के दौरान तो नाव से नदी और पानी से नाव पर उछलते-कूदते राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करने की तो कांग्रेस नेताओं में होड़ ही मची हुई थी। पुशअप चैलेंज लेते तो राहुल गांधी को पहले भी देखा गया था,

करेल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं के दिखाने पर लोगों ने उनके सिक्स पैक्स भी देख लिए और प्रियंका गांधी भी जाताने लगी हैं कि वो भी किसी से कम नहीं हैं।

वैसे भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवा देने के बाद प्रियंका गांधी का कद भी तो बढ़ ही गया है। जैसे 2018 में राहुल गांधी ने मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के हाथ से सत्ता छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। प्रियंका गांधी ने भी तो हिमाचल प्रदेश में वैसा ही काम किया है। स्कोर की बात करें तो प्रियंका गांधी का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी से थोड़ा ही कम लगता है। राहुल गांधी ने 5 विधानसभा चुनावों में से तीन जीते थे, प्रियंका गांधी के केस में 50-50 का मामला दिखाई पड़ता है। बाकी बातों का नंबर तो बाद में आएगा, हिमाचल प्रदेश की जीत से प्रियंका गांधी ने नाकामी के दाग तो धो ही डाले हैं। अमेठी लोकसभा से लेकर उपरिधानसभा चुनाव 2022 तक, हार का सिलसिला तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।

कहां प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती रही, और कहां वो हर मामले में फेल होने लगीं। चुनाव जीतने की कौन कहे, जिन मामलों में उनको संकटमोचक के तौर पर तारीफ मिलती, आगे चलकर वे और भी उलझ जाते और बड़ी मुसीबत बनकर सामने आते। मप्र और राजस्थान में मुख्यमंत्री विवाद को प्रियंका गांधी ने ही सुलझाया था। कमलनाथ तो सत्ता से ही हाथ धो बैठे, राजस्थान का हाल सब देख ही रहे हैं। धीरे-धीरे राहुल गांधी को आउटडेट और प्रियंका गांधी वाड़ा को लोग ओवररेटेड बताने लगे थे और ज्यादा दिन नहीं हुए, ये तो भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले की

ही बात है। लेकिन लगता है यह यात्रा भाई-बहन दोनों के अच्छे दिनों की तरफ इशारे करने लगी है।

राहुल गांधी को पहले के मुकाबले काफी मैच्योर माना जाने लगा है। और मीडिया के सवाल को टालते हुए वो खुद को समझदार बताने भी लगे हैं। भारत जोड़े यात्रा के दौरान प्रेस कांग्रेस में जब सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने 2024 के आम चुनाव को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी का ऐसा ही रिएक्शन था। भारत जोड़े यात्रा और हिमाचल प्रदेश चुनाव का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश चुनाव तो अपने तय समय पर होना ही था, और भारत जोड़े यात्रा के रूट में तो हिमाचल प्रदेश है भी नहीं, लेकिन ये भी है कि कांग्रेस की भारत जोड़े यात्रा के दौरान भी प्रियंका गांधी के हाथ हिमाचल प्रदेश की सफलता लगी है।

ऐसा भी कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जीत से कांग्रेस को प्रियंका गांधी का गुम हुआ टैलेंड वापस मिल गया है और प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में हिस्सेदारी की संभावना काफी बढ़ गई है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़े के कामकाज संभाल लेने के बाद प्रियंका गांधी ने नए सिरे से राहत भरी दस्तक दी है। सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश चुनाव के जरिए एक बेहतरीन टीम भी मिल गई है और उनकी टीम में सचिन पायलट का होना कांग्रेस में नए समीकरणों के बनने और बिंगड़ने की तरफ इशारे भी कर रहा है।

प्रियंका गांधी की टीम तो पहले से ही बन चुकी थी। लेकिन 2019 में जैसे उनको औपचारिक तौर पर कांग्रेस में जिम्मेदारी मिली, प्रियंका गांधी वाड़ा को भी बाकायदा काम करने के लिए एक टीम मिल गई। 2019 के बाद काफी लोग हटाए भी गए, और बहुतों को मौका भी दिया गया और फिर 2022 का उप्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी ने काफी ठोक बजाकर अपनी एक टीम बनाई। कई पुराने नेताओं में उनकी चयन प्रक्रिया को लेकर नाराजगी भी देखी गई। उप्र की तो प्रियंका गांधी खुद प्रभारी रहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो लगता है जैसे बस भेज दिया गया। चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी के गुजरात में भी गरबा से लेकर रोड शो तक के प्रोग्राम बताए गए थे, लेकिन वो गई नहीं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन के लिए राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया था।

प्रियंका गांधी के हिमाचल जाने और वहां जमे रहने में मशोबरा में बना उनका डेरा भी रहा। मशोबरा शिमला के पास ही है और चुनावों के दौरान ज्यादातर वक्त प्रियंका गांधी ने वहाँ से पूरे कैपेन की निगरानी की थी। प्रियंका गांधी ने बहुत रैलियां तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही जानी थी, मौका निकालकर कहा जरूर। खासतौर पर भाजपा के खिलाफ। अपनी रैलियों में प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और नौकरियों से लेकर पेंशन तक के मामले उठाए और असर तो सबने देखा ही। प्रियंका गांधी के हिमाचल पहुंचने के काफी

पहले से ही चुनाव प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ग्राउंड लेवल पर काफी काम कर चुके थे। क्रिकेट पॉलिटिक्स और चुनावी राजनीति में बहुत फर्क होता है, ये बात राजीव शुक्ला पहले से ही जानते थे, लेकिन वीरभद्र सिंह के दबदबे वाले हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के समने वैसी ही चुनौतियां रहीं जैसी बाकी राज्यों में होती हैं, लिहाजा राजीव शुक्ला ने सबसे पहले गुटबाजी पर ही कैंची चलाई।

राजीव शुक्ला की सलाह पर कुलदीप सिंह राठौर की जगह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को दे दी गई और दूसरे गुट

को बैलेंस करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। जो बाकी बचे नेता थे, राजीव शुक्ला ने उनको भी किसी न किसी काम में उलझाए रखा। 2021 में मंडी लोकसभा उपचुनाव और तीन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत उत्साह बढ़ाने वाली तो थी ही, प्रियंका गांधी के पहुंच जाने से राजीव शुक्ला के लिए काम करना

सुविधाजनक हो गया।

अब तो राजीव शुक्ला को भी इनाम मिलने की संभावना जारी हो रही है। ये भी हो सकता है उनको किसी और महत्वपूर्ण राज्य की चुनावी जिम्मेदारी दी जाए। सबसे अहम बात ये है कि राजीव शुक्ला के रूप में प्रियंका गांधी को जंग जीतने के लिए एक बढ़िया जनरल मिल गया है। आने वाले दिनों में एक को तरकी मिलती है, तो दूसरे की अपने आप होनी है। राजीव शुक्ला के साथ ही सचिन पायलट की हिमाचल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सचिन पायलट तो प्रियंका गांधी के साथ उप्र विधानसभा चुनाव में भी लगे रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश का मामला ऐसे वक्त का है जब एक छोटी सी कामयाबी भी उनकी सीधी मजबूत करने वाली है।

दोनों के अलावा दो और भी कांग्रेस नेता रहे जो प्रियंका गांधी के साथ मोर्चे पर डटे रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी प्रियंका गांधी की टीम का मजबूत खंभा होंगे। बताते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रियंका गांधी के मशोबरा में घर बनाने के दौरान उनकी काफी मदद की थी। ऐसे समझ सकते हैं कि रास्ते में आने वाली हर अड्डेन को खत्म ही कर दिया था। भला वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कौन बनता।

● इन्द्र कुमार



## कांग्रेस के लिए जिंदा रहना भर जरूरी है

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में आना ही नहीं, गुजरात में भी एक दर्जन से ज्यादा सीटें मिलने को भी एक ही तरह की पॉलिटिकल लाइन के तौर पर समझा जा सकता है। कांग्रेस का जिंदा रहना ही काफी है। जैसे भी संभव हो, कांग्रेस बची रही तो उसे सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो जहां कहीं भी भाजपा नहीं जीत पाई है, कांग्रेस ने मौके का फायदा उठा लिया है। ये बात गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही चुनावों पर बराबर लागू होती है। गुजरात के कुछ ही क्षेत्रों में ये हाल रहा कि इलाके के लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसे ज्यादा इलाके रहे जहां के लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी रही, या फिर भाजपा नेता आपस में लड़ते रहे और कांग्रेस को उसका सीधा फायदा मिल गया। मतलब, देर तो है, लेकिन हमेशा अंधेरा छाया रहेगा ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस अगर खत्म नहीं हुई तो कभी भी एक हरे-भरे पौधे की तरह उग सकती है और मतलब ये भी कि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का मिशन अभी अधूरा है। मौका मिलते ही कांग्रेस भाजपा को भी रिप्लेस कर सकती है।

**छ** तीसगढ़ की सियासत में जय-वीरु की जोड़ी के नाम से पहचाने जाने वाले टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच की तल्खी बार-बार सामने आती रही है। अब टीएस सिंहदेव ने कहा है कि

वे चुनाव आने तक अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। अभी कुछ सोचा नहीं है। मजाक में यह भी कह दिया कि अब बात तो रिटायरमेंट की हो रही है। सिंहदेव गत दिनों सूरजपुर पहुंचे थे। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से पत्रकारों ने अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। नई जवाबदेही के संबंध में मजाकिया लहजे में कहा कि नई जिम्मेदारी की बात हो रही है या रिटायरमेंट की। यह भी कहा कि प्रदेश के 20 हजार गांवों में से सवा सौ गांवों में अभी सड़क नहीं बन सकी है।

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच ढाई-ढाई साल का चर्चित फॉर्मूला खटास का मुख्य कारण बना। टीएस सिंहदेव ने सरकार के साढ़े तीन साल गुजर जाने के बाद खुले तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस हाईकमान को अब निर्णय ले लेना चाहिए। सिंहदेव ने कभी भी ढाई-ढाई साल के सीएम के फॉर्मूले को नहीं नकारा। इससे स्पष्ट है कि ऐसा फॉर्मूला था जरूर, जो अमल में नहीं आया। दोनों के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई कि 16 जुलाई को सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए कह दिया था कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। फिलहाल वे कांग्रेस में ही रह गए, लेकिन जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। सिंहदेव ने चार पन्नों के इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि पंचायत विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जाता रहा है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिंहदेव की न सिर्फ अहम भूमिका रही, बल्कि वे कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद से उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई। साल 1952 में जन्मे टीएस सिंहदेव अब 70 वर्ष के हो चुके हैं। उनके पिता एमएस सिंहदेव अविभाजित मप्र के मुख्य सचिव व योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव अर्जुन सिंह और प्रकाश सिंह सेठी मंत्रिमंडल में मंत्री रहीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद वे अंबिकापुर से विधायक बने।

सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि सरकार बर्नीं तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे। अब हालात ये हैं कि उन्हें कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि सरकार में उनकी नहीं चल रही है। यह सबसे विषम परिस्थिति है। इससे

# बढ़ी जय-वीरु की दूरियां...



## पार्टी छोड़ेंगे या फिर सन्यास

इसके बावजूद सिंहदेव बार-बार यही कहते रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ चाहिए। हालांकि सिंहदेव यह भी कहते रहे हैं कि वे भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठाता है कि क्या वे आम आदमी पार्टी में जाएंगे या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर चुनाव नहीं लड़ने या राजनीति से संन्यास लेने का फैसला लेंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना तो तय है कि सिंहदेव का यह बयान छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा भूयात ला सकता है। पिछले साल अगस्त में बघेल-सिंहदेव के झगड़े के बीच दोनों नेताओं (बघेल के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होने पर) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के नेतृत्व द्वारा दिल्ली बुलाए जाने पर दोनों नेता विधायकों, महापौरों और सहयोगियों के एक दल के साथ दिल्ली पहुंचे थे। टीएस सिंहदेव तब दिल्ली भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश करने के लिए पार्टी नेतृत्व से मिले थे। अब कांग्रेस को डर है कि कहीं दोनों नेताओं के झगड़े के बीच सरकार पर संकट न आ जाए और सरकार गिर न जाए। कांग्रेस के पास अब अपने दम पर केवल दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सरकार बची है।

माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव अपने भविष्य को लेकर चुनाव के पूर्व कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और यह फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है।

मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है और भूपेश ने भी इस बात को कहा है कि फैसला हाईकमान के ऊपर रहता है वह जैसा निर्णय करें हम या भूपेश या दूसरा तीसरा कोई भी अपने से मुख्यमंत्री नहीं बनता ना ही बन सकता है। किसी भी दल में वह हमारी प्रक्रिया

होती है एक प्रोटोकॉल है उसके नाते तय होता है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। यह एक अलग बात होगी कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। सिंहदेव ने उनके बयान पर चुटकी ले रही भाजपा को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले इसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं उन्हें लगता है कि कहीं आग लगी है हवा दे दो उनको इन सबसे परहेज कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए भाजपा अपने काम को देखें और अपने काम को मजबूत करें। पिछली बार जो अप्रत्याशित स्थिति हुई उनके 15 विधायक ही जीत कर आ सके मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा आज तो 14 विधायक ही बचे हैं इस स्थिति में उनका पूरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए ना कि दूसरों के घर में। मैं तो सिर्फ उन्हें सलाह दे सकता हूं बाकी उनकी जैसी इच्छा।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जब सवाल पूछा गया तब मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी चुनाव लड़ने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से पूछत हैं बाबा साहब (टीएस सिंहदेव) ने गलत क्या कहा है। मैं भी चुनाव लड़ लूंगा तब अपने कार्यकर्ताओं से पूछ लूंगा कि चुनाव लड़ूं या नहीं सहयोग दोगे या नहीं। यह बहुत स्वाभाविक बात है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरगुजा के सूरजपुर में विरष्ट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है। सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। इसके पहले भी सरकार के विरष्ट मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुली तौर पर आलोचना की है जो इस बात का उदाहरण है कि रिस्थित क्या है। सिंहदेव के बयान से यहां खुले संकेत मिल गए हैं कि कांग्रेस में 2023 विधानसभा चुनाव के पहले क्या होने वाला है।

● रायपुर से टीपी सिंह

**म** हाराष्ट्र की राजनीति में शह-मात का खेल तेज होने लगा है। ये बीएमसी चुनावों की नजदीक आ रही तारीख की बजह से भी हो सकता है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा विपक्ष के निशाने पर हैं।

ये सिलसिला तो शिवसेना में बगावत और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी को लेकर हाल के गवर्नर भगत सिंह कोशयारी के बयान ने आग में धी का काम किया है और अब तो उनको हटाए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। राज्यपाल को हटाने सहित कई मांगों को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आधाड़ी के नेताओं ने हल्ला बोल मार्च भी निकाला है और रैली भी हुई है। रैली में उद्घव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ-साथ एनसीपी नेता शरद पवार और अजीत पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेले के अलावा कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता पहुंचे थे।

एमवीएम के मार्च और रैली को काउंटर करने के मकसद से भाजपा की तरफ से माफी मांगो प्रदर्शन भी किया गया। ये लोग संजय राउत और एक अन्य शिवसेना नेता के बयानों को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। बाकी चीजें तो वहीं रहीं जो काफी दिनों से देखने को मिल रही हैं, महाविकास आधाड़ी के हल्ला बोल में बस एक ही नई बात थी और वो थी, रश्म ठाकरे की मौजूदगी। रश्म ठाकरे, उद्घव ठाकरे की पत्नी हैं और आदित्य ठाकरे की मां। ऐसे भी कह सकते हैं कि उद्घव ठाकरे पूरे परिवार के साथ सङ्क पर उतरे थे। रश्म ठाकरे की ये मौजूदगी भी महज रस्मअदायी जैसी नहीं थी, बल्कि कई जगह तो वो आगे-आगे नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौर्चा संभाल रही हों। बालासाहेब ठाकरे की बढ़ का सङ्क पर उतरकर भाजपा और शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये हल्ला बोल महाराष्ट्र की राजनीति में खास असर दिखाने वाला है या उद्घव ठाकरे की तरफ से पार्टी को बचाने के लिए ये आखिरी दंव आजमाया जा रहा है?

पूरा ठाकरे परिवार तो नहीं, लेकिन मातोश्री के तीनों जाने पहचाने चेहरे एकसाथ सङ्क पर नजर आए तो आसपास की नजरों का एक तरफ फोकस हो जाना भी स्वाभाविक ही था और उसमें मेन फोकस रश्म ठाकरे रहीं। ऐसा भी नहीं कि रश्म ठाकरे को पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में देखा गया हो। उद्घव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी रश्म ठाकरे को खासा एक्टिव देखा गया है। अपनी तरफ से एकनाथ शिंदे को धेरने के लिए रश्म ठाकरे ने भी कम कोशिशें नहीं की है। बहरहाल,

## रश्म ठाकरे मोर्चे पर...



### हल्ला बोल की जरूरत क्यों?

हाल फिलहाल तो महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर ही राजनीति काफी उबल रही है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर अमित शाह को सामने आकर संयम बनाए रखने की अपील करनी पड़ी है और इसकी एक बड़ी बजह कर्नाटक में भाजपा और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार होना भी है। महाराष्ट्र में विपक्ष ज्योतिबा

फुले और सावित्री बाई फुले को लेकर अपमान जनक टिप्पणियों का विरोध कर रहा है और छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी के बयान को लेकर उनको जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है। दरअसल, 9 नवंबर, 2022 को औरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी ने छत्रपति शिवाजी को गुजरे जमाने का हीरो बता डाला था। भगत सिंह कोशयारी ने छत्रपति शिवाजी की तुलना में नितन गडकरी को नए जमाने का हीरो बता दिया। भगत सिंह कोशयारी का कहना था, स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे पूछते थे कि आपके पसंदीदा नेता कौन हैं? हम अपनी पसंद से सुधार चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नाम लेते थे... आज अगर आपसे कोई पूछते कि आपके पसंदीदा नेता कौन हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है... महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे... शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात कर रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर से लेकर नितन गडकरी तक यहीं मिल जाएंगे।

महाविकास आधाड़ी का हल्ला बोल मार्च जब जेजे अस्पताल के पास से शुरू हुआ तो उद्घव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्म ठाकरे साथ ही निकले। मार्च के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचते-पहुंचते रश्म ठाकरे को कई बार आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाले अंदाज में भी देखा गया।

रश्म ठाकरे के पीछे-पीछे सैकड़ों महिलाएं भी चल रही थीं। ध्यान देने वाली बात ये रही कि रश्म ठाकरे ने न तो बाकी नेताओं के साथ कोई भाषण दिया, न ही मीडिया से कोई अलग से ही

बात की, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान हर निगाह उनके ईर्द-गिर्द ही टिकी रही। कहते हैं कि उद्घव ठाकरे के सामने मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव एनसीपी नेता शरद पवार ने रखा था, लेकिन मानसिक तौर पर तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका रश्म ठाकरे की ही रही। बीच में जब उद्घव ठाकरे बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो रश्म ठाकरे को खुद कमान संभालनी पड़ी थी।

उद्घव ठाकरे तो बीमार थे और आदित्य ठाकरे बच्चे, लेकिन सत्ता के केंद्र में रहकर भी रश्म ठाकरे को शिवसेना में चल रही बगावत की भनक तक क्यों नहीं लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि, एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र छोड़कर असम पहुंच जाने के बाद रश्म ठाकरे ने अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। जब उद्घव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से कुछ नहीं हो पा रहा था तो रश्म ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन जब सामने सत्ता का लालच हो तो भला पुराने संबंध और दोस्ती राजनीति में मायने रखती है क्या? शिवसेना के बंट जाने और हाथ से सत्ता फिसल जाने के बाद से रश्म ठाकरे को हर मौके पर मजबूती से ढटे हुए देखा गया है लेकिन हल्ला बोल रैली में जिस तरह वो सङ्क पर निकली हैं, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सितंबर, 2022 में जब नवारात्र के दौरान देवी दुर्गा के पंडल जगह-जगह लगे थे और वे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगे थे, तभी रश्म ठाकरे भी ठाणे पहुंची थीं। ठाणे से ही एकनाथ शिंदे आते हैं और उसे शिवसेना का पुराना गढ़ माना जाता है। शिवसेना के बड़े कददावर और सम्मानित नेता रहे आनंद दिघे का ठाणे में बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आनंद दिघे के ही शिष्य माने जाते हैं। और मौके की अहमियत को समझते हुए ही रश्म ठाकरे ठाणे पहुंचकर शिवसेना के ठाणे मुख्यालय आनंद आश्रम भी गई और आनंद दिघे को प्रद्वांजलि अर्पित की। रश्म ठाकरे के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा भी रही।

● बिन्दु माथुर

**ए** जस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 200 रथों के जरिए शुरू की गई भाजपा की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश संगठन के बहुत प्रयासों के बावजूद कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। न आक्रोश व्यक्त करने के लिए जनता जुटी, न भाजपा जनता में आक्रोश जगा सकी। न कांग्रेस सरकार का व्यापक विरोध हो सका, न सामाज्य जन तक कोई संदेश पहुंचा और कार्यकर्ता तो खें कर भी क्या लेते, जब उनके बड़े नेता ही कहीं एकजुट नहीं दिखे।

लगा तो था कि राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जन आक्रोश रथ यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देगी, और पूरे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएगी। लेकिन माहौल कुछ और ही बनता जा रहा है। भाजपा का प्रादेशिक नेतृत्व आपस में ही टकराता दिख रहा है। भाजपा इस चिंतन में है कि भले आदमी की छवि वाले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में क्या कोई कमी रह गई, या फिर पूनिया के सहयोगियों का असहयोग पार्टी के इस आयोजन पर भारी पड़ गया। राजस्थान की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को जहां प्रदेश संगठन ने इस पूरे आयोजन से दूर रखकर अपना महत्व दिखाने की कोशिश की, वहीं प्रदेश में पूनिया के प्रतिद्वंदी अन्य नेता भी इस आयोजन में आधे मन से ही जुड़े दिख रहे हैं।

जन आक्रोश यात्रा जैसे समयानुकूल बड़ा आयोजन विधानसभा चुनावों के 10 महीने पहले समूचे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनजागरण का एक बढ़िया अवसर हो सकता था, लेकिन भाजपा खुद ही अपनी अंदरस्नी चुनौतियों से ज़ूझती दिखाई दे रही है। प्रदेश संगठन द्वारा किनारे की जा रही वसुंधरा राजे को जहां इस जन आक्रोश यात्रा में कोई दायित्व या कार्यक्रम नहीं दिया गया तो राजे ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला। वहीं कई अन्य प्रदेश नेताओं ने यात्रा के लोगों तक को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जगह नहीं दी। इन छोटी-छोटी बातों से ही यह तो साफ समझ में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूनिया के साथ उनके अपने पदाधिकारी भी मन से नहीं जुड़े हैं। वसुंधरा राजे का विकल्प बनने की महत्वाकांक्षा मन में दबाए अनेक भाजपा नेता नहीं चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूनिया सफल हो, लेकिन अपनी इस चाहत से पार्टी की एकता को कोई नुकसान न पहुंचे, इन नेताओं ने यह ख्याल भी नहीं रखा।

राजस्थान में भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है। वसुंधरा राजे, ओम बिडला, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, राज्यवर्द्धन राठौड़, ओम प्रकाश माथुर, किरोड़ीलाल मीना व ऐसे ही कुछ और दिग्गज नेताओं की लंबी-चौड़ी फौज है राजस्थान में। इनमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

# भाजपा का जन आक्रोश



## लोग मुख्यमंत्री व उनकी सरकार से संतुष्ट

राजस्थान सांसद व कांग्रेस के नेता नीरज डांगी का कहना है कि प्रदेश में जब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी सरकार से संतुष्ट हैं, और उनके राज में खुश हैं, तो जन आक्रोश यात्रा का फेल होना पहले से ही सुनिश्चित था। जबकि राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि राज्य की गहलोत सरकार का राजस्थान में शासन जंगलराज की तरह है। सरकार में प्रशासन की जगह कुशासन नजर आ रहा है। उसके खिलाफ पूरी भाजपा एकजुट है व समस्त राजस्थान की जनता का जन आक्रोश यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जबाब में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ तंज कसते हुए कहते हैं कि कटारिया के पास शायद दिव्य दृष्टि है, इसीलिए उनकी पार्टी की असफल जन आक्रोश यात्रा भी उन्हें सफल दिख रही है। भाजपा परेशान है कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों में केवल सालभर से भी कम वक्त बचा है। लेकिन बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षा पाले बैठे नेताओं के परस्पर टकराव और दुराव के कारण जन आक्रोश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन का इतने बड़े पैमाने पर असफल होना, किसी बड़े राजनीतिक खतरे की आहट तो नहीं। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जन आक्रोश यात्रा में अपने नेताओं के खिलाफ और दुराव के उल्ट, कांग्रेस में एक-दूजे के धुर विरोधी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार साथ-साथ दिखे, हर तरह से यात्रा को सफल कराते दिखे और पूरी यात्रा के दौरान दोनों के बीच कोई दुराव नहीं दिखा।

सबसे जूनियर हैं, जिनकी सफलता देखना कोई नहीं चाहता, यह साफ दिख रहा है। सारे नेताओं के अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र हैं, अपनी-अपनी

जातियां, अपने-अपने लोग हैं, और अपने-अपने उद्देश्य। इसी कारण सबका एकजुट होना और सबको एकजुट करना भाजपा के किसी भी नेता के लिए कोई आसान खेल नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा द्वारा राजधानी जयपुर से जन आक्रोश यात्रा रथों को पहली दिसंबर को रवाना किया गया था। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हर गांव, शहर और ढाणी-ढाणी के लिए जन आक्रोश रथ बनाए गए। कांग्रेस सरकार की विफलताओं का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए निकले ये रथ पूरे प्रदेश में घूम तो रहे हैं, लेकिन लोग कहीं नहीं जुट रहे। कार्यकर्ता भी निराश व हताश हैं, क्योंकि कहीं से कोई सार्थक मेटिवेशन नहीं है और जनता में भी गहलोत सरकार से कोई खास नाराजगी नहीं दिख रही। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में हुए भाजपा के विभिन्न आयोजनों में जन आक्रोश यात्रा को सबसे फलपूर्ण आयोजन कहा जा रहा है।

कहीं पर गांवों में जन आक्रोश यात्रा के रथ को घुसने ही नहीं देने की खबर है, तो कहीं यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के ही आपस में भिड़ जाने के समाचार। कहीं भाजपा के जन प्रतिनिधियों से न मिलने की शिकायतें हैं, तो कहीं विकास न होने पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं यात्रा के पोस्टर पर अपने नेता का फोटो न होने के विवाद गर्म रहे हैं, कहीं सांसद के लंबे समय से गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं भाजपा विधायक पर जातिवाद फैलाने के आरोप लग रहे हैं। और कहीं पर लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये सब नौटंकी चल रही है? नागौर के गांव में लोगों ने भाजपा विधायक रूपाराम मुरावतिया व भाजपा सरपंच का विरोध किया, तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार को पचलांगी गांव के लोगों ने खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि एक रुपए का काम नहीं किया और साथे तीन साल से शक्ति तक नहीं दिखाई, और जन आक्रोश रैली में लोगों को भड़काने पहुंच गए।

● जयपुर से आर.के. बिनानी

**3** प्र नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ही नहीं सपा और बसपा में भी अंदरखाने सारी तैयारी चल रही है। बसपा और सपा भी संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहे हैं। उप्र में तमाम राजनीतिक दलों द्वारा 'छोटी सरकार' बनाने के लिए बड़े-बड़े दावेंच अजमाएँ जा रहे हैं। भाजपा, सपा, बसपा के साथ-साथ कांग्रेस भी नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत का ताला खोलने को बेचैन है। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ट्रिप्ल इंजन की सरकार का दाव खेल रही है। वह वोटरों को समझा रही है कि उप्र में अभी मोदी-योगी की डंबल इंजन की सरकार काम कर रही है, यदि नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा को बहुमत मिल गया तो ट्रिप्ल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी।

विभिन्न राजनीतिक दलों की तेजी के चलते राजनीति के तमाम जानकार नगरीय निकाय चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल मानने लगे हैं। वहाँ मैनपुरी की जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी नए सिरे से चुनाव की रणनीति बना रही है। बसपा भी अपने सिम्बल पर प्रत्याशी तय कर रही है। बहरहाल, उप्र नगरीय निकाय चुनाव 2022 में भले ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में मामला अटक गया हो, लेकिन भाजपा ही नहीं सपा और बसपा में भी अंदरखाने सारी तैयारी चल रही है। बसपा और सपा भी संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहे हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक, नगरीय निकाय चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अखिलेश यादव लगातार चर्चा कर रहे हैं। अंदरखाने से यह खबर भी आ रही है कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से आचार संहिता लागू होते ही समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी करेगी। सपा के निर्वाचन नगर पालिका अध्यक्ष, चेयरमैन का टिकट नहीं काटा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मौजूदा जीते हुए सभी लोगों को टिकट दिया जाएगा। हारी हुई सीटों और जीतने की संभावित सीटों को लेकर संभावित सूची तैयार की जा रही है।

विधानसभा चुनाव के दौरान भी आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से टिकट को लेकर अखिलेश यादव का विवाद हो गया था। इसके चलते चुनाव से पहले ही चंद्रशेखर और सपा का गठबंधन टूट गया था। अब एक बार फिर से अखिलेश ने चंद्रशेखर को अपने साथ जोड़ लिया है। दलित वोटर्स और खासतौर पर युवाओं के बीच चंद्रशेखर का अलग क्रेज है। खत्तौली और मैनपुरी में आजाद ने सपा के लिए प्रचार किया और इसका फायदा भी मिला। दोनों सीटों पर सपा की जीत हुई, हालांकि रामपुर में जरूर खेल बिगड़ गया। अब आजाद के जरिए एक बार फिर से अखिलेश दलित वोटर्स को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आजम खान से जेल में न

# छोटी सरकार के लिए बड़ी तैयारी



## निकाय चुनाव के लिए सपा ने लिए बड़े फैसले

समाजवादी पार्टी ने नगरीय निकाय के सभी पदों को पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में सक्रिय सदस्य और समाजवादी बुलेटिन के आजीवन सदस्य ही यह चुनाव लड़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इसके लिए आदेश जारी कर चुके हैं। नगर निगम महापौर, पार्षद, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सभी प्रत्याशियों को सिंबल पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रत्याशियों के चयन के लिए जिलों में आवेदन लिए जा रहे हैं। हर जिले में पहले आवेदकों की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उनमें से 5 नाम प्रदेश मुख्यालय भेजे जाएंगे, जहाँ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव लड़ने वालों को आवेदन के साथ सक्रिय सदस्य होने और समाजवादी बुलेटिन का आजीवन सदस्य होने की रसीद भी लगानी होगी। सपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नगरीय क्षेत्र में आने वाले गांवों को मिलाकर बने नए वार्डों में विशेष निगरानी रखी जाए। निकाय में शामिल होने वाले जिस गांव के लोगों का नाम काट दिया गया है, उसके बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाए। साथ ही पूरे मामले से प्रदेश कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। साथ ही सपा के प्रांप्रागत वोटबैंक से जुड़े लोग आपस में लड़ने की बजाय आपसी सहमति के आधार पर उम्मीदवार तय करें।

मिलने पर मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव से काफी नाराज हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी थी। कई तरह के आरोप भी लगाए थे। अब अखिलेश उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। यही कारण है कि वह आजम खान को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ते। हर मामले में वह आजम को साथ लेकर चल रहे हैं। सपा के दूसरे कददावर मुस्लिम नेता और कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी से मिलने के लिए जेल भी जा रहे हैं। इरफान कई मामलों में फंसे हैं और पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भी सपा मुखिया ने प्लान बनाया है। इसके अनुसार, सपा के नेता और कार्यकर्ता युवाओं से जुड़े हर मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक उठाएंगे। बेरोजगारी, फीस बढ़ावटी समेत तमाम मुद्दों पर युवाओं को अपने साथ लाकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।

उधर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अयोध्या मंडल के मुख्य प्रभारी रहे, विश्वनाथ पाल को पार्टी का नया उप्र अध्यक्ष बनाया है और भीम राजभर को उप्र अध्यक्ष पद से हटाकर बिहार प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसकी जानकारी खुद मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए दी। भाजपा उप्र में ओबीसी वोटरों के सहारे ही दोबारा सत्ता के

शीर्ष तक पहुंच सकी, और इसी के चलते बसपा भी विश्वनाथ पाल के जरिए प्रदेश में ओबीसी वोटों में सेंध लगाना चाहती है, और विश्वनाथ पाल की ओबीसी समाज में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। हाल ही में उप्र में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, और इसी के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का माहौल भापने और माहौल बनाने में भी मदद करता है। इसीलिए हर पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को गंभीरता से लेती है, और इसी का नतीजा है कि बसपा ने विश्वनाथ पाल को चुना ताकि प्रदेश में नए चेहरे के द्वारा कार्यकर्ताओं और संगठन में एक नया जोश भरा जा सके। उप्र में लगातार बसपा का वोट शेयर घटता जा रहा है, और बसपा का वोट लगातार दूसरी पार्टियों पर शिफ्ट हो रहा है, और इसका कारण है मायावती का चुनावी दंगल में न उत्तरना। इसीलिए पार्टी ने अब एक नए चेहरे को मौका दिया है, ताकि पार्टी में दोबारा जोश भरा जा सके। इस बार के नगर निगम चुनाव में बसपा का प्रदर्शन तय करेगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में हाथी कितना गरज पाता है। लगातार बसपा प्रदेश में अपनी चुनावी जमीन को गवाती नजर आती है। इसका बड़ा कारण है, बसपा का विपक्ष की भूमिका को सही ढंग से न निभाना।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

ए के ओर जहां आए दिन संसद या विधानसभाओं में हंगामे की खबरें आती रहती हैं, वहीं बिहार विधानसभा में एक ऐसी बात पर हंगामे की खबर आई जो किसी मुद्दे से नहीं बल्कि भाषाई संस्कार से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा को तुम से संबोधित कर दिया। बस इसी बात को इतनी बड़ी अशिष्टता और अभद्रता समझा गया कि विधानसभा में हंगामा हो गया। इस हंगामे को समझने के लिए बिहार के भाषा संस्कार को समझना पड़ेगा। बिहार में झगड़ा भी आप के संबोधन से होता है। पश्चिमी उप्र या हरियाणा में जहां तम या तुम एक सामान्य संबोधन समझा जाता है, वहीं बिहार में तुम का संबोधन अपमानजक माना जाता है। अपने से किसी वरिष्ठ को तुम से संबोधित करना गाली देने जैसा होता है।

बिहार में भाषाई संस्कार को लेकर बिहार में खास सतर्कता बरती जाती है। जैसे मैं की जगह हम और मेरे की जगह हमारे का प्रयोग करने वाले को सुनते ही लोग समझ लेते हैं कि वह बिहार की भाषाई भूमि पर पला बढ़ा शख्स है। इसी तरह बिहार में आप और तुम के प्रयोग को लेकर स्पष्ट भेद है। गली, मोहल्लों में तुम कहना क्रोध, रोष और हंगामे का आधार बन जाता है। अपने से उम्र अथवा पद में बड़े या सम्मानित व्यक्ति को तुम कह देना अमर्यादा है। इसे अभद्रता और गंदी गाली की श्रेणी में रखा जाता है।

यहीं बिहार विधानसभा में हुआ। विजय सिन्हा एनडीए की सरकार में वरीयता के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। बिहार की भाषाई मर्यादा के अनुसार उनसे जूनियर नीतीश कुमार उन्हें तुम से संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो इसे गाली-गलौज की भाषा में बात करना बता दिया गया।

असल में बिहार विधानसभा में सारण के दोइला गांव में नकली शराब से हुई मौतें पर हंगामा मचा था। विपक्ष के हंगामे पर गुस्से से आवेशित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष से जोर-जोर से कहने लगे, क्या हो गया तुमको, चुप रहो... शराबबंदी के फैसले के समय साथ थे कि नहीं। इससे आवेशित भाजपा ने प्रतिपक्ष के नेता को तुम कहने पर मुख्यमंत्री के माफी मांगने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।

# हंगामा क्यों बरपा है... ?



## बिहारी अस्मिता का मुद्दा

जहरीली शराब से हो रही मौतों से इतर भाषाई संस्कार के मुद्दे ने बिहार की राजनीति में टीक उसी तरह गर्माहट पैदा की है, जैसी कभी बिहारियों के डीएनए को नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहारी अस्मिता का मुद्दा बनाकर पैदा की थी। 2015 में भाजपा से अलग जाकर राजनीति कर रहे नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर राज्य के वाशिंदों से लड़ सैंपल देने का आह्वान किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखकर 50 लाख बिहारियों का लड़ सैंपल भेजने की सियासी दावेदारी की थी। ताकि उसकी जांच से अस्मिता के उज्ज्वल पक्ष को उजागर किया जा सके। अब इन्हीं नीतीश कुमार पर बिहार में प्रवर्तित भाषाई गरिमा को तिलांजिल देने का आरोप है। तुम कहकर अमर्यादित आचरण करने के लिए क्षमायाचना करने को कहा जा रहा है।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर राजनीति में आए नीतीश कुमार उज्ज्वल बिहारी अस्मिता के वाहक रहे हैं। बिहार के धबल पक्ष को बुलंद करने के लिए अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी का सख्त कानून लागू किया था। हजारों करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान वाले फैसले के बक्त भाजपा नीतीश सरकार में शामिल थी। नीतीश कुमार के दूसरी बार पाला बदलने से भाजपा फिर विपक्ष में है। शराबबंदी के दौरान

सस्ती जहरीली शराब पीने से हो रही मौतें विपक्ष के लिए प्रमुख मुद्दा है। इसे भाजपा सिर्फ बिहार विधानसभा ही नहीं संसद के शून्यकाल में भी जोर-शोर से उठा रही है।

ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा की कार्यवाही के बीच प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा को अंगूली दिखाकर आवेश में कहना कि अब तुम्हें क्या हुआ, चुप रहो, बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है। वैसे विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह में उन दिनों भी रोड़ बिछाने का काम कर चुके हैं जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग मुख्यमंत्री के एनडीए से नाता तोड़ने की एक वजह विजय सिन्हा की ओर से सदन में नीतीश कुमार के साथ किए गए सामान्य व्यवहार को मानते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को तुम तड़क की गलती का हो जाना पिछली घटना की नाराजगी का नीतीजा बताया जा रहा है।

एक समय नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता से जुड़े सम्मान की प्रधानता को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। बिहारी डीएनए पर सवाल को लेकर पटना से दिल्ली तक की फिजा को गर्मा दिया था। प्रतिपक्ष के तीक्ष्ण हमलों से घिरकर वह सदन में बार-बार आपा खो दे रहे हैं। कुछ लोग उन पर इसे उम्र का असर तो कई लोग स्वभाव के विपरीत गठबंधन करने की विश्वासता का नीतीजा बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश दूसरी बार पाला बदलकर तब के विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप्र की राज्य सीमा से घिरे बिहार में शत-प्रतिशत शराबबंदी लागू कर पाना नीतीश कुमार सरकार के लिए निरंतर चुनौती बनी हुई है। सरकार की सख्ती के बीच शराब की डिमांड की भरपाई के लिए चोरी से नकली शराब बनाने वालों की चांदी कट रही है। शराब तस्करी को लेकर राज्य की बदनामी बढ़ी है। नकली, सस्ती और जहरीली शराब पीकर गरीब ग्रामीणों के मरने का सिलसिला जारी है। इन मौतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के गठबंधन की सरकार को विपक्ष ने निशाने पर ले रखा है। विपक्ष में बैठी भाजपा का दावा है कि जहरीली शराब बेचने वालों की हिम्मत लचर कानून व्यवस्था की वजह से बड़ी हुई है।

● विनोद बक्सरी

# ANU SALES CORPORATION



## We Deal in Pathology & Medical Equipment

**E1200** for technology

● BioSystem

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,  
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

**ई** रान में सुरक्षाबलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ दुष्कर्म किए जाने को लेकर एक झकझोर देने वाली रिपोर्ट में सीएनएन ने बताया है कि कैसे एक 20 वर्षीय युवती को विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसके साथ मारपीट कर उसका सिर मुँडवाया गया। जब उसके यौनांग से रक्तस्राव हुआ तो उसे एक अस्पताल ले जाया गया। अब वह जेल में है। मानवाधिकार संस्था और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वतंत्र रूप से इस तरह के कई यौन उत्पीड़न मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। न्यूयार्क के वाचडाग आर्गेनाइजेशन और ईरान में मानवाधिकार केंद्र की समर्थक घामी ने तेहरान के निकट रहने वाली 14 वर्षीय एक गरीब लड़की के बारे में बताया, जिसने स्कूल में अपना हेड्स्कार्फ उतारकर विरोध किया था। इस लड़की की पहचान मासूमेह के तौर पर हुई। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसके यौनांग से स्राव के चलते अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब उसकी मां ने कहा कि वह जनता के बीच जाना चाहती है तो वह गायब हो गई।

यौन हिंसा के मामलों को सत्यापित करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पीड़ित को इसे बताने में संकोच के साथ ही डर भी सताता है। अधिकारी कई बार इन पीड़ित प्रदर्शनकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए प्रताड़ना के दौरान की उनकी फिल्म तक बनाते हैं। ईरान में जारी प्रदर्शन की वजह केवल हिजाब का विरोध करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी है, जो पूरी तरह भ्रष्ट, दमनकारी और क्रूर है।

यदि कोई सरकार कुछ गलत कर रही है तो देश की जनता को सीधे उसके मुँह पर बार करना चाहिए। ईरान की जनता यही करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर हैरानी और निराशा होती है कि आज ईरान की इस क्रांति को अमेरिका समेत अन्य देशों से कुछ खास समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कुछ कारण भी नजर आते हैं। इनमें पहला यह है कि ईरान ने अधिकतर विदेशी पत्रकारों को अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए वहां सड़कों पर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने वाले स्कूली बच्चों के विरोध को रिकार्ड करने वाले नहीं हैं। यह भी लगता है कि पत्रकारों ने सामूहिक रूप से इस कहानी को उतना महत्व नहीं दिया, जिसकी वह हकदार है।

दूसरा कारण ईरानियों के प्रति अमेरिकियों के मन में भरी कड़वाहट और यह गलत धारणा भी है कि वे अमेरिका की बबादी का नारा लगाने वाले कट्टरपंथी हैं। वास्तव में ईरान संभवतः पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा



## क्रूरता की हृद

### ईरान में बड़े पैमाने पर हो रहा दमन

पश्चिमी जगत ईरान के उन अधिकारियों को प्रतिवंधित करने की भी कोशिश कर सकता है, जो विदेश में पार्टी करते हैं या वहां संपत्ति खरीदते हैं। खुफिया एजेंसियों को ईरान में बड़े पैमाने पर हो रही दमन की कार्रवाई को लेकर अधिक जासूसी करनी चाहिए और वहां के अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए हरसंभव कोशिश करनी चाहिए। ईरान पर दबाव बनाना मुश्किल है, क्योंकि वह पहले से ही अलग-थलग है, फिर भी कोशिश होनी चाहिए, व्योंग अब ईरान ने जनता को डराने के लिए प्रदर्शनकारियों की हत्या भी शुरू कर दी है। दो प्रदर्शनकारियों को अब तक ईरान में फांसी दी जा चुकी है और करीब 35 को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ईरान की क्रांति के चार दशक से भी अधिक समय के बाद ईरानी उस गहरी खाई से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे वर्षों से फंसे हुए हैं और जिसका नेतृत्व स्कूली छात्राओं द्वारा किया जा रहा है, जो तमाम खतरों के बावजूद अपनी मांग पर डटी हुई है। विरोध-प्रदर्शन करने वाली इन महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक समर्थन मिलना चाहिए।

अमेरिकी समर्थक देश हो सकता है। आम ईरानी अमेरिकियों से मिलने के लिए रोमांचित रहते हैं। एक बार अमेरिका विरोधी एक संग्रहालय की सुरक्षा में तैनात एक युवा

रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि वहां अमेरिका को शैतान के रूप में बदनाम करने वाले विशाल बैनर लगे हुए थे। उसने कई लोगों से सलाह मांगी कि अमेरिका कैसे जाया जा सकता है? ईरान में आज जो विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें निडर युवा लड़कियां सबसे आगे हैं। जब अर्धसैनिक बल के एक सदस्य ने किसी स्कूल का दौरा किया तो वहां लड़कियों ने विरोधस्वरूप अपने हिजाब उतार दिए और उसे जमकर गालियां सुनाई। कराज के एक गल्स कॉलेज में लड़कियों ने एक अधिकारी पर पानी की बोतलें फेंकी और उसे बाहर धकेल दिया।

नसरीन सोतौदेह ईरान में मानवाधिकार मामलों के बकील हैं। 10 साल की सजा के बाद वह मेडिकल फरलो पर हैं। नसरीन और अन्य लोग चाहते हैं कि बाइडन प्रशासन ईरानी सरकार को अवैध ठहराने का काम करे। लोग यह भी चाहते हैं कि पश्चिम की सरकारें ईरान से अपने राजदूतों को वापस बुला लें। ईरानी-अमेरिकी फैशन डिजाइनर ताला रासी का कहना है कि बाइडन प्रशासन ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। उन्हें 16 वर्ष की उम्र में निजी पार्टी में टीर्शट और मिनी स्कर्ट पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर 40 कोडों की सजा दी गई थी। एक ईरानी-अमेरिकी लेखक अमीर सोल्टानी ने कहा कि 'मैं दमन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन को अन्य देशों के साथ काम करते देखना चाहता हूँ।' उन्होंने सुझाव दिया कि 'जिस तरह रीगन ने "मिस्टर गोर्बाचेव, टीयर डाउन दिस वाल, का भाषण दिया था, उसी तरह बाइडन 'अयातुल्ला मुक्त ईरान' की बात कर अमेरिकी संकल्प का संकेत दे सकते हैं।'

● ऋतेन्द्र माथुर

# ची

नी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस समय महान बनने का भूत सवार है। वे इतिहास के पनों में एक शक्तिशाली चीनी सप्तराषि के बतौर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिए वे अपने पड़ोसी देशों पर लगातार दनदना रहे हैं। उनकी महानता के इस सपने में सबसे बड़ी बाधा भारत और उसका मौजूदा नेतृत्व है। इसलिए वह समय-समय पर भारतीय सीमा पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं।

भारत को लेकर शी जिनपिंग की परेशानी के कई कारण हैं। पहला, जो इज्जत और सम्मान भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में मिला हुआ है, वैसा चीन की अधिनायकवादी, तानाशाही और निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्था को नहीं मिलता। इसलिए चीन लगातार अपने प्रचार तंत्र और भारत में मौजूद अपने दत्तक वैचारिक युगों के जरिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल बनाता रहता है। हमारी व्यवस्था पर ये प्रहार कभी माओवादियों के आतंक के जरिए होता है तो कभी वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग के जरिए।

याद कीजिए कि किस तरह जब भारत में कोविड महामारी की पहली और दूसरी घातक लहर आई थी तो इन कतिपय लोगों ने बड़े-बड़े अखबारों में लेख लिखकर चीन से सीखने की वकालत की थी। कई भाई लोगों ने तो बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक में भारत के भीतर ही मार्क्सवादी सरकार के केरल मॉडल की तारीफ में दर्जनों खबरों और लेख छपवाए थे। ये बात अलग है कि उनमें दिए अधपके तर्क और तथ्य बाद में गलत साबित हुए। ऐसा ही चीन की कोविड नीति के बारे में भी साबित हुआ। आज पूरा विश्व भारत की कोविड से निपटने की रणनीति को सही मानता है।

दुनिया को त्रस्त करने वाली कोरोना महामारी के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की प्रयोगशाला से ही पैदा हुई। कई पश्चिमी विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि इसे जैविक हथियार के



## जिनपिंग पर महान बनने का भूत सवार

तौर पर चीन ने दुनिया को परास्त करने के लिए जानबूझकर कर प्रयोगिक तौर पर पैदा किया। पर वही कोरोना अब खुद चीन के लिए भस्मासुर बन गया लगता है। कुछ समय से चीन में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति नाकाम हो चुकी है। त्रस्त चीनी जनता ने खुलेआम इसका विरोध किया है और चीन के दर्जनों शहरों और विश्वविद्यालयों में सरकार की कोरोना नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। वैसे तो चीन के निरंकुश और तानाशाही कम्युनिस्ट तंत्र से खबरें बाहर आना मुश्किल है। लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर छन-छन कर जो जानकारी बाहर आ पाई है उससे लगता है कि कोरोना को लेकर आम चीनी नागरिक बेहद हताश, निराश और गुस्से में हैं। ये प्रदर्शन शुरू तो कोरोना को लेकर हुए थे लेकिन बाद में इनमें शी जिनपिंग के खिलाफ नारे भी सुनाई दिए हैं। चीन की कठोर नियंत्रण वाली व्यवस्था में ये प्रदर्शन किसी विद्रोह से कम नहीं है। 1989 के ध्यानन्मान प्रदर्शनों के बाद चीन में ये ऐसे पहले व्यापक प्रदर्शन हैं। 1989 के इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीनी सरकार ने अपने निहत्थे नागरिकों पर टैंक चढ़ा दिए थे। मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों की गिरफतारी हुई लेकिन फिर भी चीनियों का आक्रोश नहीं थमा है।

हारकर कम्युनिस्ट सरकार को अपनी तीन

साल से चल रही जीरो कोविड नीति में कई बड़े परिवर्तन करने पड़े हैं। इससे स्थितियां ठीक होने की बजाय और भी विषम हो गई हैं। चीन में अभी भी सभी बुजुर्गों को टीके नहीं लगे हैं। इसलिए वहां कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की खबरें आ रहीं हैं। सघन आबादी को देखते हुए कोरोना से भारी संख्या में मौतों की आशंका की जा रही है। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग आंतरिक स्थितियों से चीन की जनता का ध्यान हटाने में माहिर खिलाड़ी हैं। इसका बेहतर इस्तेमाल उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले अधिवेशन में किया और तीसरी बार चीन के सर्वेस्व बन बैठे। ऐसा माओ के बाद पहली बार चीन में हुआ। अरुणाचल में नियंत्रण रेखा का स्वरूप बदलने की नाकाम कोशिश को भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

उधर बुनियादी तौर पर भारतीय सभ्यता और विरासत के चिर पुरातन और नित्यनूतन स्वरूप को भी चीनी नेतृत्व एक चुनौती के रूप में देखता है। चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व जानता है कि पुराने समय से भारत आध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान करता रहा है। तिब्बत और एशिया के बाकी देशों में बौद्ध धर्म का अमिट प्रभाव इसका अन्यतम उदाहरण है। चीन के लिए यह एक बुनियादी वैचारिक और आध्यात्मिक चुनौती है।

● कुमार विनोद

भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से रोकने के लिए चीन 1950 से

ही पाकिस्तान का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद की फँडिंग उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर लगाए हैं लेकिन वे सब अब बटटेखाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में डर ये है कि पाकिस्तान को दिए कर्जे की एवज में चीन उसकी सेना और आईएसआई से भारत में आतंक फैलाने को कहगा। भारत को उलझाए रखने के अपने इसी मिशन के तहत चीन भारत में माओवादियों और वामपंथी गुटों को बढ़ावा देता रहा है। यही कारण है कि भारत में हर छोटी सी बात पर शोर मचाने वाले वामपंथी बुद्धिजीवियों को चीन में उड़िगर मुसलमानों के

## पाकिस्तान का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल

निर्दयतापूर्ण दमन पर सांप सूंध जाता है। मजहबी आजादी का झंडा लेकर चलने वाले भी चीन में हो रहे दमन पर एक बयान तक नहीं देते। दरअसल इनमें से अधिकतर लोग बुद्धिजीवी की आड़ में भारत को परेशान रखने के लिए चीन के पाले हुए तोते जैसे हैं। चिंता की बात तो ये है कि अपने देश के मीडिया और अकादमिक जगत में इनकी गहरी घुसपैठ है। इन सारी रुकावटों और अड़चनों के बावजूद भारत अपनी अस्मिता के साथ आगे बढ़ता ही गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट नीतियों और ठोस सोच ने भारत को एक नई आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक धारा दी है। भारत-चीन सीमा पर बन रहे सड़कों और पुलों के नए जाल ने चीन के विस्तारवादी इरादों में खलत डाल दी है।

# प्रिज्म® चैमिप्यन प्लस

जिम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको-फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत



दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: [cement.customerservice@prismjohnson.in](mailto:cement.customerservice@prismjohnson.in)



## महर्षि धौम्य की चिंता

**अ** पने गुरु महर्षि धौम्य की आज्ञा पाकर शाम को आरूपि खेत गया। खेत पहुंचकर देखा कि मेड़ कटी हुई है। पानी खेत से निकल रहा है। बारिश भी हो रही है; और थमने का कोई आसार नहीं। रात गहरी होती जा रही है। उसने आश्रम लौटना उचित समझा। आरूपि को देखते ही महर्षि धौम्य ने पूछा— वत्स! खेत ठीक तो है न? फसल कैसी है?

ठीक है गुरुदेव! पर एक समस्या है वहां। गहरी सांस लेते हुए आरूपि बोला।

क्या वत्स? कहो? महर्षि धौम्य के श्रीमुख से स्नेहपूर्वक वाणी निकली।

आरूपि बोला— खेत की मेड़ कट गई है गुरुदेव। खेत से पानी निकल रहा है। बहाव भी बहुत तेज है। मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं मेड़ को कैसे बांधता; और पानी रोकता।

प्रयत्न तक नहीं किया पुत्र? ऋषिवर धौम्य ने कहा— मिट्टी डालकर देखना था तुम्हें; कदाचित पानी रुक जाता। वर्षा रुकने की थोड़ी प्रतिक्षा कर लेते।

इतना क्या है गुरुवर, इस वर्ष फसल नहीं पक पाएगी तो। खेत केवल न तो आपकी है; न ही मेरी। फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? हानि तो पूरे आश्रम को उठानी पड़ेगी न। मैं खेत की मेड़ बांधने तो नहीं आया हूं आश्रम में। मैं तो विद्या ग्रहण करने आया हूं। आरूपि के स्वर में बड़ी तीक्ष्णता थी। महर्षि धौम्य आरूपि की बातें सुन फिर कुछ नहीं बोले। सोच में डूब गए कि वे अपने से अपेक्षित इस समाज को भला कैसे समझाए। आज से पहले उहें इतनी चिंता कभी नहीं हुई थी।

- टीकेश्वर सिन्हा गब्दीवाला

**माँ** अपनी अटेची में कपड़े टूंसते हुए बोली— चल बेटा, अपने पुराने मुहल्ले में। मुझे अब यहां नहीं रहना।

क्यों माँ! तुम्हें तो यहां की हरियाली, फलदार पेड़ और उस पर चहकते पक्षी, सुगन्ध बिखराते फूल तो बड़े ही भाए थे। छोटे से पांड में बत्तखों को देखकर कैसे तुम बच्चों-सी मचल गई थी।

हां, लेकिन..

जानती हो माँ, तुम्हें इस तरह से खुश देखकर पहली बार लगा था कि मैं पापा की जगह खड़ा हूं, अपनी नौकरी की रकम से इस सोसायटी में तुम्हारे लिए छोटा-सा फ्लैट लेकर मैंने कोई गलती नहीं की है।

नहीं मेरे लाड़ले, तूने कोई गलती नहीं की। लेकिन...



## सम्पन्न दुनिया

सांसों से यूं कभी निभाना पड़ता है जिंदा होकर भी मर जाना पड़ता है

तेरे-मेरे बीच में ऐसी दूरी है मैं तेरा हूं रोज बताना पड़ता है

रिश्तों में कुछ जान बचाए रखने को सच्चा होकर भी झुक जाना पड़ता है

तुझसे मिलने घर से निकला करता हूं लेकिन रस्ते में मयखाना पड़ता है

तेरी बज्म में आ तो जाता हूं लेकिन बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है

खुशबुओं की बारिश है, बंदगी के टुकड़े हैं ये गजल के शेर हैं कि रोशनी के टुकड़े हैं

जो नजर नहीं आता पर हर एक शय में है तुम उसी के टुकड़े हो, हम उसी के टुकड़े हैं

बात-बात पर तेरा मुस्कुराके धृत कहना दिल्लगी नहीं है ये चांदनी के टुकड़े हैं

मां-पिता हों या पत्नी, भाई, बहन या बच्चे इनको मत कहो रिश्ते जिंदगी के टुकड़े हैं

कोई एहसान कहां दोस्ती में होता है ये अगर हुआ समझो दोस्ती के टुकड़े हैं

वो सब्जी मुंह फुलाती है कि रोटी मुंह फुलाती है नहीं टाइम से घर लौटूं तो बीबी मुंह फुलाती है

इधर सावन रहा सूखा उधर तुम भी नहीं आए ये झूले मुंह फूलाते हैं कि मैंहदी मुंह फुलाती है

जो खुद को बेच आए हो किसी मुजरिम के हाथों तुम तुम्हें दिखता नहीं शायद ये वर्दी मुंह फुलाती है

ये इतनी रात में लौटे हो उस पे लड़खड़ाते-से तुम्हारा दिल नहीं दुखता जो बटी मुंह फुलाती है

कभी चैनल बदलता है कोई अपनी पसंद वाला तो दादी मुंह फुलाती है कि नानी मुंह फुलाती है

बहू कुछ सोच ले अब तो सदा कहती हैं सासू मां ये नीबू मुंह फुलाता है कि इमली मुंह फुलाती है



- अशोक 'अंजुम'

मां तुम्हें याद है! पवनचक्की को देखकर तुमने कहा था कि चल अच्छा है यहां ये भी है, गर्मी में बिन पंखे के भी नहीं रहना पड़ेगा। फिर आज ऐसा क्या हुआ... ?

बेटा! सब कुछ है, किंतु यहां इंसान नहीं है.. !

हा.. हा.. हा.. ! क्या माँ! यहां हजारों लोग रहते हैं, बस तुम्हें दिखते नहीं होंगे। पार्क में बैठने की तुम्हारी और उनकी टाइमिंग एक नहीं होगी न!

नहीं बेटा! टाइमिंग तो एक ही है परंतु उनमें इंसानियत नहीं है, सब रोबोटिक्स हैं! तू लेकर चल मुझे उसी पुराने मुहल्ले में, जहां एक-दूसरे का दुख-दर्द पूछने वाले ढेरों इंसान रहते हैं।

- सविता मिश्रा 'अक्षजा'

**मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवींद्र भवन भोपाल में मप्र शिखर खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2020 की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मप्र में होने वाले खेलों इंडिया यूथ गेम्स-2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया गया।**

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र में खेल के अनुरूप वातावरण बन रहा है। हर जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर खेल अधो-संरचना का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में उत्कृष्ट खेल अधो-संरचना तो होगी ही, साथ ही खिलाड़ियों को खेल के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मप्र खेलों में भी नम्बर-1 बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में मप्र लगातार आगे बढ़ रहा है। खेलों इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की प्रसन्नता खेलते समय अद्भुत होती है। खेल जिंदगी का अंग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा। खेलों इंडिया गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मप्र के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धाएं में डटकर मुकाबला कर मेडल लेकर आएं। उन्होंने कहा कि भोपाल के बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्मित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2020 के राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित कर अवॉर्डियों की उपलब्धियों से समाहित स्मारिका का विप्रोचन किया। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन कर समारोह का शुभरंभ किया। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, सासंद व्हीड़ी शर्मा, मप्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, महासचिव मप्र बॉक्सिंग ओलंपिक संघ दिविजय सिंह तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मप्र ने विगत दो दशकों में खेल के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बधाई के पात्र हैं। यहां उत्कृष्ट गुणवत्ता की खेल अधो-संरचना है। यहां का शूटिंग रेंज बहुत खूबसूरत है, 30 एकड़ में तैयार हाँस रेस सेंटर उम्दा है। जब किसी अन्य देश में हमारे खिलाड़ी पदक लेते हैं, तो हमारा राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही राष्ट्रगान होता है। इससे देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को पहली बार चेस ओलंपियाड के आयोजन का अवसर मिला है, जिसकी रिले टार्च उन्होंने लांच की। देश को पहली बार थॉमस कप

# मप्र खेलों में भी बनेगा नम्बर वन



## विक्रम पुरस्कार

विश्वजीत सिंह कुशवाह को कैनो स्लॉल्म, सुनिधि चौहान को शूटिंग, निधि नन्हेर को कराटे, परिधि जोशी को घुड़सवारी, मंजू बावेरिया को बॉक्सिंग, एकता यादव को सेलिंग, विवेक सागर प्रसाद को हॉकी, हर्षवर्धन तोमर को बास्केटबॉल, पूजा मालवीया को मलखम्ब, प्राची यादव (दिव्यांग) केनोइन-क्याकिंग खेल के लिए विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## विश्वामित्र पुरस्कार

वीरेंद्र कुमार डवास को तैराकी/पैरा एथलेटिक्स में तिजपाल सिंह सलारिया को तीरंदाजी, डॉ. हबीब हसन को हॉकी में विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## स्व. प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार

वैष्णवी कहार को मलखम्ब खेल के लिए स्व. प्रभाष जोशी स्मृति खेल पुरस्कार दिया गया।

## लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार

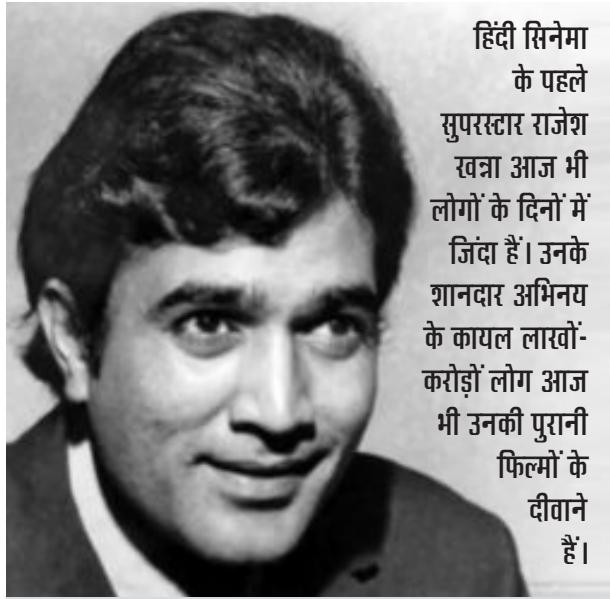
अभय छजलानी को मप्र में खेलों के उत्थान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

में वर्ष 2022 में गोल्ड मेडल मिला है। देश में एक हजार खेलों इंडिया सेंटर खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का खेल बजट 4 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए तक कर दिया है।

स्वागत उद्घोषन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मेडल ला रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ी अपना लक्ष्य हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन करें। खेलों इंडिया गेम्स 30 जनवरी को मप्र में शुरू होंगे। खेल मंत्री ने विक्रम और एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

पुरस्कृत खिलाड़ियों में वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार सुषमा वर्मा को केनोइंग-क्याकिंग और तुषिता सिंह को सॉफ्ट टेनिस में दिया। स्पर्श खरे को बुशु खेल में एकलव्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। अर्जुन सिंह को घुड़सवारी खेल के लिए वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। सुनील डाबर को एथ्लेटिक्स में 2020 का एकलव्य पुरस्कार उनकी अनुपस्थिति में पिता को प्रदान किया गया। गोरांशी शर्मा (दिव्यांग) को बेडमिंटन में वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। राम मिलन यादव को सेलिंग में, अंकित शर्मा को फैसिंग में, अनुराधा अहिवार को तीरंदाजी में, पीति रजक को शूटिंग में, शशांक पटेल को ताइक्वांडो में, साधना सेंगर को हॉकी, ध्रुव राज कुरें को पावर लिफिटिंग में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

● आशीष नेमा



हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आज भी लोगों के दिनों में जिंदा हैं। उनके शानदार अभिनय के कायल लाखों-करोड़ों लोग आज भी उनकी पुरानी फिल्मों के दीवाने हैं।

## अकेलेपन के कारण आत्महत्या करना चाहते थे राजेश खन्ना

**रा**जेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आनी शुरू हो गई थी। खबरों ये थीं कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करें। इसी बजह से दोनों में काफी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे, लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि डिंपल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीनों के लिए खुद के

आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्में साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया था। लगातार फिल्म में ढूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैस तक ना पहुंचे।

### कैरियर के डाउनफॉल में थे अकेले, अवॉर्ड फंकशन में भी कोई साथ नहीं जाता था

जहां एक बक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वहीं जिंदगी के आखिरी सफर में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने कैरियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था। लेकिन ऐसा भी बक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया। यह बताते हुए वो भावुक हो गए थे। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचौमेंट अवॉर्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या वह अवॉर्ड फंकशन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे? राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी। साथ ही उन्होंने मीरा से फंकशन के कुछ एक्सट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंकशन में अकेले पहुंचे थे जिस बात से सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने एकस्ट्रा पास लिया फिर भी उनके साथ अवॉर्ड फंकशन में कोई नहीं आया था।

### जब अपने ही दोस्तों के सामने पिता राकेश रोशन ने ऋतिक को पीटा

**ए**क बार एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने खुलासा करते हुए बताया था कि वह एक बार अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खेल-खेल में कांच की खाली बोतलें घर के टैरेस से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर राकेश रोशन को बहुत गुस्सा आया। गुस्साए राकेश रोशन ने ऋतिक के दोस्तों के सामने ही उनकी बहुत पिटाई की थी। बताया जाता है कि ये पहली और आखिरी बार था, जब राकेश रोशन ने ऋतिक पर हाथ उठाया था।

आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के साथ उनके पापा राकेश रोशन की बॉन्डिंग बेहद खास है। दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब हैं। ऋतिक अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के साथ बिताए गए यात्राओं को शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ऋतिक कई बार ये कबूल कर चुके हैं कि उनके पिता ही उनके मोटिवेटर हैं। वहीं राकेश रोशन ने हमेशा ऋतिक को सही राह दिखाई दी। जब उन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया तो भी राकेश रोशन ने उनके फैसले का सम्मान किया। जिस तरह राकेश रोशन ने ऋतिक को बॉलीबुड में लॉन्च किया, वो अपने आप में रिकॉर्ड है।



### ...सिद्धार्थ शुक्ला की किक से डरकर भाग निकले थे ऑफिस वाले

**सि**द्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ अनकहे किस्से हैं, जो उनके फैस के लिए खुशी भरे पल हैं। सिद्धार्थ के फिटनेस ट्रेनर सोनू चौरसिया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि

मुझे याद है एक बार सिद्धार्थ को मैंने कहा था कि आज तुम्हें 50 किक करनी है और वो भी पूरे जोश के साथ। हम जिस जिम में एक्सरसाइज करते थे, वहां कॉमन दीवार थी। दीवार के इस तरफ जिम और दूसरी ओर किसी का ऑफिस था। सिद्धार्थ ने दीवार पर जोर-जोर से किक करना शुरू किया था। 25 या 30 किक करने के बाद ऑफिस वाले डर गए थे, उन्हें लगा शायद भूकंप आ रहा है, इसलिए दीवार हिलने लगी हैं।

दीवार के ऊपर एक रॉड थी, जो ईंट से जुड़ी थी। वो ईंट जाकर ऑफिस की तरफ गिरी, तो वहां के लोग भूकंप समझकर बाहर निकलकर आ गए थे। हम दोनों एक्सरसाइज में इतने मशगूल थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरी ओर ईंट जाकर गिर गई है। उन ऑफिस वालों ने आकर हमें देखा, तो गुस्से में आ गए। हालांकि हम दोनों के लिए वो मॉमेंट काफी फनी था, मैं उसके साथ किए गए सेशन को कभी भूल नहीं सकता।

**ज** हां तक मेरी जानकारी की दूरदृष्टि जाती है, चोरी एक सदाबहार कला के रूप में विख्यात रही है। चोरियों के भी तो अनेक प्रकार हैं। केवल धन की चोरी ही चोरी नहीं होती। और भी चोरियों के विविध रूप हैं। धन की चोरी से पहले भी अनेक प्रकार की चोरियां होना एक साधारण सी बात मानी जाती रही है। दिल की चोरी उनमें प्रमुख स्थान रखती है। यदि ऋषि पाराशर नाव से नदी पार करती हुई निषाद कन्या सत्यवती के दिल की चोरी नहीं करते तो महाभारत जैसे महान ग्रन्थ की रचना से संसार वंचित हो जाता। संसार मात्र इसी से वंचित नहीं होता, वरन् पुराणों के पारायण से भी अनभिज्ञ रह जाता। यह दिल की चोरी का ही सुपरिणाम है कि महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण इस धरा-धाम में हो सका। इस प्रकार चोरियों की भी महान उपलब्धियों से संसार लाभांशित होता रहा है और आज भी वह परम्परा अनवरत रूप से प्रवहमान है।

निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किस-किस वस्तु या अवस्था की चोरी हो सकती है! चोरी-चोरी नजरें मिलती हैं, तो क्या कुछ नहीं होता? ये सभी चोरियां सूक्ष्म प्रकार की हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से चोरियों को दो कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है— पहली सूक्ष्म चोरी और दूसरी स्थूल चोरी। सूक्ष्म चोरी वह है जिसमें किसी भौतिक वस्तु के स्थान पर कोई अदृश्य और सूक्ष्म भाव या प्रभाव चोरी हो जाता है। मैंने यह भी पढ़ा है कि कवि लोग भी चोरी करते हैं। लेकिन उनका चौर्य-चारुर्य भी सराहना का सुप्राप्त हो सम्मानित हो जाता है। यहां पर यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि हमारी सुप्रसिद्ध चौसठ कलाओं में एक कला चोरी भी है। इसलिए कवियों की विचार और भावों की चोरी को सराहा जाता है। वाह! वाह!! ही की जाती है। हां, इतना अवश्यक है कि यदि चोरी पकड़ ली जाती है तो निंदा-उपाहन से पाहन-प्रहर कर चोर की मातमपुर्सी में भी कमी नहीं छोड़ी जाती। भाषा-शैली की चोरी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि इससे पकड़े जाने का खतरा भी उतना ही अधिक है। कवि-चोर या लेखक-चोर को इस चोरी से सर्वथा बचना ही श्रेयस्कर है। तभी उसके सिर को खल्लाट होने से बचाया जा सकता है।

आज के युग में कर-चोरी, जीएसटी-चोरी, एटीएम-चोरी, डाटा-चोरी जैसी अनेक अत्याधुनिक चोरियों की भरमार हो गई है। ज्यों-ज्यों देश, दुनिया और आदमी का विकास हो रहा है, चोरियों के क्षेत्र का विस्तार भी इतना अधिक हो गया है कि जब तक इस विषय पर मैं एक शोध प्रबंध पूर्ण करूँगा, तब तक नए-नए प्रकार की चोरियों का अविष्कार हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि चौर्य शोध प्रबंधों का धारावाहिक क्राइम पेट्रोल के धारावाहिकों की तरह अनंत

# चोर-चोर मौसोरे भाई



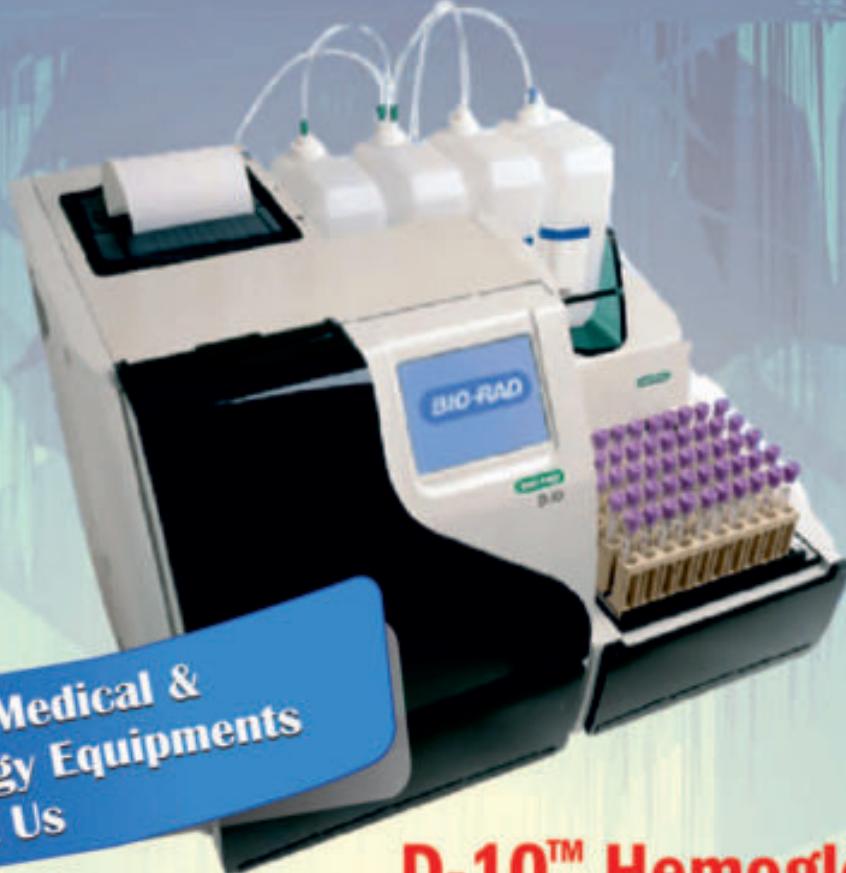
काल तक चलता रहेगा।

**सामान्यतः** संसार में सर्वश्रेष्ठ, सर्व लोकप्रिय और सर्वत्र व्याप्त चोरी का रूप ‘धन की चोरी’ है। जो अपने विविध आयामों में अवतरित होकर चोरों की कृपा का पात्र बना रहा है। धन की चोरी गबन, उत्कोच, कमीशन, छूट, अपहरण, सेंध, सुविधा-शुल्क, राहजनी, लूट, डकैती आदि अपने विविध रूपों में देखी और पाई जाती है। अब ककड़ी चोर तो ककड़ी ही चुराएगा न! कोई बैंक में डाका तो नहीं डाल सकता! चोरों और चोरी का भी अपना-अपना स्तर है। तथाकथित बड़े लोग यदि ककड़ी चुराते पकड़े गए तो उनका हीन भाव उनकी नाक ही न काट डालेगा! अब बड़े लोगों की गिनती तो मैं करा नहीं सकता, क्योंकि उनसे सभी डरते हैं। मैं भी डरता हूँ। क्योंकि वे बड़े स्तर के चोर हैं और यदि वे मेरे यहां इस कार्य के लिए यदि पधार गए तो मेरे घर में कविताओं के कुछ कागजों के ढेर देखकर वापस रिक्त हस्त ही जाना पड़ेगा।

अखबारों में बड़ी-बड़ी चोरियों के चर्चे आम हैं। पर बड़े चोरों की नब्ज पर हाथ भी लगाने की हिम्मत भला किसकी हो सकती है? नस्तर की तो बात ही करना बेकार है। हां, इतना अवश्य है

कि जब बड़े से बड़े चोरों का बुरा वक्त आ जाता है तो नस्तर तो क्या बिस्तर ही बंध जाता है। पर क्या कीजिए यहां तो सारे के सारे चोर मौसोरे ‘बहन-भाई’ हैं। ये बहन-भाई का पावन रिश्ता क्या-क्या गुल खिलाएगा! देखते जाइए। सब देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं। और देखते रह जाएंगे और ‘चोर-चोरनी’ अपनी चोरी का पवित्र औचित्य चतुराई से सिद्ध कर ये गए! वो गए! हम सब किसी सुपरिणाम की प्रत्यासा में टापते रह जाएंगे। और चोर-चोर मौसोरे भाई के साथ-साथ एक और पवित्र मुहावरा हमारे हिंदी मुहावरा कोश की अभिवृद्धि कर देगा— चोर-चोरनी मौसोरे भाई-बहन। अब कौन किसकी पूँछ उठाए, जब इधर से उधर को देखा तो सब मादा ही गए पाए! करते रहिए विरोध! कौन सुनता गए नक्कारखाने में तूती की आवाज? जब देश-दुनिया के सारे कुओं में ही भांग के बोरे के बोरे घुले पड़े हों, तो बेहोश तो होना ही है। आज उसी बेहोशी का दौर चल रहा है और करोड़ों की चोरी खुलेआम हो चुकी है। पर यह कहावत भी कुछ गलत नहीं फरमाती कि ऊंट की चोरी निहुरे-निहुरे नहीं होती।

● डॉ. भगवत स्वरूप ‘शुभम’



For Any Medical &  
Pathology Equipments  
Contact Us

## D-10™ Hemoglobin Testing System For HbA<sub>1c</sub>, HbA<sub>2</sub> and HbF

**Flexible**  
to solve more testing needs

**Comprehensive**  
B-thalassemia and  
diabetes testing

**Easy**  
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

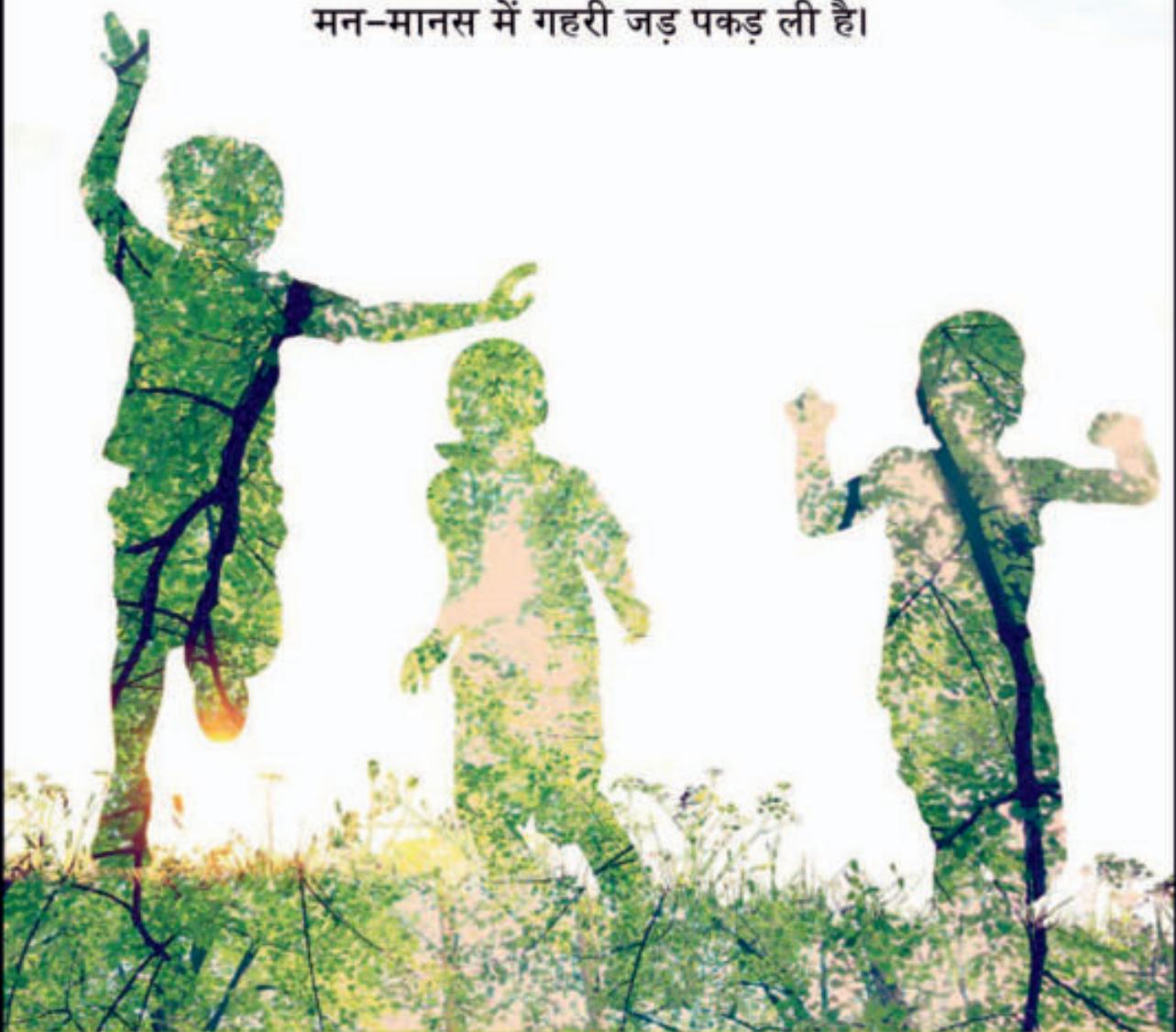
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA<sub>1c</sub> or HbA<sub>1c</sub>/FIA<sub>c</sub> testing using primary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps. With the D-10™ System, it's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

# SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

📍 C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023  
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 📩 Email : shbple@rediffmail.com  
📞 Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

# पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे  
मन-मानस में गहरी जड़ पकड़ ली है।



कोल इण्डिया लिमिटेड

विश्व की बृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था  
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही  
हमारा अस्तित्व है